सत्यमेव जयते

**असंशोधित**

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

## 07 मार्च, 2025

**बिहार विधान सभा सचिवालय,**

**पटना ।**

सप्तदश विधान सभा | शुक्रवार, तिथि 07 मार्च, 2025 ई0

चतुर्दश सत्र | 16 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय–11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया )

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाकपा–माले, सी0पी0आई0, सी0पी0एम0 के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये समय पर उठाइयेगा । समय पर अपनी बात उठाइयेगा, बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–05 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, नबीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : 1–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी जिलों में लोक अभियोजक के 37 पद एवं अपर लोक अभियोजक के 1656 पद हैं । अपर लोक अभियोजक के कुल पदों में से 838 अधिवक्ता संवर्ग तथा 818 अभियोजन सेवा संवर्ग से अनुमान्यता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी न्यायमंडलों में 37 लोक अभियोजक (10 अपर लोक अभियोजक प्रभारी लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत है) तथा कुल 722 अपर लोक अभियोजक कार्यरत हैं ।

सभी लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक की कार्यावधि समाप्त हो चुकी है परंतु नियुक्ति में होनेवाले प्रक्रियात्मक विलंब के कारण विधि विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नई नियुक्ति होने तक पूर्व से नियुक्त लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक अपने–अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे।

विधि विभागीय पत्रांक–7798 / जे0, दिनांक–19.11.2024 द्वारा इस संबंध में आदेश निर्गत किया गया है।

2– स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के व्यवहार न्यायालयों में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों का दिनांक–01.03.2025 तक कुल स्वीकृत बल 2022 है तथा इसके विरूद्ध कुल 1686 न्यायिक पदाधिकारी कार्यरत हैं एवं कुल 336 पद रिक्त हैं।

3– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के व्यवहार न्यायालय में दिनांक–31.01.2025 तक 05 वर्षों से अधिक लंबित वादों की संख्या 16,67,662 है ।

4– वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के व्यवहार न्यायालय में न्यायिक पदाधिकारियों के रिक्त पदों की कुल संख्या 336 है, जो कुल स्वीकृत बल का मात्र 16.61 प्रतिशत है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी कैडर में रिक्ति, होनेवाले प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, पद सृजन एवं मृत्यु इत्यादि के कारण उत्पन्न होता है तथा रिक्तियों को भरने हेतु की जानेवाली कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है। उक्त रिक्त पदों पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार नियुक्ति संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक के पदों की कार्यावधि समाप्ति के उपरांत नियुक्ति संबंधी वस्तुस्थिति निम्न है:–

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–18 तथा बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के नियम–5(2)(ख) के प्रावधानानुसार लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक के रिक्त पदों के संबंध में चयन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए उत्तर संलग्न है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय पर उठाइयेगा । कोई अनुमति नहीं है । पोस्टर हटाइये । नहीं—नहीं, समय पर उठाइयेगा आपकी बात सुनी जायेगी । बैठ जाइये, अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

प्रश्नोत्तर काल बाधित मत करिए, अपने स्थान पर जाइये । आप ही के गठबंधन के नेता का सवाल हो रहा है । आप उनको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं ? समय पर अपनी बात उठाइयेगा । अपने स्थान पर जाइये । सदन नियम से चलेगा, शोरगुल से नहीं चलेगा । अपने स्थान पर जाइये । बैठ जाइये अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने माना है कि न्यायिक पदाधिकारियों के 336 एवं अपर लोक अभियोजक के 934 पद रिक्त हैं तथा लोक अभियोजक की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है और कार्यवाहित रूप में कार्यरत हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सभी पद कितने वर्ष से रिक्त हैं और सरकार कबतक उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के रिक्त पदों के संबंध में चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । विभाग इस संदर्भ में कार्रवाई कर रहा है । जल्द ही इन रिक्तियों को हम भरने का काम करेंगे ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि कब से रिक्त पड़े हुए हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, रिक्त नहीं पड़ा हुआ है । पूर्व से जो कार्यरत हैं उन कार्यरत लोगों की कार्यावधि पूरी हो गयी है । कार्यावधि पूर्ण होने के बाद जबतक नई नियुक्ति नहीं होती है तबतक उनके कार्य करने का प्रावधान है । नई नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिए । महबूब साहब, शून्यकाल में सूचना आपने दी है तो अभी क्यों उठा रहे हैं ? उस समय उठाइयेगा । उस समय आपकी बात सुनी जायेगी । बैठिए, अपने स्थान पर जाइये ।

माननीय सदस्य, बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, मेरा दूसरा पूरक यह है वर्तमान में प्रति न्यायिक अधिकारी के 2323 मुकदमें सुनवाई के लिए रहते हैं । क्या सरकार न्यायिक हित में...

अध्यक्ष : विजय जी, एक मिनट ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्यों इस तरह करते हैं ? जब भी कोई घटना होती है उसकी खबर आती है और जिसको देखते हम उसी समय सबको कहते हैं किसी भी राज्य में, आप एक राज्य की बात कर रहे हैं । कहीं भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहां सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है और वहां के डी0एम0 से..

(व्यवधान)

अरे ! सुनिए । वह सब फालतू बातें हैं । बिना मतलब का, आपको क्या मालूम है ? एक–एक चीज पर तुरंत कह देते हैं कि आप लोग देख लें वहां पर क्या हुआ है । कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर ऐक्शन होना चाहिए । यह सब बात पहले ही दिन कहीं भी कुछ होता है तो हम कर देते हैं ।

(व्यवधान)

अब छोड़िए न, इन सब चीजों को लेकर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ? बेमतलब का समय आपलोग बर्बाद करते रहते हैं । इसलिए देखिए, यह सब कोई बात नहीं है । जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा । एक–एक तरह से सारी बातें, यह जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं कहीं पर कुछ होता है तो इमीडिएटली हम देखते ही हैं और उसी समय हम सबको कह देते हैं । इसलिए यह सब कुछ नहीं है और आपसे अब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए । सवाल पूछिए जवाब दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बैठ जाइये । सदन नेता ने कहा हम एक्शन ले रहे हैं तो अब क्या है । अब बैठ जाइये । वेल में कही हुई कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी । आप अपने स्थान पर जाईये । आपने शून्यकाल दिया है, शून्यकाल में अपनी बात उठाइये । अपने स्थान पर बैठिए ।

विजय जी, बोलिए । सत्येदव बाबू, बैठ जाइये । बोलिए विजय जी, अंतिम प्रश्न ।

(इस अवसर पर वेल से माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गये)

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, माननीय मंत्रीजी से हम जानना चाहते हैं कि इसमें समय–सीमा सदन को बताने का कि कब तक ये रिक्तियों को पूरा करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंडल पाण्डे, मंत्री : महोदय, हमने कहा कि ये सारी कार्रवाई विभाग में प्रक्रियाधीन है । शीघ्र ही इसको पूरा कर लेंगे । सरकार भी चाहती है कि लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति हम शीघ्रातिशीघ्र करें । हमने खंड–क के जवाब में स्पष्टता से कहा है कि जबतक नई नियुक्ति नहीं होती है तबतक पुराने लोगों को कार्य करने के लिए कहा गया है और वे कार्य कर रहे हैं लेकिन नई नियुक्ति करने के लिए विभाग संकल्पित है, बहुत शीघ्र हम इसको करेंगे ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है । यह दिवस सभी महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक सामानता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर प्रदान करता है । राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । हम सभी का यह दायित्व है कि नारी गरिमा, सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम सदैव तत्पर रहें । इस अवसर पर मैं सदन के सभी महिला सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं । साथ ही, राज्य की सभी महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

चूंकि कल महिला दिवस के दिन सदन की बैठक नहीं होगी, इसीलिए मैं आज तारांकित प्रश्नों की सूची में अपने महिला सदस्यों के प्रश्नों को प्राथमिकता

दे रहा हूं । आज के लिए कुल आठ महिला सदस्यों के प्रश्न, प्रश्न पुस्तिका में हैं । इनमें कुछ महिला सदस्यों के दो–दो प्रश्न हैं लेकिन उनमें से एक ही प्रश्न ले रहा हूं । सबसे पहले क्रमांक 431 पर अंकित माननीय सदस्या श्रीमती मीना कुमारी अपना प्रश्न पूछें ।

माननीय सदस्या मीना कुमारी जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–431 (श्रीमती मीना कुमारी, बाबूबरही)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, पूरक पूछिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पढ़ दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि खजौली प्रखंड अन्तर्गत चतरा गोबरौड़ा उत्तरी पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मरूकिया स्वीकृत है एवं किराये के मकान में संचालित है, जहाँ से प्रश्नगत ग्राम के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्त्ता, मधुबनी को पत्रांक– 203(10) दिनांक–04/03/2025 द्वारा निदेशित किया गया है। मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराये जाने पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्या, श्रीमती प्रतिमा कुमारी । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या–437 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी, राजापाकर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला के राजापाकर प्रखण्ड में स्थित ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 कॉलेज का भवन निर्माण कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा पूर्ण कराते हुए दिनांक–07.12.2020 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजापाकर को हस्तगत कराया गया।

वर्त्तमान में इस संस्थान में ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 101, जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 169 तथा पारामेडिकल पाठ्यक्रम में 150 छात्र/छात्राएँ आवासित हैं एवं पठन–पाठन कार्य कर रहे हैं।

इस भवन में लघु मरम्मति कार्य की आवश्यकता है। इसकी मरम्मति हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि कबतक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, प्राक्कलन तैयार होने के बाद तुरंत उसकी हम स्वीकृति दे देंगे । आज महिला दिवस है और आपकी आज जो भी मांग होगी उसको हम जरूर पूरा करेंगे ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : जी धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–450 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, शेरघाटी)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : गया जिलांतर्गत प्रखंड आमस के ग्राम पंचायत सावकला के ग्राम समशेरखाप नया भुई टोली भट्टा के पास लगभग 08 से 10 महादलित परिवार का नया बसावट है जो ग्राम समशेर खाप से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी के नजदीक है एवं किसी परिवार के के पास विद्युत संबंध नहीं होने के कारण विद्युत विपत्र निर्गत नहीं होता है । अभी तक उक्त स्थान पर विद्युत संबंध लेने हेतु किसी परिवार के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है ।

अतः उक्त स्थान पर नया विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु दिनांक–05.03.2025 को कैंप प्रस्तावित है । आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत संरचनाओं का निर्माण कर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उत्तर संलग्न है पूरक पूछिए ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, उत्तर आ गया है लेकिन वहां पर कैंप नहीं लगाया गया था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, पूरक पूछिए ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : इसीलिए वहां पर जांच करके कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ध्यान रखिएगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जांच करवा लेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मनोरमा देवी । पूरक पूछिए ।

माननीय मंत्री पर्यटन विभाग । प्रश्न संख्या 473 मनोरमा देवी जी का । थोड़ा क्रम बदल गया है । देख लीजिए, खोज लीजिए ।

(व्यवधान)

जी नहीं । चूंकि यह क्रम उलटकर चल रहा है न, आगे बढ़ गया है । फाईल तो लाते हैं क्रम से सजाकर तो थोड़ा तो खोजना पड़ेगा । वैसे भी महिलाओं का सम्मान करना है तो पुरूष थोड़ा धैर्य रखें, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा समझ लीजिए आप । अगर यहां घरवाले देख रहे होंगे और आप महिलाओं का विरोध कीजिएगा तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा ।

..क्रमशः.

टर्न–2/हेमन्त/07.03.2025

अध्यक्ष : ये महिला–पीड़ित लोग ज्यादा हल्ला कर रहे हैं आज ।

(व्यवधान)

मिल जायेगा, मिल जायेगा, हल्ला मत करिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–473 (श्रीमती मनोरमा देवी, बेलागंज)

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : सर, समय दिया जाय । अभी खोजकर मैं इसका जवाब दे देता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हर आदमी पहली बार नया ही मंत्री बनता है और आप लोग भी कई लोग हैं जो पहली बार माननीय सदस्य बनकर आये हैं ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । आप कहां बीच में टपक जाते हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : सर, उत्तर मिल गया है । अगर पूरक पूछें, तो मैं बताता हूं ।

अध्यक्ष : आप पहले उत्तर उनका पढ़ दीजिए । मनोरमा जी का उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक– 788 दिनांक– 05.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से विहित प्रपत्र में वर्णित स्थल के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

निश्चित रूप से जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–475 (श्रीमती रश्मि वर्मा, नरकटियागंज)

श्रीमती रश्मि वर्मा : सबसे पहले मैं महिला दिवस पर सभी को शुभकामना देती हूं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये रश्मि जी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मरीज को Final gasping की अवस्था में अस्पताल में लाया गया था, जिस समय मरीज को लाया गया था, उस समय एम्बुलेंस दूसरे मरीज को ले जाने के कारण तत्काल उपलब्ध नहीं थी। अन्यत्र जगह से एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उपलब्ध करायी गयी थी।

वस्तुस्थिति यह है कि अनुमण्डलीय अस्पताल, नरकटियागंज में कुल–03 एम्बुलेंस कार्यरत हैं। दो अतिरिक्त एम्बुलेंस संस्थान को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्त्तमान में कुल–05 एम्बुलेंस संस्थान में कार्यरत हैं।

उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, जिस कारणवश मरीज की मृत्यु हुई है, उन पदाधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर कुछ कार्रवाई की संभावना है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि जो कारण था वह Final gasping का था मलतब उल्टी सांस चलने की बीमारी उस मरीज को हुई थी । उस वक्त एंबुलेंस अस्पताल में नहीं थी । बाद में दूसरी एंबुलेंस उपलब्ध करायी गयी और माननीय

सदस्या ने जो एंबुलेंस बढ़ाने के संदर्भ में विषय उठाया है, वह भी हमने बढ़ा दिया है । अब पांच एंबुलेंस की व्यवस्था हमने उस अस्पताल में कर दी है ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, क्या वह सारी एंबुलेंस में सभी सुविधाएं हैं जिसमें डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, इसमें एक ALSA एंबुलेंस और चार BALSA एंबुलेंस हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–483 (श्रीमती गायत्री देवी, परिहार)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मंत्री जी उत्तर पढ़ देते तो अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । गायत्री देवी जी का उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत वैला पंचायत में पावर सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी पंचायत है । सरकार की योजना है कि सभी खेत में बिजली और बोरिंग लगा दिया जायेगा, अभी तक नहीं लगा है और परेशानी हो रही है । मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कब तक लगा दिया जायेगा कि खेतों में पानी चला जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कब तक लगा दिया जायेगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जल्द–से–जल्द इसको करवा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष जी, एक मिनट समय दिया जाय । आज तो महिला दिवस है, जो आप हम लोगों को समय दिये हैं इसके लिए पूरे देश की महिलाओं की तरफ से मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं और प्रणाम करती हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–486 (श्रीमती भागीरथी देवी, रामनगर)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–491 (श्रीमती रेखा देवी, मसौढ़ी)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पोस्टर नहीं दिखाइये, हटाइये पोस्टर । पोस्टर लीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या–426 (श्री अली अशरफ सिद्दिकी, नाथनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक योजना (Village Health Guide Scheme) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिवार कल्याण योजना के तहत सम्मिलित योजना थी। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अ0स0 पत्रांक–पी0 17019/3/2002–RHS दिनांक– 05.03.2002 द्वारा दिनांक–01.04.2002 के प्रभाव से उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना को समाप्त कर दिया गया है। तदालोक में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–746 (प0क0) दिनांक–26.07.2002 द्वारा ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक/स्वैच्छिक कार्यकर्ता (Village Health Guide) से कार्य नहीं लिए जाने का निदेश निर्गत किया जा चुका है।

वर्तमान में राज्य में कहीं भी स्वैच्छिक कार्यकर्ता कार्यरत नहीं है।

उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अध्यक्ष : पूछिये समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : पूछता हूं । अध्यक्ष महोदय, पूरक ही है । माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है उसमें कहा गया है कि योजना भारत सरकार द्वारा 2002 में समाप्त कर दी गयी थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये, आपस में बात नहीं करिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : इसलिए 2002 से इनकी सेवा समाप्त हो गयी । माननीय मंत्री के उत्तर को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे पास कागजात उपलब्ध है, माननीय मंत्री जी बतावें कि ये लोग 2017 तक कार्यरत थे या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में लिखा है कि वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक योजना (Village Health Guide Scheme) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिवार कल्याण योजना के तहत सम्मिलित योजना थी। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अ0स0 पत्रांक–पी0 17019/3/2002–RHS दिनांक–05.03.2002 द्वारा दिनांक–01.04.2002 के प्रभाव से उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना को समाप्त कर दिया गया है। तदालोक में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–746 (प0क0) दिनांक–26.07.2002 द्वारा ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक/स्वैच्छिक कार्यकर्ता (Village Health Guide) से कार्य नहीं लिए जाने का निदेश निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य में कहीं भी स्वैच्छिक कार्यकर्ता कार्यरत नहीं है। यह मैंने स्पष्ट कर दिया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह 20 वर्ष के बाद हटाया गया है । क्या यह बात सही है कि किसी की नियुक्ति करने के बाद उसको हटाने के लिए कोई पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने बोला कि पत्र 2002 में निर्गत किया जा चुका है । भारत सरकार का जो निर्णय हुआ उस निर्णय के आलोक में राज्य की सरकार ने वह पत्र निर्गत किया है और वर्तमान में कोई भी कार्यरत नहीं है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : 2017 तक वह कार्यरत है, 2002 में उनको हटाया गया है। तो निश्चित तौर पर जब 2002 में हटाया गया भारत सरकार के द्वारा और 2017 तक कार्यरत हैं। हमारा यह कहना है । हमारे पास पत्र भी उपलब्ध है । कहेंगे तो मंत्री जी को उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष : दे दीजिए । मंत्री जी दिखवा लेंगे उसको ।

श्री समीर कुमार महासेठ : क्या यह बात सही है कि इन लोगों की नियुक्ति तो की गयी, लेकिन सेवा से हटाने संबंधित कोई पत्र आज तक जारी नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : आपके पास जो पत्र है वह मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, 26.07.2002, पत्रांक–746, इसके द्वारा निर्देश निर्गत किया जा चुका है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : आपके जवाब में तो नहीं है ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : जवाब में ही तो है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर इतर में आपके पास कोई प्रश्न है, कागज है, तो दे दीजिए, मंत्री जी दिखवा लेंगे उसको ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया । अब बैठ जाइये । अगली बार उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

आपकी कौन व्यवस्था है ? बोलिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, जब प्रश्नकर्ता यह कहते हैं कि वह 2017 तक कार्यरत थे और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, इसको 2002 में ही खत्म कर दिया गया ।

अध्यक्ष : तो हमने जो कहा वह नहीं सुने आप ? हमने कहा कि अगर ऐसा पत्र आपके पास है, तो मंत्री जी को दे दीजिए, वह दिखवायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : जवाब में डिफरेंस है महोदय । उसकी जांच करवाइये ।

अध्यक्ष : वह देंगे तब न । आप बैठ जाइये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आजकल मोजर लगने का मौसम है और मौजर टपकते रहता है, तो सत्यदेव बाबू अपने भाई हैं, वह बीच–बीच में मौजर की तरह टपकते रहते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–427 (श्री प्रणव कुमार, मुंगेर)</u>

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है । हम चाहेंगे कि जवाब पढ़ दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रणव जी, यह ट्रांसफर हुआ है मंत्रिमंडल सचिवालय में, जवाब अगले हफ्ते आयेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–428 (श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, गोपालपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–429 (श्री नारायण प्रसाद, नौतन)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अग्नि पीड़ित श्री लालबाबू भगत को नगद, खाद्यान, बर्तन एवं वस्त्र तथा क्षतिग्रस्त झोपड़ी मद में कुल अनुमान्य राशि ₹20,000/–(बीस हजार) का भुगतान कर दिया गया है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, नारायण बाबू ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रश्न करने के बाद उसका मुआवजा तो मिल गया, लेकिन आवास के संबंध में भी लिखा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से भी उसको मकान दे दिया जाता तो फिर झोपड़ी बनाने की जरूरत नहीं थी । क्या सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन ।

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : महोदय, आवास ग्रामीण विकास विभाग से देने का प्रावधान है । हम लोगों के विभाग से आवास देने का प्रावधान नहीं है ।

टर्न–3/धिरेन्द्र/07.03.2025

तारांकित प्रश्न संख्या–430 (श्री अजय कुमार सिंह, जमालपुर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर हुआ है। अगले सप्ताह आयेगा ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–432 (श्री शकील अहमद खाँ, कदवा)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बलिया बलौन का संचालन वर्त्तमान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र बलिया बलौन (कदवा) के भवन में किया जा रहा है, जहाँ से आमजनों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं । उक्त भवन वर्त्तमान में नवनिर्माण योग्य नहीं है ।

भविष्य में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी को प्राधिकृत किया गया है । आप पूरक पूछिये ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, ऑनलाईन उत्तर आया है लेकिन इसमें मेरा पूरक यह है कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जगह की कमी है, जिसके कारण छः बेड का हॉस्पिटल नहीं हो रहा है तो क्या सरकार विचार करती है कि छः बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था वहाँ पर करें ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, पूरी अच्छी तरह से विचार कर हमने जवाब दिया है कि भविष्य में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण पर हम विचार करेंगे मैंने जवाब में लिखा है कि विचार किया जायेगा ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–433 (श्री पवन कुमार जायसवाल, ढाका)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–434 (श्री चेतन आनंद, शिवहर)</u>

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सरोजा सीताराम सदर अस्पताल, शिवहर में चिकित्सकों के 32 स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में 02 सर्जन सहित कुल 10 विशेषज्ञ चिकित्सक, 08 सामान्य चिकित्सक, 01 दन्त चिकित्सक एवं 02 आयुष चिकित्सक कार्यरत हैं । उक्त अस्पताल में मस्तिष्क तथा नस रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पद सृजित नहीं है ।

उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 एवं दन्त चिकित्सक के 808 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है । सामान्य चिकित्सा

पदाधिकारी एवं दन्त चिकित्सक के विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई अंतिम चरण में है । योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे छोटा जिला है, इसमें जल्द–से–जल्द करा दिया जाय तो बेहतर रहेगा ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, हम प्राथमिकता पर करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–435 (श्री मोहम्मद अनजार नईमी, बहादुरगंज)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत, बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछ प्रखण्ड में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द में 18 प्रकार की जाँच हो रही है।

संस्थान में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है अपितु सामान्य प्रसव करायी जाती है ।

अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा तथा सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति उपरान्त प्रारम्भ की जायेगी ।

विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) का पद–542, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक) का पद–988, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (रेडियोलॉजी) का पद–184 एवं अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की गई है । नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : नईमी साहब, पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, कब तक बहाली होगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, बहाली की प्रक्रिया चल रही है, विज्ञापन प्रकाशित हो गया है बी॰टी॰एस॰सी॰ के माध्यम से, अभी एक सप्ताह हुआ है और बी॰टी॰एस॰सी॰ के द्वारा चयन की पूरी प्रक्रिया की जाती है । मैं समझता हूँ कि अनुमानित लगभग दो महीने में यह प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या–436 (श्री अरूण सिंह, काराकाट)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0 एक्ट–1994 के आलोक में अल्ट्रासाउण्ड संचालन हेतु योग्यता स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ/पी0जी0 डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी/एम0डी इन पेडियाट्रिक चिकित्सक होना जरूरी है ।

विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) का पद–542, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (रेडियोलॉजी) का पद–184 एवं अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की गई है । नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

चिकित्सकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना उपरान्त अल्ट्रासाउण्ड की सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

3. उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव जी को प्राधिकृत किया गया है । पूरक पूछिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और बताया गया है कि रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल में अल्ट्रासाउंड के लिए योग्य स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ, रेडियोलॉजी....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बात नहीं कीजिये, आपकी आवाज आ रही है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, पेडियाट्रिक चिकित्सक होना जरूरी है । यह समझाने का प्रयास किया गया है और बहाली हो जायेगी....

अध्यक्ष : रामबली बाबू, एक मिनट । महिला सदस्य को इतनी छूट नहीं हो सकती है, मेरी बात समझिये, महिला–पुरुष एक–दूसरे के पूरक हैं, एक–दूसरे के विरोधी नहीं हैं तो दोनों के समन्वय से ही सृष्टि बनती है । हम और आप सभी उसी कारण से आये हैं इस पृथ्वी पर तो दोनों का समन्वय होना चाहिए न ।

बोलिये, रामबली बाबू ।

श्री रामबली सिंह यादव : जी, महोदय । रोहतास जिला का बिक्रमगंज अनुमंडल सबसे बड़ा अनुमंडल है और कहा गया था, प्रश्न था कि वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन के इंतजाम करने की बात थी । महोदय, उत्तर में कहा गया कि.....

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं । योग्य प्रसूति रोग विशेषज्ञ और अन्य चिकित्सक की आवश्यकता होती है तो बहाली होगी तब अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जायेगी, यह उत्तर में है । हम कहना चाहते हैं कि वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था 2005 के पहले 2002 में थी और इसके बाद उसको अन्यत्र हटा दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि चिकित्सक की बहाली होगी तब वहाँ लगा दिया जायेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार के रहते वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाएगी और होगी तो कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0 एक्ट के तहत ही अल्ट्रासाउंड का काम किया जाता है, उसकी अवहेलना कर हम किसी अस्पताल या किसी स्वास्थ्य संस्थान में अल्ट्रासाउंड का काम नहीं कर सकते हैं और हमने जवाब में बताया है कि उसके लिए हमको प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पी0जी0 डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी या एम0डी की जरूरत होती है तो इसकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, बहुत शीघ्र बहाली हो जाएगी । यह प्राथमिकता में हमारे विभाग में रहेगा और जैसे ही हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध होंगे, वहाँ पर उनको हम भेजकर इस काम को शुरू करवा देंगे ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, यही बात मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक डॉक्टर के साथ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था मिल जायेगी ?

अध्यक्ष : चिकित्सकों के बहाली की प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र होगा, वैसा कहा मंत्री जी ने।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, समय जानना चाहते हैं कि कब तक हो जायेगा ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, यह बी॰टी॰एस॰सी॰ के द्वारा होता है । बी॰टी॰एस॰सी॰ एक स्वायत्त संस्था है, मैं अनुमान करता हूँ, मैंने पूर्व के भी प्रश्न में कहा कि मैं अनुमान करता हूँ कि संभावित दो महीने में यह प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब कहाँ, शीघ्र बोल रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, महबूब भाई को ठीक ही बोला गया था कि आपका नाम कुछ और रहता तो सदन में और आनंद आता । आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उसका जवाब मैंने दे दिया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–438 (श्री राकेश कुमार रौशन, इस्लामपुर, नालन्दा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–439 (श्री अवध विहारी चौधरी, सिवान)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, सिवान में अधीक्षक सहित कुल स्वीकृत 81 पदों के विरुद्ध वर्त्तमान में 01 अधीक्षक, 06 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 17 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं 06 आयुष चिकित्सक कार्यरत हैं जिनके द्वारा मरीजों का उपचार ससमय किया जा रहा है ।

सदर अस्पताल सिवान में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएँ उपलब्ध हैं । मानक के अनुरूप बाह्य कक्ष में 268 के विरुद्ध 260, अन्तः कक्ष में 156 के विरुद्ध 140 एवं शल्य कक्ष हेतु 123 के विरुद्ध 110 दवाएँ उपलब्ध हैं । मानक के अनुरूप सदर अस्पताल, सिवान में आवश्यक चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध है, जिससे मरीजों का उपचार कराया जाता है ।

उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 एवं दन्त चिकित्सक के 808 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है । सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं दन्त चिकित्सक के विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई अंतिम चरण में है । योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : अवध विहारी बाबू, पूरक पूछिये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिवान जिला अस्पताल में मानक के मुताबिक 81 चिकित्सक होना चाहिए, आपने अपने जवाब में दिया है परन्तु अभी तक मात्र 30 चिकित्सक हैं, 51 चिकित्सक अभी भी सिवान जिला अस्पताल में नहीं है और इसके पूर्व भी मैंने

आपसे प्रश्न किया था कि सिवान जिला अस्पताल में भिन्न–भिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं रहने के कारण रोगियों को दिक्कत होती है और उपचार के लिए उन्हें गोरखपुर या पटना भेजने का काम सिवान जिला अस्पताल करता है । आपने कहा था कि प्रक्रियात्मक है और प्रक्रियात्मक कार्रवाई तकनीकी सेवा आयोग से हो जाने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सक दे दिये जायेंगे । मेरा प्रश्न भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से ही संबंधित है क्योंकि न्यूरो के डॉक्टर नहीं हैं, हार्ट के डॉक्टर नहीं हैं और वहाँ आपने डिप्यूटेशन किया है, हफ्ता में एक दिन न्यूरो जाता है और एक दिन हार्ट के डॉक्टर जाते हैं तो महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या जो चिकित्सकों की कमी है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को, स्वास्थ्य को देखते हुए सिवान जिला अस्पताल में आप कब तक विशेषज्ञ चिकित्सक और जो आवश्यकता जितने चिकित्सकों की होनी चाहिए, उसकी पूर्ति आप कब तक करेंगे?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों सिवान के हैं, मैं यह भी जानता हूँ कि आप दोनों हमेशा बात करते रहते हैं, मैं यह भी जानता हूँ कि दोनों एक–दूसरे की समस्या का समाधान करते रहते हैं । माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, श्री अवध विहारी चौधरी जी अभिभावक तुल्य हैं । मैंने अपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, पद की रिक्ति है और पद खाली है तभी तो उनके नियोजन के लिए बी॰टी॰एस॰सी॰ के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 3623 विशेषज्ञ चिकित्सकों का विज्ञापन अभी कुछ दिन पूर्व बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है । जहाँ तक माननीय सदस्य ने यह विषय कहा कि पूर्व में मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि विशेषज्ञ चिकित्सक सिवान में उपलब्ध करा दिया जायेगा । निश्चित रूप से यदि बीच के 16 महीनों में मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा होता तो अब तक वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक हो गए होते । श्री

अवध विहारी चौधरी जी, मैं 16 महीना नहीं था इसीलिए वह काम उस वक्त नहीं हो पाया, अब जब मैं बना हूँ तो फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दिया हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार सिवान सदर अस्पताल की सूरत हमने बदली है, नया अस्पताल भवन हमने आपको दिया है, इतना बढ़िया व्यवस्था अभी कुछ महीने पहले शुरू किया है, कुछ महीनों में ही ये विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहाँ चले जायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया ।

टर्न–4 / संगीता / 07.03.2025

श्री अवध विहारी चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुझे हमारे प्रश्नों के जवाब जो खंडवार दिये हैं, मैं आपके जवाब से अन्य खंडों के जो जवाब हैं उनसे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं इसलिए कि मैं सिवान हेडक्वॉर्टर से ही जीतता हूं और मेरे ही इलाके में सिवान जिला सदर हॉस्पिटल है । एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगे थे परन्तु वह ऑक्सीजन प्लांट आज भी बंद है और बाजार से गैस सिलेंडर खरीद करके लाया जाता है जिसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तक 12 लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए हैं तो इसका औचित्य क्या है? क्यों नहीं उस ऑक्सीजन प्लांट को इतने दिनों से 17 महीने हो गए, चालू नहीं किए गए और ये बाहर से ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खरीदने के पीछे औचित्य क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अवध विहारी चौधरी : और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सिवान के हैं प्रसन्नता है । आपने जवाब दिया प्रसन्नता है परन्तु आपके रहते हुए कोरोना काल में माननीय विधायकों के जो..

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री अवध विहारी चौधरी : ऐच्छिक कोष थे वो दे दिया गया आपलोगों ने दिया मैंने भी दिया, परन्तु आपने सजगता दिखाई लेकिन वह ऑक्सीजन प्लांट क्या बात है कि इतने दिनों से बंद है...

अध्यक्ष : जवाब देने दीजिए न अवध विहारी जी ।

श्री अवध विहारी चौधरी : और वह बन नहीं रहा है और वहां पर जी0एन0एम0 की भी कमी है जिसके चलते प्रसव में भी दिक्कत होती है । इन तमाम चीजों के बारे में मैं कहूंगा कि यह अलग से ऑक्सीजन प्लांट नहीं चालू करके बाहर से ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने का औचित्य क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, समय–समय पर विभाग के द्वारा जहां भी ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगे हैं उन सभी ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांटों को चलाकर उसकी जांच की जाती है । अभी माननीय अवध विहारी चौधरी जी ने जिस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है, एक महीना पूर्व ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चाहे वह अनुमंडल अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो, जहां पर ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगे हैं उसका ट्रायल हमने करवाया था लगभग 30 जगहों पर उसमें कठिनाई, तकनीकी कठिनाई आयी थी, उस संदर्भ में विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है लेकिन अधिकतर जगहों पर यदि वह प्रश्न रहता तो मैं पूरी सूची लेकर आ जाता । अधिकतर जगहों पर ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट चल रहा है, काम कर रहा है । सिवान के संदर्भ में विशेष तौर पर जो माननीय सदस्य ने बताया है मैं उसको भी दिखवा लूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बीच में क्यों बोल रहे हैं । ये दोनों बात करके आए हैं । ये सवाल करेंगे और ये जवाब देंगे, दोनों का तय है पहले से । बैठिए न आप ।

(व्यवधान)

जहानाबाद की बात मत करिए अभी, दोनों की बात सुनिए न ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय...

अध्यक्ष : हां, बोलिए ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है..

अध्यक्ष : ठीक है, अंतिम प्रश्न पूछिए ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि सिवान जिला सदर अस्पताल में जो–जो समस्या है रोगियों के इलाज में खंडवार मैंने

आपसे प्रश्न किया है आपने जवाब दिया । क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों के वहां पर प्रतिनियुक्ति–पदस्थापन और ऑक्सीजन प्लांट कितने दिनों में चालू करा देंगे, यही आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, नए चिकित्सकों के पदस्थापन के संदर्भ मैं मैंने बताया कि बी0टी0एस0सी0 एक स्वायत्त संस्था है । बी0टी0एस0सी0 परीक्षा लेता है, बी0टी0एस0सी0 परिणाम प्रकाशित करता है और उनकी अपनी पूरी प्रक्रिया जब पूर्ण होकर हमें परिणाम मिलती है फिर उसके बाद हम उन चिकित्सकों की नियुक्ति जिन अस्पतालों में आवश्यकता होती है उसके अनुरूप करते हैं तो परिणाम मिलने के बाद निश्चित रूप से अवध विहारी जी और मेरा भी जिला है तो विशेष चिन्ता रहती ही रहती है और आपने ठीक कहा हम दोनों समय–समय पर समस्याओं के निदान का प्रयास भी करते रहते हैं तो इस काम को हम करेंगे । ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट को अगले 15 दिनों के अंदर मैं उसको ट्रायल करवाकर जांच करवा दूंगा ।

अध्यक्ष : श्री कुमार शैलेन्द्र ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–440 (श्री कुमार शैलेन्द्र, बिहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए पहुॅच पथ एवं मिट्टी भराई हेतु BMSICL को प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप क्यों, अच्छा वे भी सिवान वाले ही हैं । सिवान वाले ही हैं वे भी क्या, ये आपलोग क्यों बतियाते रहते हैं और फिर यहां पर समय बर्बाद करते हैं हमलोगों का ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, समय बर्बाद करते हैं खाली सत्यदेव बाबू ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी बोलिए । बोलिए ।

(व्यवधान)

आप बैठिए, बैठ जाइए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : सत्यदेव बाबू दूसरों का भी प्रश्न देखिएगा न, बीच–बीच में टपक जाते हैं आप । बैठिए सत्यदेव बाबू, बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

शांत रहिए, शांति बनाए रखिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दिया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : है न, संबंध तो आपसे भी है । भूल गए आप, आपके घर गए थे खाना खाने के लिए, सब बात कितना याद रखें । बोलिए, शैलेन्द्र जी आप बोलिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, बोलेंगे सुनेंगे मंत्री महोदय तब न...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम सुन रहे हैं आप बोलिए । सब सुन रहे हैं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दिया है। प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए पहुंच पथ एवं मिट्टी भराई हेतु BMSICL को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही है महोदय । ये स्वास्थ्य उपकेंद्र 10 वर्ष पहले बन चुका है, 10 वर्ष हो गया है और एकदम स्पष्ट जवाब चाहते हैं महोदय कि आखिर 10 वर्ष तक इस स्वास्थ्य उपकेन्द्र में जाने के लिए मरीजों

को अभी तक क्यों नहीं बनाया गया । दूसरा, लगातार बढ़ाते हैं महोदय कि हम चाहते हैं कि ये प्राक्कलन हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये बना देंगे ये जवाब दें महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, हमारा सोच और विचार बहुत स्पष्ट है कि हमको उस सड़क का निर्माण कराना है तभी तो BMSICL को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिए हैं और जब कोई निर्माण कराना होता है तो प्राक्कलन से ही काम शुरू होता है और मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर प्राक्कलन तैयार करके उसके निविदा की कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री अमरजीत कुशवाहा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : बहुत–बहुत धन्यवाद, महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–441 (श्री अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैरवा में वर्त्तमान में 01 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डा0 प्रकाश कुमार तथा 03 ए0एन0एम0 (श्रीमती कमलावती कुमारी, श्रीमती रासमनी देवी एवं श्रीमती निर्मला पाण्डेय) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उक्त केन्द्र के अन्तर्गत संचालित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित 04 चिकित्सकों से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैरवा में चिकित्सीय कार्य लिया जाता है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पद सृजित नहीं होता है।

रेफरल अस्पताल, मैरवा में वर्त्तमान में 02 जी0एन0एम0 (सुश्री प्रियंका कुमारी एवं रूपा कुमारी) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 01 संविदा जी0एन0एम0 श्री बलराम प्रसाद भी कार्यरत हैं। राज्य के रेफरल अस्पतालों में नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पद सृजित नहीं होता है।

रेफरल अस्पताल, मैरवा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैरवा एक ही भवन में संचालित है। संयुक्त रूप से रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों एवं

पारामेडिकल कर्मियों द्वारा ईलाज हेतु आने वाले मरीजों को आवश्यक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 एवं दन्त चिकित्सक के 808, जी0एन0एम0 के 7903 एवं ड्रेसर के 3326 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। शेष पदों के विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए अमरजीत जी ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : पूरक पूछता हूं महोदय । महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि मैरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्तमान में एक सामान्य चिकित्सक डा0 प्रकाश कुमार तथा 03 ए0एन0एम0 कार्यरत हैं । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 8 का जगह है मैरवा में, मैरवा में रेफरल अस्पताल और प्राथमिक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र दोनों एक ही जगह पर संचालित है, एक ही बिल्डिंग में चलता है और इसमें 8 के विरूद्ध मात्र एक चिकित्सक वहां कार्यरत है जो मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है और मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय, जो अतिरिक्त 4 स्वास्थ्य...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : पूछता हूं महोदय तो 4 केन्द्रों से आकर जो डॉक्टर रहते हैं उसमें डॉ0 प्रकाश का जो जिक्र हुआ है तो डॉ0 प्रकाश भी आंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर हैं जो प्रभार के रूप में हैं...

अध्यक्ष : क्या पूछ रहे हैं आप, बोलिए न ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 8 के विरूद्ध कम से कम 4 चिकित्सक भी स्थायी रूप से वहां देना चाहते हैं ? दूसरी बात कि डॉ0 प्रकाश जो आंदर के डॉक्टर हैं केवल प्रभार में हैं तो क्या उनको स्थायी रूप से वहां प्रभार देना चाहते हैं पहला पूरक है महोदय...

अध्यक्ष : आपका 2 पूरक हुआ । माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : नहीं, एक ही के साथ है महोदय...

अध्यक्ष : आपका 2 पूरक हो गया । बैठिए, बैठिए । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, जवाब में मैंने स्पष्टता से बताया कि एक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी वहां हैं और 4 अन्य जगहों से चिकित्सकों को भी वहां पर चिकित्सकीय कार्य के लिए लगाया गया है तो कुल मिलाकर इस जगह पर 5 चिकित्सकों की सेवा दी जा रही है । माननीय सदस्य ने यह जिज्ञासा किया कि परमानेंट नियुक्ति वहां कब हो जाएगी, तो जैसे ही बी0टी0एस0सी0 से हमारा रिजल्ट आ जाएगा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों का, हम उनकी नियुक्ति कर देंगे और माननीय सदस्य तो गवाह हैं अभी मेरे साथ कई कार्यक्रमों में रहे हैं...

अध्यक्ष : हम समझ रहे हैं माननीय मंत्री जी...

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : हमलोग मिलजुल कर काम किए हैं, और वहां तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे सरकार का...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, हम समझ रहे हैं कि सिवान के चक्कर में ...

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, मैंने उसी में...

अध्यक्ष : दोनों बतियाते रहते हैं हमलोग खाली सिवान के चक्कर में घेराए हुए हैं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, उसी में एक प्रश्न किया है कि आंदर के जो प्रभारी हैं वहां उनको स्थायी कर दिया जाय और दूसरा मेरा जो पूरक है महोदय कि वहां ड्रेसर लगभग 2 साल से नहीं है और ड्रेसर नहीं होने की वजह से चूंकि मैरवा सीमावर्ती इलाका है...

टर्न–5/सुरज/07.03.2025

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, अमरजीत जी ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, ड्रेसर की या तो नियुक्ति की जाए नहीं तो पुराने ड्रेसर जो हैं उनका कार्य विस्तार करके उनको रखना चाहता हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ड्रेसर के बारे में माननीय सदस्य को बता दीजिये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, ड्रेसर के पद की अधियाचना बी0टी0एस0सी0 को भेजी गयी है और मैं समझता हूं कि उसका भी विज्ञापन बहुत शीघ्र प्रकाशित हो जायेगा और उसकी भी नियुक्ति की कार्रवाई भी पूर्ण हो जायेगी और वहां ड्रेसर भेजा

जायेगा । जो चिकित्सक को परमानेंट अंदर से करने के लिये उन्होंने प्रश्न पूछा है मैं उसको एक बार विभाग में देख लेता हूं, चूंकि सभी प्रखंडों में सेवा देना आवश्यक है फिर भी मैं उसको देख लेता हूं ।

तारांकित प्रश्न सं0–442, श्री जय प्रकाश यादव (नरपतगंज)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (लिखित उत्तर) महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज विधान सभा के मानिकपुर पंचायत स्थित वार्ड सं0–12, महतो टोला में जर्जर तार को सुव्यवस्थित कर लिया गया है । 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफॉर्मर पर अत्यधिक लोड के कारण उक्त ट्रांसफॉर्मर को 100 के0वी0ए क्षमता के ट्रांसफॉर्मर से बदलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 15 मार्च 2025 है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये जय प्रकाश जी ।

श्री जय प्रकाश यादव : पूरक पूछ रहे हैं महोदय । माननीय मंत्री महोदय ने तार और ट्रांसफॉर्मर बदलने के लिये विस्तृत में जवाब दिया है, जो संतोषप्रद है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

तारांकित प्रश्न सं0–443, श्री प्रमोद कुमार (मोतिहारी)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (लिखित उत्तर) श्री रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी निजी प्रक्षेत्र का कॉलेज एवं अस्पताल है एवं निजी प्रक्षेत्र के कॉलेज खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा मात्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। निजी कॉलेज अस्पताल पर राज्य सरकार का सीधा एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष निजी कॉलेजों के सरकारीकरण का मामला विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार बहुत काम करना चाहती है । रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मोतिहारी में 20 वर्षों से बंद है तो कब सरकार विचार रखती है और कब चालू कराना चाहती है ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि वह सरकारी महाविद्यालय और अस्पताल नहीं है । रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण निजी प्रक्षेत्र का कॉलेज और अस्पताल है, वह सरकारी नहीं है । निजी प्रक्षेत्र के कॉलेज खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा मात्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। निजी कॉलेज अस्पताल पर राज्य सरकार का सीधा एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष निजी कॉलेजों के सरकारीकरण का मामला विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : प्राईवेट कॉलेज है माननीय सदस्य ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, अभी बजट में आया है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी कि मेडिकल कॉलेज पी0पी0पी0 मॉडल पर खोलेंगे, सरकार खोलेगी । तो उसके तहत आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि प्राथमिकता में इसको रखें और भविष्य में उसको खोलने का प्रयास कराएं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपका आग्रह सुन लिया ।

तारांकित प्रश्न सं0–444, श्री गुंजेशवर साह (महिषी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री गुंजेश्वर साह : महोदय उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : उत्तर पढ़ दीजिये मंत्री जी ।

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है।

पर्यटन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा से उक्त स्थल के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक– 202 दिनांक– 28.02.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, किन्तु भूमि से संबंधित सूचनाएँ अप्राप्त थी ।

फिर भी विभाग इतना सिंसियर है कि पुनः विभागीय पत्रांक– 735 दिनांक– 03.03.2025 द्वारा वर्णित स्थल के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मैं माननीय सदस्य से आग्रह भी करूंगा कि यह जो प्रपत्र भेजा गया है जिलाधिकारी को उनसे भी बात कर लें और जैसे ही हमलोगों को भूमि से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होंगे निश्चित रूप से

सरकार शादी मण्डप बनाने का विचार रखती है और नियमानुसार इस पर कार्रवाई करेगी ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, जमीन वहां उपलब्ध है फिर भी माननीय मंत्री जी बोले हैं तो हमलोग उसको दिखवाकर जल्दी भिजवा देते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–445, श्री विजय कुमार (शेखपुरा)</u>

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि मनियण्डा में स्थित ध्वस्त भवन से संबंधित कोई अभिलेख/अधिसूचना स्थानीय कार्यालय के पास नहीं है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रखण्ड स्तर पर प्रावधानित होता है न कि पंचायत स्तर पर। शेखपुरा सदर प्रखण्ड के कैथवाँ पंचायत को स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं चिकित्सीय सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखपुरा सदर से दी जा रही है। इसके अलावा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, कैथवाँ का भवन भी निर्माणाधीन है। मनियण्डा से 05 कि0मी0 की दूरी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वर्मा भी संचालित है।

उक्त के आलोक में प्रश्नगत स्थल पर अलग से कोई स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : पूरक है महोदय । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि विगत 50 वर्षों से शेखपुरा जिला के ग्राम मनियण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन हो रहा था यदि हाँ तो उक्त पी0एच0सी0 जर्जर भवन को ध्वस्त कर उक्त भूमि पर एक पी0एच0सी0 या सी0एच0सी भवन का निर्माण कराते हुये चिकित्सा सुविधा बहाल कराने हेतु सरकार विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, जवाब में मैंने लिखा है कि वस्तुस्थिति यह है कि मनियण्डा में स्थित ध्वस्त भवन से संबंधित कोई भी अभिलेख/अधिसूचना स्थानीय कार्यालय के पास नहीं है । साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रखण्ड स्तर पर प्रावधानित होता है न कि पंचायत स्तर पर ।

प्रश्न जो किया गया है कि पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तब तो यह होता ही नहीं है ।

शेखपुरा सदर प्रखण्ड के कैथवाँ पंचायत को स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं चिकित्सीय सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखपुरा सदर से दी जा रही है। इसके अलावा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, कैथवाँ का भवन भी निर्माणाधीन है । मनियण्डा से 05 कि0मी0 की दूरी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वर्मा भी संचालित है ।

उक्त के आलोक में प्रश्नगत स्थल पर अलग से कोई स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, माननीय मंत्री जी को लिखित रूप से 31.01.2025 को सूचना माननीय विधायक जी के द्वारा दी गयी थी और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है । या तो माननीय मंत्री जी के विभाग के पदाधिकारी इनको गलत जवाब दे रहे हैं । 50 वर्षों से यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा था मनियण्डा में...

अध्यक्ष : आप बैठिये, हम बताते हैं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अगर वहां पर जर्जर भवन है...

अध्यक्ष : आप बैठिये न, हम बताते हैं आपको ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : मेरे शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया । मैंने अभिलेख/अधिसूचना की बात की है । कोई भी अभिलेख या अधिसूचना नहीं है । मैंने पत्र की बात नहीं की है ।

अध्यक्ष : आपको भी हम जानकारी देते हैं मंत्री जी, बैठिये ।

एक बार वर्ल्ड बैंक की सहायता से कुछ पंचायतों में स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये थे लेकिन बाद में वह सरकार के अधीन नहीं आये । पंचायतों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होता है, यह स्पष्ट है । आप भी जानते हैं मंत्री जी और आप भी जानते हैं माननीय सदस्य, आपको भी साढ़े चार साल हो गया है । प्रखंडों में होता है । हो सकता है कि वह उस योजना वाला होगा तो लोग कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । लेकिन पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होता है इसलिये कोई अभिलेख सरकार के पास नहीं होता है । सरकार से हम

जरूर आग्रह करेंगे कि अगर उस प्रकार का कोई अस्पताल था जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से बना था क्योंकि मैं जानता हूं उस विषय को...

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय...

अध्यक्ष : बैठिये न, आप सुनते भी नहीं हैं । मैं जानता हूं उस विषय को क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पंचायत में भी एक बन गया था और यह सवाल मुझसे किया गया था तो मैंने उसकी तहकीकात की थी । इसलिये मैं बता रहा हूं कि वह हो सकता है लेकिन उसका इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं होता है । आप उसका निर्माण करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं इसकी आप एक बार मंत्री जी समीक्षा कर लीजिये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : ठीक है । मैंने जवाब में माननीय सदस्य...

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय...

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : एक मिनट माननीय सदस्य । महोदय, पंचायत का नाम कैथवाँ है और कैथवाँ पंचायत में ऑलरेडी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माणाधीन है, उसी पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहा है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, सबसे बड़ा चीज है कि तब माइंड में बैठ जाता है लोगों के कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से चल रहा था...

अध्यक्ष : माइंड में बैठने से नहीं न होगा ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, एक मिनट सुन लिया जाए । जब वहां पर अगर कोई जर्जर भवन हो जाता है तो कल होकर के मीडिया के साथी जाते हैं और कैमरा चमका–चमका कर दिखाते हैं कि माननीय विधायक जी क्या काम किये, देखिये यह स्वास्थ्य विभाग का...

अध्यक्ष : फिर भाषण दे रहे हैं...

श्री मुकेश कुमार रौशन : इस तरीके का महोदय, तो सवाल का जवाब उस समय जनप्रतिनिधि को देना पड़ता है । या तो उसको ध्वस्त करा दिया जाए और नहीं तो वहां पर एडिशनल पी0एच0सी0 या सी0एच0सी0 का निर्माण करा दिया जाए...

अध्यक्ष : बैठिये । मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है, वह दिखवायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–446, श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (दरौंदा)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–1817(2) दिनांक–27.12.2024 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौंदा, सिवान में 01 महिला चिकित्सा पदाधिकारी डा० नेहा कुमारी की पदस्थापना की गई है। वर्त्तमान में डा० नेहा कुमारी दिनांक–01.03.2025 से मातृत्व अवकाश पर चली गई है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करसौत, दरौंदा में पदस्थापित महिला आयुष चिकित्सक डा० रजिया सुल्ताना द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौंदा में महिला मरीजों के उपचार का काम लिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) के 542 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह : महोदय, उत्तर मिला है और मंत्री जी से अलग से भी बैठकर बात हुआ है, संतुष्ट हैं । आसन के माध्यम से हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : आज हम पड़ गये हैं सीवान के चक्कर में । आज पूरा सदन सीवान के चक्कर में पड़ा हुआ है । अवध बिहारी बाबू क्या छेड़ दिये सीवान का कि सिर्फ सीवान का ही क्वेश्चन हो रहा है । और कुछ पूछना है, पूरक पूछने वाले हैं क्या ?

श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह : महोदय, मंत्री जी को हम आसन के माध्यम से धन्यवाद देते हैं । बात हो गया है अलग से, उत्तर से हम संतुष्ट हैं ।

अध्यक्ष : वैसे यह इस बात का भी प्रतीक है कि माननीय मंत्री बिहार के मंत्री हैं लेकिन यह अच्छी बात है कि पूरे बिहार की अच्छी चिंता करने के साथ–साथ अपने गृह जिला की भी भरपूर चिंता कर रहे हैं, खराब बात नहीं है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–447, श्री छत्रपति यादव (खगड़िया)</u>

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मथार का भवन निर्माण योग्य है एवं इसके लिए प्राक्कलन की माँग निगम (BMSICL) से की गयी है। वर्त्तमान में यहाँ पदस्थापित 03 ए0एन0एम0 एवं 01 सी0एच0ओ0 के द्वारा टीकाकरण, प्रारंभिक प्रसव पूर्व जाँच एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधायें ग्रामीणों को

उपलब्ध करायी जा रही है। चिकित्सकों का यहाँ पद स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, मंत्री जी से जवाब प्राप्त हुआ है लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, खगड़िया जिला विधान सभा के अंतर्गत रहीमपुर पंचायत में मथार क्षेत्र है और लगातार 4 साल से स्वास्थ्य विभाग से हम मांग करते आये हैं लेकिन हर बार जवाब वही आता है और आपको जानकारी दे देते हैं कि मथार दियरा से खगड़िया की दूरी 10–15 किलोमीटर पड़ता है और सदर अस्पताल की स्थिति भी यह है कि 52 पद है वहां लेकिन मात्र 13 डॉक्टर स्वीकृत है । इस बीच में हमारे जो मरीज आते–जाते हैं, उनको रेफर भागलपुर या अन्य कहीं कर दिया जाता है...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री छत्रपति यादव : हम यह जानना चाहते हैं कि...

अध्यक्ष : जानना चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं ?

श्री छत्रपति यादव : पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी का जवाब यह आया है कि हमने बी0एम0एस0आई0सी0एल0 को प्राक्कलन के लिये मांग किये हैं । यहे कितने दिनों में प्राक्कलन आ जायेगा और कितने दिनों में इसकी निविदा हो जायेगी ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, इसके बाद दूसरा पूरक भी है ।

अध्यक्ष : ठीक है, एक ही बार तीनों पूरक पूछ लीजिये ।

श्री छत्रपति यादव : मंत्री जी, इसमें दूसरी बात लिखते हैं कि चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं होने के कारण यहां प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सकों के पद कब तक स्वीकृत होंगे ? 70 साल हो गया देश की आजादी का । वह दियरा क्षेत्र है, एकदम अत्यंत पिछड़ा, गरीब, दलित बस्ती है । 10–15 हजार की आबादी है । यह कब तक पद स्वीकृत हो जायेगा और डॉक्टर उपलब्ध हो जायेंगे ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, जवाब मेरा बहुत ही सकारात्मक है । स्वास्थ्य उप केन्द्र मथार का भवन निर्माण योग्य है यह हम मान रहे हैं । हमको बनाना है इसलिये प्राक्कलन के लिये हमने अपनी एजेंसी को कहा है और यह पूरा सदन जानता है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य उप केन्द्र पर चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होती है । वहां पर सी0एच0ओ0 और ए0एन0एम0 की नियुक्ति होती है और वहां पर सी0एच0ओ0 वर्तमान में एक हैं और तीन ए0एन0एम0 हैं । तो जिसकी नियुक्ति उस केन्द्र पर होनी चाहिये, उनकी नियुक्ति वहां की गयी है । तो जिसका प्रावधान ही नहीं है वह कैसे कर सकते हैं ।

टर्न–6 / राहुल / 07.03.2025

अध्यक्ष : श्री कुंदन कुमार ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष जी, एक मिनट...

अध्यक्ष : हो गया अब ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष जी, एक मिनट । वह प्रावधान नहीं है...

अध्यक्ष : अंतिम प्रश्न है आपका ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष जी, सुना जाय । आप गार्जियन हैं, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं...

अध्यक्ष : इसीलिए तो कह रहे हैं पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : मान लीजिये हमारी उम्र 50 साल हो गयी है, 50 साल से कोई प्रावधान नहीं हुआ तो क्या 50 साल बाद होगा ? गरीब लोगों के लिए सरकार को प्रावधान करना पड़ेगा...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, पूरक यह है कि जो सी0एच0ओ0 की बात किये हैं वहां कोई डॉक्टर नहीं जाते हैं, नर्स उपलब्ध नहीं रहती हैं, खगड़िया जिले के हर अस्पताल में यही स्थिति है । हमेशा सरकारी जवाब आता है...

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री छत्रपति यादव : हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहां गरीबों के लिए एक पद सृजित किया गया ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि जो व्यवस्था पूरे देश में नहीं है तो बिहार में अलग से कोई व्यवस्था थोड़े होगी, पूरे देश की यह व्यवस्था है । स्वास्थ्य उपकेन्द्र, स्वास्थ्य सेवा की सबसे छोटी इकाई होती है । यह बिहार में विगत वर्षों में अब सी0एच0ओ0 दिखायी पड़ने लगा, अब ए0एन0एम0 दिखायी पड़ने लगा, नहीं तो पहले इन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की क्या स्थिति होती थी सभी माननीय सदस्य जानते हैं । इसलिए व्यवस्था को बेहतर किया गया है लेकिन जो प्रावधान है उसी में न काम करेंगे । माननीय सदस्य का कहना है कि प्रावधान से अलग हटकर कुछ व्यवस्था कर दें तो वह कैसे कर पायेंगे ।

अध्यक्ष : वह नहीं हो सकता है । श्री कुंदन कुमार ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, हटकर नहीं बोल रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सरकार को विचार करना चाहिए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–448 (श्री कुंदन कुमार, बेगूसराय)</u>

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (लिखित उत्तर) महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मोहनपुर भूमि के अभाव में प्राथमिक विद्यालय, किल्ली के परिसर में संचालित है। साथ ही, नवसृजित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, किल्ली के भवन का निर्माण भूमि अनुपलब्ध होने के कारण अब तक नहीं किया जा सका है ।

उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्त्ता, बेगूसराय को पत्रांक–240(10) दिनांक 05/03/2025 द्वारा निदेशित किया गया है । मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भविष्य में नये निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं । मेरा सवाल मोहनपुर पंचायत के मोहनपुर एवं किल्ली उप स्वास्थ्य केन्द्र से जुड़ा हुआ था, जवाब आया है कि भूमि उपलब्ध नहीं है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि वहां पर भूमि भी उपलब्ध है और सवाल था जर्जर भवन से संबंधित । दोनों जगह स्वास्थ्य उपकेन्द्र है और भवन जर्जर है तो क्या माननीय मंत्री जी

जर्जर भवन को तुड़वाकर वहीं पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनवाना चाहते हैं या माननीय मंत्री जी वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं वे दोबारा जांच करवाना चाहते हैं क्योंकि मेरी जानकारी से दोनों जगह जमीन उपलब्ध है ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैं दिखवा लेता हूं । जमीन उपलब्ध होगी तो निर्माण करा दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0–449 (श्री राहुल तिवारी, शाहपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (लिखित उत्तर) स्वीकारात्मक । स्व० धर्मेन्द्र यादव, पिता–कन्हैया यादव, ग्राम– जवईनिया, पो०–थाना–शाहपुर दामोदरपुर, (बहोरनपुर ओ० पी०), प्रखण्ड–शाहपुर, जिला–भोजपुर के आश्रित पिता श्री कन्हैया यादव को विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जगदीशपुर के कार्यालय आदेश संख्या–13, ज्ञापांक–253 दिनांक– 03.03.25 द्वारा नियमानुसार अनुदान राशि रू0 4,00,000/– (चार लाख) मात्र का भुगतान करने का आदेश निर्गत किया गया तथा उक्त स्वीकृत आदेश के आलोक में चेक संख्या–008767, दिनांक–03.03.2025 के द्वारा भुगतान किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं वह मुआवजे की राशि मिल गयी है लेकिन साथ ही साथ मेरा पूरक यह है कि क्या सरकार मुआवजा राशि देने में कोई समय–सीमा निर्धारित करना चाहती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कुछ प्रक्रिया है उसी के कारण कुछ विलंब होता है। जल्दी से जल्दी करने की कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : जल्दी किया जायेगा ।

श्री राहुल तिवारी : बिल्कुल सही है । यह पांचवे साल के बाद चेक मिला है । वर्ष 2021 का यह मामला है । कोई भी प्रक्रिया में चार साल, पांच साल इस पर ध्यान दिया जाय और समय–सीमा इसमें निर्धारित की जाय ।

अध्यक्ष : आपकी बात पर जरूर ध्यान देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–451 (श्री संजीव कुमार, परबत्ता)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–452 (मो0 सैयद रूकनुद्दीन अहमद, बैसी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–453 (श्री पवन कुमार यादव, कहलगांव)

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि एस०डी०आर०एफ० में उपलब्ध मानव बल के आलोक में सम्प्रति राज्य के कुल 20 जिलों में एस०डी०आर०एफ० की एक–एक टीम को स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित गति से राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके । उक्त 20 जिलों में भागलपुर जिला भी शामिल है । जिलों में प्रतिनियुक्त टीमें संबंधित जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करती है । साथ ही, जिला में प्रतिनियुक्त एस०डी०आर०एफ० टीम को जिला के अंदर किस स्थान पर प्रतिनियुक्त किया जाना है, इसका निर्णय भी संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा लिया जाता है । जिला प्रशासन, भागलपुर के द्वारा भागलपुर जिला में प्रतिनियुक्त एस०डी०आर०एफ० टीम को दो सब–टीमों में विभक्त कर दो प्रखण्डों यथा–सबौर एवं सुल्तानगंज में प्रतिनियुक्त किया गया है । जिला के किसी भाग में आपदा आने की स्थिति में उक्त टीमों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु भेजा जाता है । अतएव, वर्तमान में विभाग के स्तर पर भागलपुर जिला में अतिरिक्त टीम को प्रतिनियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है लेकिन उत्तर में कहलगांव, सुल्तानगंज एवं सबौर में एस0डी0आर0एफ0 टीम स्थायी रूप से रखी गयी है । सर्वाधित भीड़ एवं दुर्घटना का क्षेत्र कहलगांव एवं बटेश्वरस्थान है । ऐसे में एस0डी0आर0एफ0 की टीम को सबौर और सुल्तानगंज में रखने का कोई औचित्य नहीं है । क्या सरकार, जिलाधिकारी, भागलपुर को निर्देशित करना चाहती है कि एस0डी0आर0एफ0 टीम को स्थायी रूप से नियुक्त करें ?

अध्यक्ष : कहलगांव में नियुक्त करें ?

श्री पवन कुमार यादव : जी सर ।

अध्यक्ष : बोलना न चाहिए कहलगांव । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : महोदय, दो टुकड़ी सबौर और सुल्तानगंज में रखी गयी हैं और उसका रखरखाव वहां के जिला पदाधिकारी करते रहते हैं । भागलपुर के

जिलाधिकारी दो जगह रखे हुए हैं और जब दुर्घटनाएं होती हैं तो वहीं से टीम भेजी जाती है ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, क्या सरकार के पास आंकड़ा है कि सबौर में कितनी दुर्घटना घटी और कहलगांव में कितनी घटी ?

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : महोदय, अभी यह आंकड़ा मेरे पास नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप...

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, सर्वाधिक घटना सबौर की अपेक्षा कहलगांव में घटती हैं, इसका मानवीय आधार है कि कहलगांव और बटेश्वरस्थान उत्तर वाहिनी गंगा के छोर पर हैं, वहां हजारों की संख्या में गंगा स्नान करने के लिए झारखण्ड, बिहार से लोग आते हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेता हूं । ऐसे सर्वाधिक चूंकि सभी जानते हैं कि श्रावणी मेला सुल्तानगंज से शुरू होता है और ठीक है माननीय सदस्य की चिंता है कि कहलगांव में भी हो तो जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवाकर उस पर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–454 (श्री रामप्रवेश राय, बरौली)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि बरौली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मांझा एवं बरौली प्रखंड के कृषि कार्य हेतु लगे चोरी हुए सामनों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं । उक्त घटनाओं के दर्ज प्राथमिकी के आलोक में कंपनी के वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार तथा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध एवं चोरी की घटना के रोकथाम हेतु लगातार पत्र एवं मौखिक रूप से समन्वय स्थापित किया जा रहा है । वर्तमान में पुलिस अनुसंधान प्रक्रियाधीन है । उक्त विद्युत संरचना के पुनःस्थापन के लिए सर्वे का कार्य किया जा चुका है एवं कार्य के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । निधि की उपलब्धता के आलोक में शीघ्र ही उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये रामप्रवेश जी ।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है लेकिन हम लोगों की सरकार के लिए, यह डबल इंजन की सरकार है और इतना हास्यास्पद जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी की, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री रामप्रवेश राय : महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार की है कि कृषि कार्य के लिए अलग से ट्रांसफॉर्मर, तार, पोल लगाये जाते हैं और उस तार, पोल की चोरी हुए कई महीने हो गये और जवाब आया है कि कार्य के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । निधि की उपलब्धता के आलोक में शीघ्र ही उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा । महोदय, इसके लिए निधि की कोई कमी है ?

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री रामप्रवेश राय : मेरा पूरक है कि यह जवाब ही ठीक नहीं है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री रामप्रवेश राय : निधि कब तक उपलब्ध होगी ? बार–बार मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में दौरा होता है...

अध्यक्ष : ठीक है । बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री रामप्रवेश राय : सरकार को...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय,...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । जवाब हो रहा है । बैठ जाइये ।

श्री रामप्रवेश राय : कृषि सरकार की प्राथमिकता में है और कृषि कार्य के लिए...

अध्यक्ष : रामप्रवेश जी बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : चोरी भी प्राथमिकता में है ? जब ट्रांसफॉर्मर की चोरी हो गयी, जांच की प्रक्रिया चल रही है इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है, जल्दी ही करवा दिया जायेगा ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, आखिर कब तक होगा ? चोरी अगर हो गयी है तो चोरी आप रूकवाइये, कार्रवाई कीजिये...

अध्यक्ष : रामप्रवेश जी, पूरक पूछिये ।

श्री रामप्रवेश राय : पूरक है कि उन किसानों के खेतों में फिर कब तक ट्रांसफॉर्मर और तार, पोल लगाकर के विद्युत की आपूर्ति की जायेगी ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, दिखवा लेते हैं । जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय,...

अध्यक्ष : शीघ्र किया जायेगा । बैठिये ।

तारांकित प्रश्न सं0–455 (श्री छोटे लाल राय, परसा)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरियापुर में जी0एन0एम0 के कुल 16 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 03 जी0एन0एम0 पदस्थापित है । स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–1629(6), दिनांक–10.12.2024 द्वारा जी0एन0एम0 के 7903 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को अधियाचना भेज दिया गया है । अनुशंसा प्राप्त होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी । ओ0टी0 असिस्टेंट का 1683 रिक्त पदों का अधियाचना भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को भेज दी गई है । आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया जा चुका है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरियापुर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध कराने हेतु Ultrasound Machine with Colour Doppler की आपूर्ति का आदेश निर्गत किया जा चुका है । मशीन प्राप्त होते ही शीध्र अधिष्ठापित कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री छोटे लाल राय : महोदय,...

अध्यक्ष : रामप्रवेश जी, हो गया । बैठिये । छोटे लाल जी, पूरक पूछिये ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बतला दें...

अध्यक्ष : आप इधर देखकर पूछिये न पूरक ।

श्री छोटे लाल राय : जी, हम तो लिखे हुए हैं...

अध्यक्ष : बोलिये न ।

श्री छोटे लाल राय : वहां अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था करनी है और कब तक वहां लगा देंगे, हम लोग क्षेत्र वहीं होकर जाते हैं और मुख्य सड़क है वहां दुर्घटना होती रहती

है, इसके पहले भी इनको अनुरोध किये थे, गंभीरता से दिखवा लीजिये और जो प्रश्न है उसको करवा दीजिये यही आग्रह कर रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, यह हमारी भी सोच है कि सेवा की बहाली शीघ्रातिशीघ्र हो जाय और...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उत्तर सुनिये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : सेवा की बहाली शीघ्रातिशीघ्र हो जाय इसीलिए जो आवश्यक कार्रवाई करनी है वह सभी कार्रवाई विभाग के द्वारा की गयी है । मैं माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां चिकित्सक की उपलब्धता और अल्ट्रासाउण्ड मशीन की उपलब्धता शीघ्रता से कराने की कोशिश करूंगा ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, सीवान मुख्य...

अध्यक्ष : बैठिये । हो तो गया ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, समय–सीमा तो बता दी जाय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप मधुबनी से उधर कहां आ गये, उनके प्रमंडल, आप उनके प्रमंडल में क्यों घुस गये । छोड़ दीजिये उनको ।

(व्यवधान)

छोटे लाल जी, जब उधर ही से जाते हैं तो कर ही न देंगे । बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0–456 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, सिकटा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (लिखित उत्तर) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण के पुरषोत्तमपुर के अंडरग्राउंड केबुल के माध्यम से डायरेक्ट सिकटा में विद्युत आपूर्ति पूर्व में होती थी । परंतु रेलवे अंडरग्राउंड कॉसिंग केबुल जल जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भेड़िहरवा से सिकटा बाजार समेत प्रखंड के कई पंचायतों में बिजली की आपूर्ति की जा रही है । विद्युत आपूर्ति सही एवं सुचारूरूपेण बहाल है ।

स्वीकारात्मक । वर्तमान में भी विद्युत आपूर्ति सही एवं सुचारूपेण बहाल है ।

अंडरग्राउंड केबुल बदलने हेतु रेलवे को आवेदन किया गया है, जिसका आवेदन संख्या–ECR-SPJ-2024-WL-44 है । अनुमति प्रकिया में तीन माह का समय लगने की संभावना है । रेलवे से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत रेलवे अंडरग्राउंड केबुल कार्य पूर्ण करा–कर सिकटा में पुनः पूर्व की भांति विद्युत आपूर्ति बहाल की जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह सिकटा बाजार और प्रखंड में बिजली आपूर्ति में जो बाधा होती है उससे संबंधित सवाल है तो पहले वहां जो व्यवस्था थी रेलवे लाईन क्रॉस करने के लिए अंडरग्राउण्ड तार लगाया गया था पुरूषोत्तपुर हॉल्ट के पास तो अभी जो व्यवस्था है वह भेडिहरवा होकर बिजली सप्लाई होती है जिससे वहां आपूर्ति बाधित है तो इस संदर्भ में सवाल यही था कि बिजली आपूर्ति करने के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाय, रेलवे स्टेशन के पास पुरानी अंडरग्राउण्ड व्यवस्था हो तो महोदय जवाब तो है एक हद तक संतोषजनक है कि...

अध्यक्ष : ठीक है । बैठिये ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : तीन माह के अंदर करने के लिए कहा गया है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहे, वह कागज पर ही न रहे, हम मंत्री जी से यह आश्वस्त होने चाहते हैं कि वह तीन माह में हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, रेलवे को लिखा गया है, रेलवे से समीक्षा करके उसको जल्दी से जल्दी करवाया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

टर्न–7 / मुकुल / 07.03.2025

## शून्यकाल

श्रीमती मंजू अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में स्वच्छता पर्यवेक्षक को 7500/– रुपया के स्थान पर 20,000/– मासिक वेतन एवं पर्यवेक्षक व कर्मियों की सेवा स्थाई करने की मांग करती हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बसमत्ता पंचायत के मोहीपुर कुरवा टोला में मनरेगा के तहत आवंटित कार्य को मजदूरों से न कराकर जे0सी0बी0 मशीन से कार्य कराई जा रही है । अतः सरकार से उक्त मामले में गहन जांचकर कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत परिहार उत्तरी, परिहार दक्षिणी एवं धरहरवा पंचायत मिलाकर जनसंख्या 50 हजार के ऊपर है जो नगर पंचायत होने की पात्रता रखती है । अतः सरकार से सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने की मांग करती हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्षम महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों हिसुआ, नरहट और अकबरपुर में 3,000 राशन कार्ड पेंडिंग है, जिसे बनाने के लिए गरीबों से कर्मचारियों द्वारा 2—2 हजार रुपया रिश्वत मांगी जाती है, राशि नहीं देने पर पेंडिंग छोड़ दिया जाता है, इसकी निगरानी जांच की मांग सरकार से करती हूं ।

श्रीमती निशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखंड के पथरवार पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत एल0ओ0—55 से चतरा पथ का निर्माण लम्बे समय से अधूरा है । इस पथ का यथाशीघ्र निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखण्ड में के0जी0डी0—84 मुख्य नहर पर पासवान टोला के समीप पुल नहीं होने से वहां के आमजनों को काफी कठिनाई होती है ।

अतएव उक्त पुल का यथाशीघ्र निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के प्रखंडों राजापाकर, सहदेई बुजुर्ग और देसरी का महनार में अवस्थित अनाज गोदामों से बिचौलियों को अनाजों की अवैध सप्लाई से पी0डी0एस0 दुकानदारों को अनाजों की आपूर्ति वजन में कम होती है, जिसकी निगरानी से जांच कराने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज प्रखण्ड के हरदी टेढ़ा पंचायत में हरदी टेढ़ा गांव एवं राजपुर तुमकड़िया पंचायत में तुमकड़िया गांव का पंडई नदी से प्रत्येक वर्ष कटाव होने के कारण आधा गांव विस्थापित हो गया है ।

अतः मैं सरकार से उक्त दोनों गांव में शीघ्र कटावरोधी कार्य करने की सदन से मांग करती हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन :अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अन्तर्गत पोठिया प्रखण्ड के पोठिया बाजार, छत्तरगाछ बाजार एवं दामल बाड़ी बाजार एक बहुत बड़ा व्यापारी स्थान है किन्तु यहां भारतीय स्टेट बैंक की कोई भी शाखा नहीं रहने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः मैं उक्त स्थलों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा की मांग करता हूं।

मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, राज्य में जन वितरण प्रणाली के डीलरों को देश में सबसे कम 90 रुपया क्विन्टल की दर से कमिशन दिया जाता है । वहीं दिल्ली में 200, हरियाणा 170, हिमाचल 143, महाराष्ट्र 180, गोआ 280 रुपया प्रति क्विन्टल की दर से भुगतान करती है, जो बिहार के डीलरों के साथ नइंसाफी है ।

मैं प्रतिमाह 30,000 रुपया मानदेय भुगतान की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सदन में घोषणा किये थे भूमिहीनों को वैकल्पिक व्यवस्था बगैर नहीं उजाड़ा जायेगा, परन्तु समस्तीपुर जिला के गोलिया ग्राम, अंचल सिघिया के दर्जनों महादलितों के घरों को प्रशासन ने उजाड़ दिया ।

मैं सरकार से उक्त उजड़े महादलितों को अविलम्ब पुनर्वासित करने की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार 25 फीसदी दलित गरीबों का परिवार जहां दशकों से बसे हैं, उस जमीन का मालिकाना कागजात उसके पास नहीं है । अनधिकृत बसावटों मुकम्मल भौतिक सर्वे समय का तकाजा है । बिना वैकल्पिक व्यवस्था गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगे । मैं मांग करता हूं कि इस दिशा में कानून बनाये ।

श्री मोहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों जेसे मुखिया/समिति/सरपंच/वार्ड सदस्य की मासिक मानदेय बहुत ही कम है । जिससे प्रतिनिधियों को जीवन–यापन में काफी दुशवारियों का सामना करना पड़ता है । अतः मैं सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक मानदेय में वृद्धि की मांग करता हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में कार्यरत पंचायत स्वच्छता कर्मी, रसोईया, सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, स्कूलों के रात्रि प्रहरी आदि निष्ठापूर्वक राज्य के विकास में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं ।

मैं सरकार से उक्त सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी की दर से मासिक वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रदेश में बापू के ग्राम स्वराज, स्वच्छता के सपने को साकार करने लगे, एक लाख पन्द्रह हजार स्वच्छता कर्मी एंड 8 हजार पर्यवेक्षकों को संविदा कर्मी की घोषणा कर मानदेय को क्रमशः 5 हजार एंड 15 हजार बढ़ाकर मुख्यालय से भुगतान करावे ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारियों को 400/– रुपये दिया जा रहा है जो इस महंगी व्यवस्था में बहुत कम है उक्त पेंशनधारियों के लिए कम से कम 1500/– रुपये मासिक, ससमय पेंशन देने की मांग सरकार से करता हूं ।

डॉ0 मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड सिंघवाड़ा में किसानों के फसल की सिंचाई हेतु स्थित कुशुमपट्टी, सिरहुल्ली एवं टेक्टार उदवह योजना जिनका कई वर्षों से मरम्मती नहीं होने के कारण बंद है, जिससे किसानों के सिंचाई हेतु काफी कठिनाइयां होती हैं । सदन के माध्यम से सरकार से मरम्मती कराने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के कहलगांव विधान सभा अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सनोखर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरहन एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जानीडीह का अपना भवन निर्माण कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री शिव प्रकाश रंजन : अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों में आई0टी0सी0 लैब इंस्ट्रक्टर को तीन वर्षों के लिए रखा गया था । एक वर्ष कार्य करने के बाद निकाल दिया गया है । उनको पुनः काम पर लौटाया जाए और एक साल का वेतन बकाया है, उसको भुगतान करने की मांग करता हूं ।

टर्न–8 / यानपति / 07.03.2025

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ । आ गए ससुराल से आप, अभी–अभी इनकी शादी हुई है एक बार ताली बजाकर इनका अभिनंदन कर दीजिए । बोलिए संदीप जी । पूरे सदन की तरफ से आपको बधाई देते हैं और माननीय मंत्री जी भी आपको बधाई देनेवाले हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपकी शादी हुई है, इस सदन के आप सदस्य हैं इसलिए हमलोग तो आसन से आग्रह करते हैं कि पूरे सदन की तरफ से इनको शादी की बधाई दे दी जाय ।

अध्यक्ष : अभी सत्र की समाप्ति के बाद आप मेरे कक्ष में आइयेगा, वहां आपका अभिनंदन करेंगे, बधाई भी देंगे ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत रनियातालाब और आरा जिलांतर्गत संदेश के बीच सोन नदी पर पुल नहीं होने से आवागमन में कठिनाई होती है । कोईलवर और अरवल पुल के बीच 50.7 कि0मी0 तक कोई और पुल नहीं है । अतः रनियातालाब और संदेश के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के शिक्षक–शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान 2024 से ही नहीं हुआ है, जिसके चलते शिक्षक और उनका परिवार बेहद आर्थिक संकट से जूझ रहा है । अपनी मांगों को लेकर शिक्षक–शिक्षिकाएं आंदोलनरत हैं । सरकार से तत्काल वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा अंतर्गत मेजरगंज प्रखंड के हरसखरी खैरवा विश्वनाथपुर के समीप नदी में श्लुईस गेट का निर्माण होने से लाखों किसानों के हित में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । मैं सरकार से उक्त स्थान पर अविलंब स्लुईस गेट निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल के शहर तेलपा एवं कुबड़ी में पशु चिकित्सालय के लिए भवन निर्माण हेतु जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद भवन नहीं बना है । ग्रामीणों को काफी संकट होता है । सरकार से शहरतेलपा एवं कुबड़ी में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, घोसी विधानसभा अंतर्गत एक मात्र प्रखंड काको में बड़ी मुस्लिम आबादी है । सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द तथा छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काको प्रखंड मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

मो0 इजराइल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय,राज्य के गृह रक्षा वाहिनी के सदस्यगण बिहार पुलिस के समतुल्य ही विधि व्यवस्था का संधारण करते हैं, परंतु उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय प्राप्त होता है मासिक वेतन से वंचित रह जाते हैं ।

अतः उन्हें भी बिहार पुलिस की भांति मासिक वेतन एवं भत्ता दिलाने की मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय रोड पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं जर्जर है । इसे अविलंब बनवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकोठी प्रखंड के पीरनगर चौक से राजकपुर जानेवाली सड़क जर्जर है जिससे आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः जनहित में अतिशीघ्र उक्त पथ का निर्माण करवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के नगर पंचायत अकबरनगर में उच्च्य मानक का एक अस्पताल बनाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार के साढ़े चार लाख बंगाली शरणार्थी परिवारों में 90 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं । पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड में उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी का दर्जा मिल चुका है । बिहार में भी मूल जाति श्रेणी के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत जाफरनगर पंचायत के सीताचरण दियारा क्षेत्र में किसानों द्वारा बोये फसल को अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर काट लिया जाता है ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बांका जिलांतर्गत धोरैया प्रखंड के चंदाडीह पंचायत के भगौंधा गांव के पास गहिरा नदी में पुल क्षतिग्रस्त होने से काफी परेशानी होती है एवं दुर्घटना प्रत्येक दिन होती है । यह पुल दो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है ।

अतः जनहित में पुल के नवनिर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग द्वारा प्रस्तावित पांच स्थानों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं रमई गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य विभाग की लापरवाही से संवेदकों द्वारा आधा–अधूरा कर छोड़ दिया गया है यथाशीघ्र सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य संपन्न कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत नरपतगंज प्रखंड के खाब्दह पंचायत वार्ड संख्या–7, साह टोला से घीवहा परवाहा मार्ग तक पक्कीकरण सड़क निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सभी पंचायतों में कार्यरत विकास मित्र जो बिहार के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं । बढ़ती महंगाई को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाया जाय तथा राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए सातवां वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान देने की मांग करता हूं ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, चित्रगुप्त नगर थाना ,खगड़िया केस नंबर–27/24 दिनांक–25.05.2024 में राजनीति साजिश तहत कारेलाल यादव एवं अमन कुमार छात्र को फंसाया गया जिसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जरूरत है ।

उपमहानिरीक्षक बेगूसराय स्तर पर केस नंबर–27/24 को पुनः अनुसंधान समीक्षा करते हुए कारेलाल यादव एवं छात्र अमन कुमार को दोष मुक्त करने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत बैसा प्रखंड के कटहलबाड़ी पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से अर्था जानेवाली सड़क का कार्य प्रारंभ वर्ष–2020 में हुआ था किंतु संवेदक द्वारा अभीतक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है जिस कारण ग्रामीणों में आक्रोश है ।

अतः कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा अंतर्गत तेघड़ा प्रखंड में गौरा चौर से कौआ कोल तक 8 पंचायत के करीब 5000 एकड़ उपजाऊ जमीन है । बरसात के दिनों में जल जमाव से फसल बर्बाद हो जाती है ।

अतः जल निकासी का स्थायी निदान करने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । जो शेष शून्यकाल हैं ध्यानाकर्षण के बाद समय बचेगा तो उसको लिया जायेगा ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' एवं श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद । आपकी सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में अक्टूबर–2022 से राज्य के सभी जिलों में कैंसर रोग की रोकथाम एवं उपचार हेतु निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है । राज्य के सभी जिलों में कैंसर मरीजों की खोज हेतु प्रचार–प्रसार की गतिविधियों के साथ–साथ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है । होमी बाबा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है । राज्य के छः जिलों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर का संचालन किया जा रहा है, बायोप्सी के माध्यम से कैंसर रोग की सभी जिला अस्पतालों में पहचान हेतु जांच की जाती है । (क्रमशः)

टर्न–9 / अंजली / 07.03.2025

(क्रमशः)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महावीर कैंसर संस्थान में राज्य सरकार की तरफ से पेट, सीटी–स्कैन के क्रय हेतु 13 करोड़ रुपए की स्वीकृत्यादेश संख्या–1115, दिनांक–07.09.2015 को एवं बोन मेरो ट्रांसप्लांट हेतु 1 करोड़ 93 लाख रुपए मशीन क्रय हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–1532 प्रदान किया जा चुका है । सवेरा कैंसर हॉस्पिटल, रोटरी, पटना मिड टाउन तथा आर0एस0एस0 मेमोरियल कैंसर सोसायटी को कैंसर रोग के स्क्रीनिंग में सहयोग प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्रांक–2, दिनांक–17.01.2025 द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है, इनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाने का भी कार्य किया जा रहा है । एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर में कुल 10 हजार 295 कैंसर निदान हेतु शल्य चिकित्सा किया गया है तथा एन0एच0सी0एच0 पटना में एक वर्ष 6 माह में कुल 574 कैंसर निदान हेतु शल्य चिकित्सा किया गया । होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के द्वारा अब तक कुल 574 कैंसर निदान हेतु शल्य चिकित्सा किया गया । होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान के द्वारा अब तक कुल 23 लाख स्क्रीनिंग किया गया जिसमें कुल 4 हजार 21 कैंसर के मरीज चिन्हित किए गए, साथ ही, कुल 52 हजार 905 मरीजों को कीमोथेरेपी प्रदान की गई । 23 जनवरी, 2025 को दरंभगा के गंगवारा अस्पताल में 100 बेड मुख्य एवं गले के कैंसर के इलाज के लिए विशेष अस्पताल की स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया । राज्य सरकार 112 करोड़ की लागत से पैलिएटिव केयर की 100 शय्या वाले अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थापित करने जा रही है, जिसकी शुरुआत शीघ्र होगी । बिहार सरकार द्वारा आई0जी0आई0एम0एस0 पटना में राज्य कैंसर संस्थान जो 100 शय्या बेड का है, में कैंसर पीड़ित मरीजों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है । कैंसर के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सा अनुदान राशि प्रदान की जाती है । कैंसर मरीजों को रेडियोथेरेपी की सुविधाएं आई0जी0आई0एम0एस0, पटना एवं पी0एम0सी0एच0, पटना, एम्स, पटना तथा होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर में उपलब्ध है । अगले दो माह के अंदर मुजफ्फरपुर

में 425 करोड़ रुपए की लागत से होमी भाभा कैंसर संस्थान में नए हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा । डे केयर सेंटर के कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी हेतु कुल 59 दवा निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । 9 से 14 आयु वर्ग के किशोरियों को सर्वाइकल से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है, ऐसा करने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है । सीड संस्था द्वारा कैंसर के नियंत्रण, रोकथाम हेतु तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाकर सरकार को तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तार से कैंसर जैसी घातक बीमारियों के बचाव के लिए जो किए जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है । उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जन को भी निर्देश दिया है इसके लिए, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी जिलों में कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए आप सर्वे कराकर पूर्णतः एक समय–सीमा के अंदर जैसे एक वर्ष का समय निर्धारित हो या 6 माह का समय निर्धारित हो चूंकि जिस गति से कैंसर का मरीज का मिल रहा है, आपने माननीय मंत्री जी के उत्तर में भी सुना है ...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । संक्षेप में अपनी बात कहिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : कि 22 लाख लोगों में 4 हजार कैंसर का मरीज मिला है, तो यह गति बहुत तेज है और बड़ी तीव्र गति से यह हो रहा है और जिस परिवार में कैंसर हुआ, वह उजड़ गया । कोई परिवार सुरक्षित नहीं रहा । इसलिए मेरा मानना है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहिए । आज 12:30 तक ही सदन है और बाकी माननीय सदस्यों का भी है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जी, 12.30 तक है । महोदय, एक मिनट भी नहीं लिया हूं । अभी आपका दस मिनट शेष है । तीन क्वेश्चन है । मैं देख रहा हूं ।

अध्यक्ष : हो गया आपका, बताइए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सभी जिलों में एक निश्चित अवधि में सर्वे कराकर कि किस जिले का क्या रेशियो है...

अध्यक्ष : आप दोबारा दोहरा क्यों रहे हैं ? बैठ जाइए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : उसको मंगाकर और उस हिसाब से उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाय ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्वाइंट–2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बायोप्सी के माध्यम से कैंसर रोग के सभी जिला अस्पतालों में पहचान हेतु जांच ऑलरेडी की जाती है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मेरा केवल समय से था कि सर्वे एक समयावधि के अंदर कराने का...

अध्यक्ष : टाइम नहीं है । कैंसर की बीमारी हमेशा होती रहती है, बढ़ती रहती है, लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है और कैंसर के बारे में मुझसे ज्यादा थोड़े न आप जानते हैं । मैंने अपनी पत्नी खोया है, मैंने अपना भाई खोया है, मैं ज्यादा जानता हूं और सरकार जितना काम कर रही है उतना कोई नहीं, कभी नहीं कर पाया है । बैठ जाइए ।

माननीय सदस्य, श्री सुधांशु शेखर । अपनी सूचना पढ़िए ।

श्री सुधांशु शेखर, श्री अशोक कुमार चौधरी एवं श्री ललित नारायण मंडल, स॰वि॰स॰ से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर (सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, राज्य में जनवितरण प्रणाली की दुकानों को संचालित करने वाले डीलरों को अनाज वितरण करने पर जो कमीशन दिया जाता है, वह काफी कम दिया जाता है । इस कारण डीलरों को जीवनयापन में काफी कठिनाई होती है । उन्हें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है । जन वितरण प्रणाली के डीलर हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जिस कारण ही लोगों को अनाज की उपलब्धता हो पाती है ।

अतः हम जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का कमीशन कम से कम दोगुना देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा नियम, 2015 के तहत उचित मूल्य के दुकानों के संचालकों को उनके द्वारा वितरण किये गये कुल खाद्यान्न की मात्रा के विरुद्ध 70 रुपए प्रति

क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जा रहा था । कालांतर में खाद्य सुरक्षा संशोधन नियम, 2022 के अधिसूचित होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक–01.04.2022 से उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन मनी को 70 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कुल 90 रुपए प्रति क्विंटल किया गया । जिसके आलोक में वर्तमान में उचित मूल्य के दुकानों के संचालकों द्वारा वितरण किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा के विरुद्ध 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न को राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से निशुल्क वितरण कराया जा रहा है । चूंकि यह योजना केंद्र प्रायोजित है जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा नियम, 2015 एवं खाद्य सुरक्षा संशोधन नियम, 2022 के तहत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय बेसिक डीलर्स मार्जिन मनी हेतु केंद्रीय सहायता एवं राज्यांश की राशि का प्रतिशत क्रमशः 50–50 निर्धारित है । वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बेसिक डीलर मार्जिन हेतु 90 रुपए प्रति क्विंटल का दर निर्धारित है जिसमें केंद्रीय सहायता की राशि के रूप में 45 रुपए प्रति क्विंटल एवं राज्यांश के रूप में शेष 45 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि का व्यय किया जा रहा है तथापि यदि भारत सरकार द्वारा बेसिक डीलर मार्जिन की दर को संशोधित किया जाता है तो तद्नरूप राज्य सरकार द्वारा भी उक्त दर में संशोधन करते हुए डीलर्स मार्जिन दर में वृद्धि कर दी जाएगी ।

श्री सत्यदेव राम, श्री अजय कुमार एवं अन्य नौ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर_

से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम जी, अपनी सूचना को पढ़िए ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी वर्गों के प्रोन्नति पर Status Quo है । सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 द्वारा SC/ST के 17 प्रतिशत पदों को FREEZE कर अन्य वर्ग को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर

उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा रहा है । उच्चतर प्रभार में प्रोन्नति की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं यथा–वेतनमान, वरीयता, कालावधि की परिगणना, सेवांत लाभ सहित रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की जा रही है । इस व्यवस्था से हजारों SC/ST कर्मी उच्चतर पदों के प्रभार से वंचित हो गए हैं, जिससे संवैधानिक समानता के अधिकार का हनन हुआ है और दूसरी ओर SC/ST के लिए नई नियुक्तियों में रिक्तियां भी प्रभावित हो रही हैं । इससे SC/ST को दोहरा मार पड़ रहा है ।

अतः उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के मद्देनजर SC/ST को भी अन्य वर्गों के तरह FREEZE पदों पर उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

टर्न–10 / पुलकित / 07.03.2025

अध्यक्ष : सत्यदेव बाबू, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वैसे तो जवाब कुछ लम्बा है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जो माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण सूचना में कह रहे हैं कि ये जो तात्कालिक प्रोन्नति दी जा रही है इसमें एस0सी0 / एस0टी0 वंचित हो रहे हैं लेकिन सही स्थिति यही है कि इसमें वंचित नहीं हो रहे हैं । क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है या सरकार ने जो नियम बनाया था कि जो इनको परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति दी जाए यह हमलोगों की सरकार का ही निर्णय है, जिसके खिलाफ न्यायालयों में, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक मामला गया और अंत में वहां से स्थगन आदेश के आलोक में अभी स्थगित है। लेकिन फिर भी जो एकदम सब, पूरा एक तरह से जाम की स्थिति हो गयी थी, किसी की प्रोन्नति नहीं हो पा रही थी इसलिए हुआ कि प्रभार कार्यकारी प्रभार देकर के ही बाकी अन्य सुविधाएं दी जाए और उसमें जो माननीय सदस्य ने कहा है कि उससे वे वंचित हो रहे हैं । स्थिति ऐसी नहीं है जो कार्यकारी प्रभार दिया जा रहा है उसमें भी जो उस लिस्ट में, उस श्रेणी तक आते हैं एस0सी0 / एस0टी0 के भी जिनका मामला है, कर्मी या पदाधिकारी हैं उनको भी ये कार्यकारी प्रभार दिया जाता है । इसलिए मूल रूप से ऐसी बात नहीं कि कार्यकारी प्रभार देने में कहीं उनको छोड़ दिया जाता है और उनके लिए जो 17 प्रतिशत अलग से सीट

आरक्षित करके छोड़ दी जाती है । जब पदों की गणना होती है अगर वेकेन्सी की 100 सीट है तो उसमें 83 सीट पर ही कार्यकारी प्रभार भी दिया जाता है, 17 सीट उनके लिए आरक्षित छोड़ दी जाती है और इस 83 सीट पर भी जो कार्यकारी प्रोन्नति दी जाती है उसमें भी एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठिये, यह क्या तरीका है ? सत्यदेव जी बोल रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह जवाब असत्य है और मेरे पास सारे एविडेंस है । महोदय, इनकी जो अधिसूचना जारी हुई है, यह अधिसूचना जारी हुई है उसमें जो नियमावली दी गयी है उसके विरोध में माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : विरोध में कैसे बोल सकते हैं ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, विरोध में बोल रहे हैं क्योंकि वह असत्य बोलना है । अभी तो यही बात है कि इस नियमावली को लागू होने से पूरी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आज उच्चतर पदों पर जाने से वंचित हो रही है । महोदय, यही नहीं अब वह पद से ऊपर नहीं जा रहा है जिसके कारण निचला पद खाली नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हम यह कह रहे हैं कि जब आपका यह जाम हो रहा था तो सारे वर्ग के लोगों के लिए आपने खुला किया तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए फ्रिज क्यों किया, वह भी चलता । महोदय, जब हाई कोर्ट का निर्णय आता तब आप इनको भी इसी तरह से लागू करते जिस तरह से उनके लिए आपने व्यवस्था की है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम यह समझ नहीं पाये कि किसके हित की बात कह रहे हैं । ये कह रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्था किये हैं वह इनके लिए भी करिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, जिनको देना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार ने तो सिर्फ एस0सी0/एस0टी0 वर्गों के लिए ही व्यवस्था की है, किसी दूसरे वर्ग के लिए कहां कोई विशेष व्यवस्था है? जिस नियम और नियमावली की बात कहते हैं, उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। महोदय, जिस नियमावली की बात कर रहे हैं उसके नियम 6(ग) में स्पष्ट लिखा है कि– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विहित पदों को सुरक्षित रखने के बावजूद मूल कोटि की वरीयता के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को भी समान रूप से उच्चतर पद के प्रभार का लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

महोदय, यह तो नियमावली में स्पष्ट है और इसी नियम से सरकार कर रही है । इसमें आपका क्या मतलब और कहां दिक्कत है ? अगर इस नियम का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप मामला दीजिए, सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : बिना समझे कि सरकार उल्लंघन कर रही है और महोदय, हम तो स्पष्ट रूप से सदन को बताना चाहते हैं कि यह सारा मामला आया ही है बिहार सरकार के एस0सी0/एस0टी0 के कर्मियों या पदाधिकारियों के हित में जब इनको परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति देने का फैसला लिया, उसी के कारण मामला कोर्ट में गया । सरकार की नियत साफ है, हम ही ने निर्णय बनाया है, इनको अलग से जो दोहरी मार कह रहे हैं, इनको दोहरा लाभ देने का निर्णय बिहार सरकार का है और ये कहां बीच में बिना समझे इसको डायवर्ट कर रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिना समझे सवाल है ? मंत्री जी कह रहे हैं तो मैं भी पढ़कर सुना देता हूँ कि इस नियमावली के अधीन अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के लिए रोस्टर क्लीयरेन्स की व्यवस्था नियमित प्रोन्नति की व्यवस्था आरंभ होने तक स्थगित रखी जायेगी । महोदय, यह फ्रिज करने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ गयी ? सबके लिए ....

अध्यक्ष : सत्यदेव बाबू, बैठ जाइये । सत्यदेव जी, पहले बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा ही है कि सरकार ने बड़े साफ मन से एस0सी0/एस0टी0 के कर्मियों को दोहरा लाभ देने के लिए नियम बनाया था, किसी को वंचित करने के लिए यह नियम, किसी दूसरे का कहा हुआ नहीं है । हम ही लोगों की सरकार ने नियम बनाया था और क्योंकि मामला कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण रूका हुआ है और यह भी जान लीजिए कि जब कोर्ट ने रोका है तो एक वह नियम लागू रहे परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति इसके लिए एस0एल0पी0 में बिहार सरकार ही उच्चतम न्यायालय गयी है जो एस0सी0/एस0टी0 अधिकारियों/कर्मियों के हित में उनको दोहरा लाभ दिया जाए, इसी के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय गयी है ।

श्री सत्यदेव राम : लेकिन अभी तो ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री सत्यवेद राम : महोदय, सुन लिया जाए, सरकार दोहरा लाभ देने के लिए उच्चतम न्यायालय में गयी है लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले का फलाफल इस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर ही क्यों पड़ रहा है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, हम बताते हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, 17 प्रतिशत जो फ्रिज किया है उसको आप वापस लीजिए, नहीं तो यह पूरे बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध है । हम आपसे यही अपील करते हैं कि सबका जब होगा तो उसमें जो घटाना बढ़ाना होगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उसी रेश्यो में घटायेगा लेकिन अभी इन फ्रिज पदों को खाली कर दिया जाए ।

अध्यक्षः आप तो नुकसान पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार ने तो फ्रिज किया नहीं है, सरकार ने तो कर्मियों की जो बाधित सुविधा थी एस0सी0/एस0टी0 के साथ अन्य कर्मियों को भी प्रोन्नति की सुविधा बिल्कुल बाधित नहीं रहे जो हमने कहा स्टेलमेट में जो कहते हैं कि अनिर्णय की स्थिति में कोर्ट भी निर्णय नहीं दे रहा है और हमलोग कोर्ट से कह रहे हैं जो आपके एस0सी0/एस0टी0 कर्मियों के अधिकतम हित में

है । बिहार सरकार उसके लिए कोर्ट गयी है, यह हमेशा याद रखिये कि बिहार सरकार उनके अधिकतम हित को संरक्षित करने के लिए हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 7 मार्च, 2025 के लिए...

(व्यवधान)

समय बहुत हो गया । पूरा जवाब आ गया है, स्पष्ट जवाब आ गया है ।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

शून्यकाल की सूचनाएँ

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में महान शासक शेरशाह सूरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग करता हूं, रोहतास जिले में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होने की वजह से यहां के छात्रों को आरा और गया जाना पड़ता है ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र लौरिया में दलित आवासीय विद्यालय नहीं है । हमारे दोनों अंचल लौरिया तथा योगापट्टी में जमीन पर्याप्त है। दलित बच्चों को शिक्षा में अग्रसर करने हेतु 720 आसन का बाबा साहब अम्बेडकर आवासीय विद्यालय स्वीकृति करने हेतु सदन के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद जिला के रतनी–फरीदपुर प्रखण्ड के नाराणपुर पंचायत के पतिआवाँ के पास मोरहर नदी के (उसपार) पूर्वी छोर पर मखदुमपुर प्रखण्ड के जयविगहा, सागरपुर 10+2 विद्यालय है ।

पतिआवाँ जयविगहा के बीच में मोरहर नदी पर उच्चस्तरी पुल निर्माण कराने की माँग सरकार से करता हूँ ।

डॉ0 शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल रक्सौल के अधीन छोड़ादानो प्रखण्ड के ग्राम पैठानपट्टी से बशुवहिया जाने वाली सड़क के पसाह नदी पर पुल नहीं होने के कारण पांच किलोमीटर दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है ।

अतः सरकार से आमजनों के हित में उक्त पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मुख्यमंत्री के गृह जिला से महिला हत्या की दर्दनाक और भयावह दृश्य सामने आया है । कटिहार, कैमूर, समस्तीपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सिवान आदि जिलों से महिला हिंसा की बर्बर तस्वीर सामने है । स्नेहा कुशवाहा का बलात्कार हत्या से राज्य मर्माहत है । हम सरकार से महिला दिवस की पूर्व संध्या पर स्पष्ट वक्तव्य की मांग करते हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सभी शेखटोली से आदर्श कॉलोनी से लहेरियागंज होते हुए जीवछ नदी की उड़ाही एवं पक्कीकरण किये जाने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, बीहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड एवं नारायणपुर प्रखंड के क्रमशः पश्चिम केबीन और पूर्वी केबीन के पास आर0ओ0बी0 नहीं रहने के कारण घंटों जाम लगा रहता है ।

अतः दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर आर0ओ0बी0 बनाने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11 / अभिनीत / 07.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''दिनांक 07 मार्च, 2025 को कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''दिनांक 07 मार्च, 2025 को कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :–

1. वृहस्पतिवार दिनांक 13 मार्च, 2025 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो ।
2. वृहस्पतिवार दिनांक 13 मार्च, 2025 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग से संबंधित आय–व्ययक एवं अनुदान की मांग शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 को मुखबंद के माध्यम से निष्पादित किये जायं ।
3. वृहस्पतिवार, दिनांक 13 मार्च, 2025 के सभी स्वीकृत प्रश्नों को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिए जायं । शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

## वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा :–

| | |
|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | – 59 मिनट |
| राष्ट्रीय जनता दल | – 57 मिनट |
| जनता दल यूनाइटेड | – 33 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | – 14 मिनट |
| सी0पी0आई0 (एम0एल0) | – 08 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | – 03 मिनट |
| सी0पी0आई0 (एम0) | – 02 मिनट |
| सी0पी0आई0 | – 02 मिनट |
| ए0आई0एमआई0एम0 | – 01 मिनट |
| निर्दलीय | – 01 मिनट |
| | कुल = 180 मिनट |

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हमलोगों का 09 मिनट होता था ।

अध्यक्ष : 09 मिनट कब होता था ? जोड़ लीजिए । जोड़ लीजिए, फिर से हम जोड़ लेंगे । अभी बैठ जाइये । हम जोड़कर देख लेंगे ।

प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6806,53,49,000/– (छः हजार आठ सौ छः करोड़ तिरेपन लाख उनचास हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अखतरूल ईस्लाम शाहीन, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम से पथ निर्माण विभाग के संपूर्ण मांग पर प्रति कटौती प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ से अनुदान मांग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं । इन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं । संपूर्ण मांग पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ का कटौती प्रस्ताव प्रथम है । बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 173 (6) के प्रथम परंतुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दी गयी कटौती प्रस्ताव को प्रमुखता दी जाती है ।

अतः माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष 3054, उप मुख्य शीर्ष–80 के लिये 2343,23,71,000 (दो हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़ तेईस लाख इकहत्तर हजार) रुपये की मांग 5,00,00,000 (पांच करोड़) रुपये से घटाई जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव मितव्ययिता के दृष्टिकोण से दिया है । इस उप मुख्य शीर्ष में गाड़ी के ईंधन, कार्यालय व्यय, भाड़े की गाड़ी आदि का प्रावधान किया गया है जिसमें कटौती की जा सकती है । इसमें आश्चर्यजनक रूप से विधि प्रभार मद में 1.20 करोड़ और दूरभाष में 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इस तरह के अनेक गैर जरूरी खर्चों में अत्यधिक राशि का प्रावधान किया गया है । इसलिए कटौती की जानी चाहिए ताकि योजनाओं के लिए निधि का अभाव नहीं हो । मेरा अनुरोध है कि ऐसे खर्चों को कम करते हुए मधुबनी विधान सभा क्षेत्र की तीन योजना जो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पथ निर्माण विभाग में लंबित है उन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाय । पहला तो एयर स्ट्रीप का है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पार्टी ने आपको समय नहीं दिया है । आपने पुट किया, अब आप बैठ जाइये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : केवल इतना कहना चाहेंगे कि सिंघानिया चौक से सुदी हाई स्कूल और आर0के0 कॉलेज से भुवाना उद्यान तक सड़क निर्माण कराने की व्यवस्था करें ।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं । आपने मुझे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राम, अपना पक्ष रखें । आपका समय 08 मिनट है ।

श्री सुरेन्द्र राम : बहुत–बहुत धन्यवाद । महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हमको आपने मौका दिया इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं और मैं गरीबों के मसीहा, जन–जन के नेता, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी एवं तेजस्वी बाबू को भी हम तहेदिल से धन्यवाद देते हैं और अपने गरखा विधान सभा की जनता मालिक को भी तहेदिल से धन्यवाद देता हूं । चूंकि उनकी वजह से ही मैं इस सदन में पहुंचा हूं ।

कहना है कि गांधी जी एवं अन्य देश की आजादी में जिन्होंने भूमिका निभाने का काम किया । जिनकी वजह से यह देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, देश तो 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ लेकिन असली आजादी हमलोगों को, हमारे गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी के लंबे संघर्ष के बाद हमलोगों को 1990 में आजादी मिली । सामंतवादियों की जो जकड़न थी, जिसमें दलित, गरीब, मजदूर, महिला, किसान को एकदम काम कराने के बाद भी मजदूरी नहीं देना यह सामंतवादी विचारधारा की सोच थी । हम आदरणीय लालू जी के उस संघर्ष को तहेदिल से सलाम करते हैं कि लाख विपरीत परिस्थितियों के बाद आदरणीय लालू जी ने जो हमें आजादी दिलाने का का किया, पहले तो आप देख रहे होंगे कि चौक–चौराहों पर दलितों को बोलने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था । काम करने के बाद, खेत जोतने के बाद, खेत का गेहूं काटने के बाद उचित मजदूरी मांगे जाने पर जब दलितों को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को बांध कर पीटा जाता था । बंधुआ मजदूर की तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो हम तो यही

कहेंगे कि आदरणीय लालू जी की वजह से हमलोग आजादी पूर्ण रूप से माने, 1990 में मिला है । आज उन्हीं की आजादी का, उन्हीं की लड़ाई की देन है कि वहां प्रथम कुर्सी पर आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे हैं, द्वितीय कुर्सी पर जो हमारे चौधरी जी बैठे हुए हैं, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के परिश्रम, उन्हीं के संघर्ष की लड़ाई की वजह से वे लोग बैठे हुए हैं और वे क्षण भर में कुर्सी के लोभ में भूल जाते हैं आदरणीय लालू जी के उस संघर्ष की लड़ाई को ..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुरेन्द्र बाबू, उस कुर्सी पर श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर भी बैठ चुके हैं इसका ध्यान रखिएगा ।

श्री सुरेन्द्र राम : महोदय, 2005 से, यह लालू जी के संघर्ष की लड़ाई ही है कि 1990 से लेकर 2005 तक स्वयं और माता राबड़ी देवी जी और 2005 से जो आज कुर्सी पर विराजमान हैं...

..क्रमशः...

टर्न–12 / हेमन्त / 07.03.2025

श्री सुरेन्द्र राम : (क्रमशः) : वह हमारे नेता आदरणीय लालू जी के संघर्ष की लड़ाई है और नहीं तो उनको कोई पूछता ? खटिया पर तो वह लोग बैठने नहीं देते थे । उनको उससे उठा देते थे कि उठो, यहां दलित, बैकवर्ड, अतिपिछड़ा के लिए कोई जगह आरक्षित नहीं है । तो हम यही कहेंगे कि आदरणीय लालू जी ने सामंतियों के साम्राज्य को पलटकर समाजवाद की यहां स्थापना की । यह आदरणीय लालू जी की देन है । हम यही कहेंगे कि आदरणीय लालू जी, आप सब लोग चौकीदार को सुने होंगे, जो रात–रात भर घूमकर अपने यहां सुरक्षा के लिए पहरा देते थे, लेकिन लालू जी आये तो देखे कि इनको तो उचित मजदूरी नहीं मिल रही है । आदरणीय लालू जी ने चौकीदार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में उनको वेतनमान देने का काम किया । लालू जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है । आदरणीय लालू जी जब रेल मिनिस्टर बने, तो बोझ उठाने वाले हमारे दलित वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के कुलियों को भी रेलवे में क्लास फोर वर्ग का पद देने का काम किया । हम तो यही कहते हैं कि

लालू जी संत शिरोमणी गुरू रविदास जी के उस वचन, उस कथन को भी पूरा करने का काम किये । संत शिरोमणी गुरू रविदास जी कहा करते थे कि–

''ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न,

छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न ।

ये लालू जी, संत शिरोमणी गुरू रविदास जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे उन सारे महापुरूषों के सपनों को साकार करने का काम किये आदरणीय लालू जी ।

अध्यक्ष : अब केवल एक मिनट है आपके पास ।

श्री सुरेन्द्र राम : आदरणीय नीतीश कुमार जी, यहां आंगनबाड़ी सेविका हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, रसोइया हो उन सबके श्रम का शोधन करने का काम कर रहे हैं । तो हम यही कहेंगे कि लालू जी से आदरणीय नीतीश बाबू को सीखना चाहिए । हमारे संत शिरोमणी गुरू रविदास जी की सिर्फ पूजा करते हैं, वोट के लिए दिखावा करते हैं । पूरे बिहार से विकास मित्रों को बुलायें, सारे विकास मित्र भाई आयें । हो सकता है कि ये संत शिरोमणी गुरू रविदास जी की पूजा कर रहे हों, हो सकता है कि उनके विचारों पर चलकर हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से क्लास फोर या तृतीय वर्ग की श्रेणी में हो सकता है कि मान्यता देंगे । लेकिन बुलाकर उनको अपमानित करने का काम किये, उनको सम्मान देने का काम नहीं किये । आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत..

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री सुरेन्द्र राम : वर्ष 2016 से बिहार में क्लास फोर वर्ग के कर्मचारियों की बहाली बंद है । आउटसोर्सिंग के माध्यम से दलित भाइयों का शोषण कर रही है यह नीतीश जी की सरकार । क्यों नहीं बहाली कर रहे हैं क्लास फोर वर्ग में । क्लास थ्री वर्ग की बहाली हो सकती है, क्लास टू की बहाली हो सकती है, क्लास वन की बहाली हो सकती है, लेकिन क्लास फोर की बहाली इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें ज्यादातर जो सफाई का काम करते हैं किस वर्ग से आते हैं ? वह अनुसूचित जाति, दलित वर्ग से आते हैं। जो माली हैं, वह किस वर्ग से आते हैं. ..

अध्यक्ष : समाप्त करिये । समय समाप्त हुआ आपका ।

श्री सुरेन्द्र राम : अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं । जो गार्ड का काम करते हैं वह किस वर्ग से आते हैं, अनुसूचित वर्ग से आते हैं । लेकिन हम तो यह कहेंगे कि उनके साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा के हिमायती नहीं हैं, ये पिछड़ा अतिपिछड़ा के ये शोषण दोहन करने वाली इस सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में सामंतियों के साथ मिलकर हम लोगों का, दलित भाइयों का शोषण हो । ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका हो, कितनी मजदूरी उन्हें मिल रही है, तो आंगनबाड़ी सेविका को सात हजार रुपये महीना। यह मात्र 233 रुपया होता है । स्किल वर्कर का कितना होना चाहिए, 538 रुपया, प्रत्येक दिन 288 रुपया इनकी मेहनत का सरकार ले रही है । आंगनबाड़ी सहायिका का मात्र चार हजार रुपया महीना है, मात्र 133 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सरकार दे रही है । इनकी मजदूरी का 387 रुपया प्रतिदिन सरकार मार रही है । विकास मित्र रात दिन एक करके मेहनत करने का काम करते हैं, जो सभी कर्मचारी से ज्यादा मेहनत परिश्रम करने वाले हमारे विकास मित्र हैं इनको क्लास फोर वर्ग का वेतनमान मिलना चाहिए । मैं बता दूं कि आशा दीदी मात्र 600 रुपया और एक हजार रुपया मानदेय के रूप में दिया जाता है, यह 33 रुपया मात्र महोदय हो रहा है । इस सरकार को मैं कह रहा हूं कि आप किस युग में जी रहे हैं, इससे तो बेहतर अंग्रेजों की सरकार में मेहनत–मजदूरी करने वालों का भला होता था । आपने तो अंग्रजी हुकूमत को भी फेल कर दिया है । आज के युग में आशा दीदी को मात्र 33 रुपया मिल रहा है ।

(व्यवधान)

आप हमको बोलने से रोकना चाहते हैं । लालू जी ने हमको बोलने की ताकत दी है।

अध्यक्ष : सुरेन्द्र राम जी, इधर देखकर बोलिये ।

श्री सुरेन्द्र राम : यह आवाज अब रुकने वाली नहीं है । यह आवाज संघर्ष की आवाज है । यह आवाज अपने अधिकारों को लेने के लिए हमको लालू जी दिये हैं । हम जरूर बोलेंगे। आज मैं आपकी कृपा से नहीं पहुंचा हूं । मैं आज इस सदन में

पहुंचा हूं तो बाबा साहब भीम राव अंबेडकर और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने वाले लालू जी की कृपा से पहुंचा हूं । आपकी कृपा से मैं नहीं हूं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये सुरेन्द्र जी, हो गया ।

श्री सुरेन्द्र राम : महोदय, नहीं । आप इजाजत देंगे तो और बोलेंगे ।

अध्यक्ष : आपकी पार्टी ने जितना टाईम दिया है उतना ही न बोलियेगा ।

श्री सुरेन्द्र राम : आज आप देख लीजिए, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पासवान भाइयों...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राम जी आपका समय समाप्त हो गया है । श्री मिथिलेश कुमार । सुरेन्द्र जी, समय हम नहीं देते हैं, आपकी पार्टी समय देती है । सबसे कम समय आप ही को दिया है पार्टी ने ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पथ निर्माण में सरकार के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर मिला । इसके लिए तमाम सीतामढ़ी की जनता की ओर से संपूर्ण सदन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, विशेषकर आसन को ।

महोदय, चर्चा हो रही है कटौती प्रस्ताव की, बात हो रही है दलितों की रक्षा की । महोदय, सारे विश्व ने देखा है कि जिस दलित को ये इस श्रेणी में रखे थे कि जिससे सफाई करवाते हैं उसको आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, 500 वर्ष का इतिहास बदलने के बाद जब राम मंदिर बनता है, तो उसके कर्मचारियों का, उसके श्रमिकों का पैर धोकर पूजन करते हैं । दलितों के सम्मान का इससे बड़ा उदाहरण विश्व में नहीं है । महोदय, यह पिछड़ों की, अतिपिछड़ों की बात करते हैं । आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, संजीव जी ।

श्री मिथिलेश कुमार : जब कांग्रेस के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन होता है और संपूर्ण देश में जब यह नारा बनता है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है । उस समय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी उस आंदोलन के प्रणेता होते हैं और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में बिहार जब अंगड़ाई लेता है, उसमें से नीतीश कुमार जैसा समाजवादी नेतृत्व पैदा लेता है और उस समय कैलाशपति मिश्र के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कांग्रेस

विरोधी पहली सरकार बनती है और जिस आंदोलन के गर्भ से लालू जी पैदा लेते हैं, उस इमरजेंसी वालों की गोद में बैठते हैं । आप उसके साथ हैं । अभी भी चिंता करिये देश के लोकतंत्र की, आपके लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, गरीब और दरिद्र की बात करते हैं । यह हमारे सनातन ने सिखाया है आपको दरिद्रनारायण भवः । हम लोग दरिद्र को भी नारायण की श्रेणी में रखते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / धिरेन्द्र / 07.03.2025

...क्रमशः....

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, इस देश की आजादी में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे–बैठे मत बोलिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : वीर विनायक दामोदर सावरकर की जो आहुति हुई है और उस समय सहजानंद सरस्वती जो सन्यासी थे, जो दशनामी अखाड़ा के सन्यासी थे, वे देश के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेकर भारत माता के हाथ और पैर की बेड़ी और जंजीर को तोड़ने में सहायक बने थे और हमारा जो इतिहास है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इतिहास है । वंदे मातरम् की गूंज उठती है और संपूर्ण देश में क्रांति की चिंगारी फैलती है और 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरूआत होती है। प्रथम स्वतंत्र आंदोलन में और हम सभी भारत माता के सपूत उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं, देश के हजारों नौजवान बलिदान देते हैं और ये लोग बात कर रहे हैं, जिस लॉर्ड माउंटबेटेन की गोद में जाकर जवाहरलाल नेहरू बैठते हैं, उस अंग्रेजी हुकूमत के भी माननीय सदस्य मेरे मित्र चर्चा कर रहे थे और पथ निर्माण की बात हो रही है, ये तो उनके विषय पर बोलने को विवश हो गये । मैं सीता प्राकट्यस्थली से आता हूँ तो मैं....

अध्यक्ष : मिथिलेश जी, विवश होने की जरूरत नहीं है अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत नहीं है पथ निर्माण से तो नहीं बोला, आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर वे संतुष्ट हैं पथ निर्माण विभाग के काम से तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं ? आप अपनी बात कहिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, मैं सीता प्राकट्यस्थली से आता....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये, दूसरे की बात नहीं कहिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, मैं संपूर्ण सदन को उस धरती से, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ सीता से जो 'उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेषकरिं सीतां नमामि राम वल्लभां', ऐसी सीता माता आज जब देश 2047 के विकसित भारत का सपना देख रहा है, उसमें बिहार का संपूर्ण सदन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो उनको सीता माता सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे पथ निर्माण का, पर्यटन का, हमारे बजट का, हमारे राज्य के विकास का, हमारे राज्य में चिकित्सा के विकास का, हमारे राज्य में शिक्षा के विकास का, हमारे राज्य में जीविका जो उदाहरण बना है संपूर्ण देश में बिहार का, उन सब के विकास में और उन सब की सकारात्मक भूमिका के लिए हम विपक्ष से भी आग्रह करते हैं क्योंकि आप भी सरकार के ही अंग हैं । आइये, हम सभी मिलकर 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का, उन सभी में, उन सभी कार्यों में आपका साथ मिले, आपका स्वागत है ।

अध्यक्ष जी, इस बार जो कार्य हुआ है पथ निर्माण का उसकी चर्चा ये लोग नहीं करेंगे । मिथिला की भूमि, बिहार में मिथिला की भूमि तो अतिविशिष्ट भूमि रही है । महोदय, मिथिला की भूमि से जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरती हैं वह इजराइल की भूमि के लगभग सिमिलर है और इजराइल जैसी बौद्धिक फर्टिलिटी मिथिला के भूमि की है, मिथिला की भूमि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मखाना को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड बनाया और मिथिला में मत्स्य के विकास के लिए, तालाब के विकास के लिए अमृत सरोवर योजना की संकल्पना एन॰डी॰ए॰ की सरकार देखती है जिस सरकार की कोई विजुअलिटी नहीं है, उनके सदस्य को ये विजन नहीं है कि आदरणीय कर्पूरी जी ने क्या किया । उनको नजर आता है पथ निर्माण में, जिस सरकार में अलकतरा घोटाला का दाग लगता है उनको उस सरकार की बात नजर आती है और उनको यह नजर आती है कि वे दरिद्र, गरीब और अति पिछड़ा का काम करते हैं । दरिद्र, गरीब और अति पिछड़ा के निवाला को खाने वालों बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, बिहार की जनता भूली नहीं है, बिहार की जनता भूली नहीं है कि संध्या 06 बजे के बाद हमारी मातृशक्ति सड़क पर उतरने से डरती

थी, बिहार की जनता भूली नहीं है कि हमारे सड़क का टुकड़ा–टुकड़ा बेच कर ये लोग निवाला कर गए, ये बिहार की जनता भूली नहीं है इनका सपना धरा का धरा रह जाएगा । आगामी 50 वर्षों तक यह बिहार की जनता भूलेगी नहीं, ये लोग सपना देखते रह जायेंगे फिर से बिहार की जनता अपनी अस्मिता को बर्बाद करने का हक इस महागठबंधन के लोगों को नहीं देने वाली है । महोदय, मिथिला में जो पथ निर्माण विभाग ने काम किया है वह चिन्हित करने योग्य है। मिथिला लोक उत्सव, बौद्ध महोत्सव के तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार–प्रसार के लिए मिथिला के क्षेत्र में पर्यटन विभाग का काम हुआ और उस पर्यटन विभाग के तहत विश्व की विशिष्टतम धरती सीता प्राकट्यस्थली सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत पुनौरा धाम के विकास हेतु लगभग 51 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए हमारी सरकार ने 121 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दी है और वहीं पर सीता माता का जहाँ डोली बैठता है पंचपाखर में, वहाँ के लिए 23.66 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कर दी है । यह है हमारी विजुअलिटी, यह है हमारा सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और एन॰डी॰ए॰ सरकार चौमुखी विकास की बात करती है । इसी मिथिला में पर्यटन विभाग ने मिथिला हाट की तर्ज पर समस्तीपुर जिला में मुक्तापुर मोइन झील विकास हेतु 37.9 करोड़ रुपये एवं पूर्णियां जिला अंतर्गत काझाकोठी के विकास हेतु 14.94 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है । महोदय, संपूर्ण बिहार के साथ–साथ एक ऐतिहासिक निर्णय जो एन॰डी॰ए॰ की सरकार ने ली है वह ली है, शिवहर–सीतामढ़ी खंड में दो लेन चौड़ीकरण एवं पुनर्स्थापन कार्य, सीतामढ़ी से जयनगर में दो लेन मजबूतीकरण एवं पुनर्स्थापन कार्य, इतना ही नहीं सबसे, हमारे सांस्कृतिक....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल 05 मिनट और आपके पास है ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, हमारे सांस्कृतिक धरोहर जिसके लिए संपूर्ण देश 500 वर्ष बाट जोहती रही तब जाकर राम मंदिर का विकास और निर्माण हुआ, इसके लिए हम विपक्ष के लोगों से भी कहेंगे कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से एन॰डी॰ए॰ सरकार को धन्यवाद दीजिये कि राम–जानकी मार्ग यू॰पी॰ बार्डर से सिवान, वहाँ से मधुवन होते हुए सीतामढ़ी से लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर मतलब अवध भूमि जहाँ राम जी का जन्म होता है और सीता प्राकट्यस्थली सीतामढ़ी को स्पर्श करती

हुई ये पथ सीधा जहाँ माँ जानकी का पालन–पोषण और स्वयंवर हुआ था जनकपुर तक के लिए इस सरकार ने स्वीकृत किया है, उसके लिए राशि भी स्वीकृत की गयी है । महोदय, प्रगति यात्रा जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और एन॰डी॰ए॰ सरकार की दूरदर्शिता और विकास का संकल्प, उसके तहत प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने जाकर स्थानीय जगहों पर जब देखा कि कहाँ किन चीजों की आवश्यकता है तो उसमें, महोदय, 22 सड़कों का ऑन द स्पॉट वहाँ तय कियें । मुंगेर में किये, लखीसराय में किये, शेखपुरा में किये, औरंगाबाद में किये, बक्सर में किये, भोजपुर में किये, कैमूर में किये, रोहतास में किये, किशनगंज में किये, पूर्णियां में किये, मुजफ्फरपुर में किये, गोपालगंज में किये, दरभंगा में किये, मधुबनी में किये, समस्तीपुर में किये, बेगूसराय में किये मतलब वैसी सरकार....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पटना क्यों छोड़ दिये ? हमसे झगड़ा है ? पटना भी बोलिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, वैसी सरकार, पटना में तो लगातार कार्य हो रहे हैं, पटना की जब बात करता हूँ तो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ राज्य में ही विकास दिखाई देती है तो मैं जमीनी स्तर पर जिलों में, गाँवों में जो विकास होता है उसका आईना दिखाने के लिए सबसे लंबा सत्र है, सत्रहवीं विधान सभा का, इसलिए मैंने आईना दिखाने के लिए ये तीनों का नाम लिया....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल तीन मिनट हैं । इधर–उधर ध्यान मत दीजिये, सामने देखकर बोलिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एन॰डी॰ए॰ सरकार ने हाईस्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य किया, ये हाईस्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस–वे के बारे में वर्ष 2005 के पहले बिहार की जनता न कल्पना कर सकती थी, न नाम सुनी थी जिसको एन॰डी॰ए॰ सरकार में धरातल पर उतारा जा रहा है ।

...क्रमशः...

टर्न–14 / संगीता / 07.03.2025

(क्रमशः)

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, उत्तर–दक्षिण एक्सप्रेस–वे, हाई स्पीड कोरीडोर, आमसरामनगर, कल्याणपुर, दरभंगा के हरिक्षेत्र पथों से गुजरेगी । रक्सौल में हल्दिया एक्सप्रेस–वे,

हाई–स्पीड कोरीडोर में फारबिसगंज, कहलगांव, बाराहाट, नवादा, वारसलीगंज, मोकामा, बरौनी, झंझारपुर, लदनिया का भी अनुरोध किया गया है, इस पर भी सरकार काम करेगी । राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की कुल लम्बाई 13 हजार किलोमीटर करने का विचार रखती है एन0डी0ए0 सरकार और बृहत जिलों में कुल 6840 किलोमीटर को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करने का भी हमलोगों ने योजना भेजा है केन्द्र में । सड़क में जो वोल्डर ने खोदे थे, अवरोध उसको हटाने के लिए भी हमलोग मुजफ्फरपुर में बाईपास का निर्माण कार्य, बख्तियारपुर मोकामा में औटा–सिमरिया में सरिस्ताबाद में, हाजीपुर में, पटना में, बकरपुर में और ये पथ निर्माण में महोदय, ये गांधी सेतु का जो लेन बन रहा है, ये अटल पथ जो बना और पूरे पटना को जो जाम से निजात मिलता है, ये कभी दूसरे सरकार का दूरदर्शिता हो सकता था उसको ब्लूप्रिंट ही नहीं था, उसके आइडियाज ही नहीं थे तो उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करेंगे । अध्यक्ष जी, पथ निर्माण विभाग यहां तक चिन्ता करता है कि शहर के अंदर जैसे हमारे सीतामढ़ी में ये सरकार जो आर0सी0डी0 विभाग का पथ था तो किसी कारण से आर0सी0डी0 विभाग अगर नहीं बना पा रही है तो इस सरकार ने उसके लिए आमजन के हित में यह व्यवस्था किया 'मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना' । सीतामढ़ी की बाईपास सड़क जो आर0सी0डी0 के अंतर्गत थी उसका भी हमलोग चिन्ता कर रहे हैं । लंबी–लंबी सड़कों के साथ–साथ जो स्थानीय सड़क, जो जनता के दिन–रात आवागमन का मार्ग है, उसका भी हमलोग चिन्ता करके उसका भी निर्माण करवा रहे हैं, जिसके तहत सीतामढ़ी का वर्षों से उजड़ा–पुजड़ा जर्जर सड़क जो था बाईपास रोड, उसका भी हमलोग इस सत्र में निर्माण करवा रहे हैं...

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, जैसे सीतामढ़ी का ये पथ निर्माण विभाग से ही संबंधित है, सीतामढ़ी का रेलवे ओवर–ब्रिज, जो लालू जी के जमाने से लंबे अरसे से पड़ा था लोगों को कल्पना नहीं थी कि वहां भी आर0ओ0बी0 बन सकता है उसको भी एन0डी0ए0 की सरकार ने और पथ निर्माण विभाग ने उस आर0ओ0बी0 को बनाने का काम जारी किया है और वह जल्द ही लोकार्पित भी होने वाला है । यह एन0डी0ए0 सरकार का विजुएलिटी...

अध्यक्ष : धन्यवाद, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मिथिलेश कुमार : कामों को धरातल पर उतारने की संकल्पना और 2047 के विकसित भारत में बिहार के योगदान की भूमिका अदा करेगी एन0डी0ए0 सरकार । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार, अपना पक्ष रखें । आपका समय 24 मिनट है ।

श्री ऋषि कुमार : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं आज पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों के मांग अनुदान के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका, अपने नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का एवं अपनी ओबरा विधान सभा की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, अनुदान की जो मांग की गई उसमें मैंने देखा, जो बजट 2023–24 में जो 9 हजार 430 करोड़ का था उसमें स्पेंडिंग जो की सरकार ने वह लगभग 13 हजार 935 करोड़ की और जो 2025–26 में मांग रखी गई है जो 6 हजार कुछ करोड़ का आपने बताया तो वह लगभग 39 परसेंट कम है जो एक्चुअल स्पेंडिंग पिछले साल हुई थी उससे तो एक यह सवाल बनता है कि क्या जहां 13 हजार करोड़ रुपये पिछले साल खर्च हुए थे इस साल क्या कम सड़कों की संख्या बनाने के लिए या फिर अनुपूरक फिर बाद में लायेंगे एक सवाल यह है । हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को सुना था जब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण पर वे जवाब दे रहे थे । महोदय, वे कह रहे थे कि पटना आने के लिए किसी भी क्षेत्र से बिहार के सुदूर क्षेत्र से पहले 7 घंटे हुए, फिर 6 घंटा हुआ फिर 5 घंटा हुआ । महोदय, एक वास्तविक सच्चाई यह है कि पटना तक आते–आते जो ट्रकों की लाइन पटना के हर बाउंड्री के ऊपर है चाहे हम उस सेतु की बात ले लें जो अपना सेतु बना है फिर अगर हम नौबतपुर की बात कर लें जो एन0एच0–39 पर है, ऐसी जितनी भी सड़क पटना की तरफ आती है वह आप किसी भी समय आप आ जाएं, ट्रकों की लंबी लाइन होती है और जाम से जूझना पड़ता है कम से कम डेढ़ से दो घंटे...

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए, सुन लीजिए । वास्तविकता यह है कि जब भी पटना हम पहुंचने का प्रयास करते हैं तो पटना के बाहर लंबी जाम का हमें सामना करना पड़ता है । माननीय उप मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे हैं पिछले दिनों ये आए थे औरंगाबाद । अगर इनके साथ स्कॉट नहीं होता तो इनको भी 2 घंटे तक कम से कम इंतजार करना पड़ता । मैं बहुत जेन्युइन समस्या के बारे में यहां पर जानकारी दे रहा हूं और ये सब फेस करते हैं । महोदय, पिछले बरसात के बाद हमने पुलों के गिरने का सिलसिला देखा था । लगभग–लगभग पिछले मॉनसून के आसपास 12 से 15 पुल गिरे थे, जिसमें सुपौल में मार्च, 2024 एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिरा, कोसी नदी के अंदर पिलर नंबर–154 के आसपास । पूर्णिया–कटिहार में 15 मई, 2023 को भी कास्टिंग वर्क के दौरान पुल का एक हिस्सा गिरा । कटिहार जुलाई, 2022 में भी अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलेप्स होता है । बख्तियारपुर में 20 मई, 2022 में 136 वर्ष पुराना ब्रिज गिर गया, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है । इसी क्रम में महोदय, हमारे विधान सभा में ओबरा विधान सभा में हमने 2022 में सदन के माध्यम से ही प्रश्न पूछा था कि अदरी नदी के ऊपर ओबरा बेल बराही पथ है उसमें बहुत ही पुराना पुल बना हुआ है, वह पुल भी किसी भी वक्त गिरने की कगार पर है । 2022 में मैंने इसकी मांग रखी थी कि उस पुल का फिर से निर्माण कराया जाय जो आज तक विचाराधीन है तो मैं सदन के माध्यम से इसके ऊपर भी जवाब चाहूंगा । महोदय, पुलों के गिरने के क्रम में एक पुल जो सबसे अहम है वह है, सुल्तानगंज अगवानी घाट ब्रिज जो भागलपुर से खगड़िया को, दो डिस्ट्रिक्ट को टच करता है यानी कि अगर खगड़िया से किसी को देवघर जाना हो तो वह डेढ़ से दो घंटे में पहुंच जाय । वह ब्रिज महोदय 3–3 बार गिरा है । पहली बार पिलर नंबर 5 और 6 के आसपास 30 जून, 2022 को । दूसरी बार पिलर नंबर–10 और 12 के बीच में खगड़िया की तरफ 4 जून, 2023 को । तीसरी बार, जो स्ट्रक्चर था पिलर नंबर–9 पर, वह कोलेप्स करता है 17 अगस्त, 2024 को । उसके बाद सरकार की तरफ से जब स्टेटमेंट आया, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया एक याचिका की सुनवाई पर । सरकार ने उस टाइम एस0के0सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को फाइनेलाइज करते हुए यह मेंडेट किया कि ब्रिज जो है कंपनी अपने खर्चे पर बनाएगी ।

उसका क्या रहा, उसका क्या स्टेटस है आज के डेट में मुझे नहीं मालूम । कल परसो सुनने में यह आ रहा था कि उस कंपनी को डिबार किया गया है पर क्या डिबार कर देना सजा काफी है ? जो एक्सचेकर मनी लॉस हुआ, जो जनता के टैक्स के पैसे वेस्ट हुए उसको कैसे हम रिकवर करेंगे यह बहुत बड़ा सवाल है । उसके बाद एक्सपर्ट कमिटी बुलायी गई, जो एक्सपर्ट कमिटी थी उन्होंने अपनी जांच में यह बताया कि पुल गिरने की 3 खास वजह थी, एक तो स्ट्रक्चरल डिजाइन, दूसरा खराब मेटेरियल का इस्तेमाल और तीसरा जो टाइमली काम होना था, जैसे–जिस समय जितना समय छोड़ना चाहिए था पिलर को कास्ट होने के बाद उतना समय नहीं दिया गया तो जब यह डिजाइन का फ्लो आता है महोदय, तो हमने संवेदन को तो घेर लिया पर उस कड़ी में जब हमने आर0टी0आई0 के माध्यम से इन्फोर्मेशन और मंगाया कि उसके डिजाइन कंसल्टेंट यानी कि जो इस प्रोजेक्ट का अथॉरिटी इंजीनियर अपॉइन्ट हुआ था महोदय, मुझे आर0टी0आई0 के माध्यम से पता चला कि...

(क्रमशः)

टर्न–15 / सुरज / 07.03.2025

श्री ऋषि कुमार : (क्रमशः) ये Studio De Miranda Associati JV with M/s Rodic Consultant Pvt. Ltd. इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर को संयुक्त रूप से ऑथिरिटी इंजीनियर नियुक्त किया गया था । फिर मैंने M/s Rodic Consultant के बेवसाइट को खंगाला फिर मुझे पता चला कि ये और कहां–कहां काम कर रहे हैं बिहार सरकार में । जब लिस्ट हमने निकाली तो पता चला कि 2015 से, यह अप्वाइंटमेंट भी 2015 में ही हुआ था इनका Rodic का । 2015 से लेकर के इन्होंने SAKKADI-SAHAR Section SH 81 के ऊपर काम किया है as supervision consultant । इन्होंने SAHAR-NASARIGANJ Section SH 81 पर काम किया है । इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 535 करोड़ थी । इसी तरह सीवान में 89 बहुत छोटा सा लिखा हुआ है वह समझ में नहीं आ रहा है । यह उन्हीं के वेबसाइट से निकाला हुआ रिपोर्ट है, ये 203 करोड़ का । Agreement Execution Date किसी का 4 जुलाई, किसी का 15 जुलाई । 2013, 2014,

2015, 2016 यानी की कुल लगभग–लगभग 2 हजार, 2.5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के लिये supervision consultant अप्वाइंट हुये और आर0टी0आई0 के माध्यम से ही जो जानकारी हमने निकाली के इस JV को कितना पेमेंट का भुगतान किया गया था । इसमें साफ लिखा हुआ है कि Studio De Miranda Associati JV with M/s Rodic Consultant Pvt. Ltd. को सुल्तानगंज–अगुवानी गंगा घाट पुल परियोजना के निर्माण कार्य के ऑथिरिटी इंजीनियर के रूप में दिनांक–27.05.2015 को कार्य आवंटित किया गया एवं इन्हें अब तक सुल्तानगंज–अगुवानी घाट पुल परियोजना में कुल रनिंग अकाउंट बिल का भुगतान 63.86 करोड़ रुपया किया गया है । महोदय, अब यह जो फिगर आता है यह बहुत Interesting फिगर इसलिये भी हो जाता है कि आमतौर पर किसी भी प्रोजेक्ट का 1 परसेंट या 2 परसेंट कंसलटेंट को भुगतान किया जाता है । अभी तक सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर 12 सौ करोड़ से ज्यादा का खर्च किया है और अगर 63 करोड़ का हम एवरेज निकालते हैं तो यह कहीं 5 परसेंट या 6 परसेंट के आस–पास निकलता है, जो अपने–आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह् है कि आखिर इतना भुगतान इस JV को क्यों किया गया ? यह जांच का विषय है मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे और क्योंकि यह उसके डिजाइन से, उसके सुपरविजन से जुड़े हुये थे सुल्तानगंज–अगुवानी पुल के । तो क्या इनकी भी बराबर की जिम्मेदारी नहीं बनती है ? क्या ये भी सजा के हकदार नहीं हैं ? पर इनके साथ इतने प्रोजेक्ट हुये उसके बाद और जानकारी जब हमने इनके वेबसाइट से निकाली तो पता चला कि ये स्वास्थ्य विभाग में भी काम कर रहे हैं as a consultant एक बहुत बड़ी योजना वह कर रहे हैं वहां पर, स्टेट हेल्थ सोसायटी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में डिजिटल ट्रांसफार्मेशन का जो कि पूरे 38 जिले में इम्प्लीमेंट होना है और लगभग 13 हजार प्लस पेसेंट का डेटाबेस जमा करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है । महोदय, इनके वेबसाइट पर यह तो मेंशन नहीं था कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका क्वांटम कितना है अमाउंट में । पर अनुमोदन यह भी करोड़ों

में ही जायेगा तो आखिर ऐसा क्या है Rodic Consultant के साथ । एक सीरियल आता था बहुत पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है ।

(इस अवसर पर सभापति (श्रीमती ज्योति) देवी ने आसन ग्रहण किया)

देखते थे कलर्स के ऊपर आता था ये रिश्ता क्या कहलाता है । तो ये रिश्ता वाकई में महोदय क्या कहलाता है और किसके साथ कहलाता है कि Rodic Consultant का रिश्ता कहां–कहां तक है । यह जिम्मेदारी तय होने के बजाय हम उसको बिहार सरकार में और ज्यादा से ज्यादा काम दिये जा रहे हैं । तो इस रिश्ते को हम क्या नाम दें अब तो सदन के माध्यम से मैं यह जरूर जानना चाहूंगा इसके ऊपर जवाब ।

महोदया, ये किस्सा तो था जितने भी पुल गिरे हैं उसका । अब आगे जो सरकार का जवाब आयेगा उसको हम देखेंगे कि क्या आता है । अभी हमारे साथी कह रहे थे कि केन्द्र के द्वारा बहुत सारे एन0एच0 एक्सपैंशन और थ्री लेनिंग, टू लेनिंग का अनॉन्समेंट किया गया है । उसमें पटना–औरंगाबाद एन0एच0 139 को फोरलेन में परिवर्तित करने के लिये जब केन्द्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री, माननीय नितिन गड़करी जी आए थे गया में कुछ दिनों पहले । उन्होंने वहां घोषणा की थी कि एन0एच0 139 को फोरलेन बनाया जायेगा । उसके बाद सर्वे भी स्टार्ट हुआ । सर्वे के बाद हमारी जो दिशा की बैठक होती है जिले में उसमें भी हमारे सामने सर्वे की रिपोर्ट रखी गयी की ऐसे–ऐसे यह सड़क बनना है केन्द्रीय मंत्री जी का आश्वासन हो चुका है, आवंटन का इंतजार है । महोदय, कल के अखबार में एक खबर आती है इस एन0एच0 139 को फोरलेन नहीं किया जायेगा क्योंकि सासाराम–पटना फोरलेन बनाया जा रहा है । अब सासाराम, औरंगाबाद से लगभग 50–55 किलोमीटर दूर है । तो क्या जिन लोगों को औरंगाबाद से पटना जाना है वह सासाराम आकर फोरलेन लेंगे ? यह बहुत बड़ा सवाल है । हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो हमारा लोड है इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें तो और ज्यादा फोरलेन्स की जरूरत है जितना हमारा ट्रैफिक है । महोदय, एन0एच0 139 इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह मार्ग पटना से लेकर हरिहरगंज होते हुये रजबारा झारखंड को जोड़ती है । इस

मार्ग से लोग मध्यप्रदेश के गढ़वा, चौवन एवं छत्तीसगढ़ के चेरीबरी, बिलासपुर, रायपुर तक पटना से ट्रैवल करते हैं, इस पर बसों का परिचालन होता है और इसी राजमार्ग पर बिहार के राजस्व का इजाफा करने वाले सैंड माइन्स भी बहुत सारे हैं सोन के किनारे तो वहां पर ट्रकों का ट्रैफिक का लंबा–चौड़ा है । तो यह एन0एच0 139 फिर सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि इस सदन से प्रपोजल फिर से जाए केन्द्रीय मंत्री जी को और इस एन0एच0 139 का फोरलेनिंग जल्द से जल्द कराया जाए । मैं यहां इस सदन से मांग करता हूं ।

महोदया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अपने वक्तव्य में कहा था कि जाम से जुझना पड़ता है पटना आने के लिये उसी तरह ओवरा–दाउदनगर से जब हम चलते हैं अरवल की तरफ फिर नौबतपुर आता है । हमारे साथी वहां के रहने वाले हैं । नौबतपुर में इतना बड़ा जाम लगता है कि ट्रैफिक को निकालने के लिये कभी नहर का रास्ता, कभी दूसरा रास्ता, कभी तीसरा गोल–गोल घुमते हैं और जाम की स्थिति बनी हुई है तो मैं चाहूंगा कि रोड से कैसे उस जाम से निजात दिलायी जाए, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है ।

महोदया, एक और प्रक्रिया होती है जब भी आर0सी0डी0 की कोई नई सड़क बनती है तो उसके लिये जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है और किसानों से जमीन ली जाती है और जिन किसानों से जमीन ली जाती है और जो मुआवजा मिलता है वह इतना कम होता है क्योंकि किसानों के पास खेत के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है और जो मुआवजा मिलता है वह इतना थोड़ा मिलता है और इतने देर से मिलता है कि मुआवजे की अहमियत खत्म हो जाती है । वह किसान, वैसे किसान हैं जब उसके घर में बेटी की शादी होती है या किसी की शादी होती है तो जमीन का टुकड़ा बेचकर वह अपने हिसाब से शादी–व्याह करवाता है । पर जब सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है तो सालों–साल उसको मुआवजे का इंतजार करना पड़ता है । तो ये मुआवजे की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द कराया जाए और उचित मुआवजा किसानों को मिले मैं इस सदन से, आपके माध्यम से मांग करता हूं । कुछ परियोजनाएं और हैं सड़क की जोकि मैं आपके सामने कहना चाहता हूं । जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे एन0एच0ए0आई0 और इंडो–पाक नेपाल बार्डर का जो सड़क बन रहा है वह

पिछले 12 साल से बन रहा है और 12 साल से आज तक वह कम्प्लीट नहीं हुआ । क्या उसकी समय–सीमा तय की जायेगी आपने वाले समय में कि कितनी जल्दी बनेगा और कितना जल्द उस पर काम लगेगा ।

महोदया, दानापुर से कोयलवर तक जो रास्ता जाता है वहां भी पूरी जाम की स्थिति बनी रहती है । रोहतास के अंदर पाण्डुका ब्रिज है, वह भी घोषणा हुई लेकिन अभी तक बनना शुरू भी नहीं हुआ । सोनपुर प्रमंडल के तीन बाईपास का एग्रीमेंट हो चुका है और एग्रीमेंट हुये एक वर्ष से ज्यादा हो चुका है । तीन बाईपास, पर अभी तक एक मीटर भी काम शुरू नहीं हुआ ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / राहुल / 07.03.2025

श्री ऋषि कुमार : (क्रमशः) महोदया, पुलों की सुरक्षा को लेकर के राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे पुलों का हेल्थ कार्ड बनायेंगे और उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से रीयल टाईम मॉनिटरिंग होगी कि पुल की क्या हालत है । ताकि कोई भी डैमेज छोटे से बड़ा होने से पहले उसको काबू किया जा सके तो उस योजना का क्या हुआ ? क्या सारे पुलों का हेल्थ कार्ड बना है वह भी जानकारी इस सदन के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा । क्योंकि पुल के निर्माण के बाद पुल की जो टेक्नीक्लीटी है उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट और दूसरा होता है वॉल बियरिंग । जो दोनों चीजों की मेजर मेंटिनेंस दस साल के अंदर–अंदर दोबारा होना चाहिए तो क्या ऐसे मेंटिनेंस की प्रक्रिया है हमारे यहां ? महोदया, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स और यूथ भी है तो उसके उपर भी मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा । महोदया, खेल विभाग हमारे यहां बहुत ही लचर तरीके से काम कर रहा है । हमारी मित्र वहां बैठी हैं, श्रेयसी जी बैठी हुई हैं वे जानती हैं कि स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व है, प्रॉपर ट्रेनिंग का क्या महत्व है वे अच्छे से जानती हैं । महोदया, किसी भी खेल के व्यवसायीकरण से पहले उसका आधार प्रॉपर ट्रेनिंग है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग है, प्रॉपर कोचेज के साथ ट्रेनिंग है । हमारे बिहार में कुल चार स्टेडियम अभी कार्यरत हैं । एक पटना का ऊर्जा स्टेडियम है, एक मोईन–उल–हक स्टेडियम है पटना का, फिर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स है और आखिर में जो

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजगीर में बनाया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बना रहे हैं । महोदया, इन चार स्टेडियम्स में अगर हम बात करें तो पटना ऊर्जा स्टेडियम थोड़ा लेटेस्ट बना है, मोईन–उल–हक स्टेडियम का रीकंस्ट्रक्शन प्लान जो है वह पिछली सरकार में आया था, 17 महीने की जो सरकार थी तेजस्वी जी की और नीतीश कुमार जी की, महागठबंधन की सरकार, उसमें उस स्टेडियम को रीकंस्ट्रक्शन करने का प्रपोजल आया था पर पता नहीं उसके ऊपर कोई काम हुआ या नहीं हुआ नई सरकार के बाद, वह भी आपके माध्यम से जानना चाहेंगे तो किसी भी स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, उसके बाद हमें वर्ल्ड क्लास कोचेज और ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है । फिर जो तीसरी सबसे जरूरी चीज है वह है हमारे खिलाड़ियों की सेहत यानी न्यूट्रिशन रिलेटेड इशूज । अभी हमारे यहां कोई भी ऐसा सही उपक्रम नहीं है सरकार का जहां पर प्रॉपर गाइडेंस मिले जैसे स्पोर्ट्स क्लीनिक हो या स्पोर्ट्स कंसल्टेशन का कोई ऑफिस हो जहां पर सही नॉलेज दिया जा सके कि राइट न्यूट्रिशन वर्सेज बैन्ड ड्रग्स के बारे में जानकारी दी जाय । क्योंकि हमारे युवा कई बार जल्दी रिजल्ट को पाने के लिए ऐसे सबस्टेंसेज का यूज करने लगते हैं जो कि नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बैन्ड कैटेगरी में माने जाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, उसमें सरकार का ज्यादा खर्चा नहीं होना है क्योंकि अगर हम एक कंसलटेशन वाली ही यूनिट स्टार्ट करें हर जिले से एक–एक स्टार्ट करें तो भी कई हद तक हमारा कार्य सफल हो जाता है । महोदया, इन सब चीजों के बाद जो चैलेंजेज हमारे युवा आज की डेट में फेस कर रहे हैं और छोटे–छोटे बच्चे, वह है ड्रग्स की समस्या । महोदया, हमारी जो आने वाली जेनरेशन है वह ड्रग्स की तरफ बढ़ती जा रही है । पहले ये बच्चों को आदत दिलाते हैं जो बड़े–बड़े पैडलर्स होते हैं, पहले बच्चों को आदत दिलाते हैं, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के । सुवाइटनर्स, पेट्रोल, पेंट थीनर्स, इस तरह के सबस्टेंशेज यूज करके छोटे बच्चों को गुमराह किया जाता है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य अब संक्षिप्त करें । आपका सयम दो मिनट और बचा है ।

श्री ऋषि कुमार : जी महोदया, इस तरह से पहले छोटे बच्चों को गुमराह किया जाता है । एक सर्वे के अनुसार पहले हमारी सोसाइटी में 60 परसेंट एडिक्शन के जो केसेज आते थे वे एल्कोहल रिलेटेड होते थे जो कि बड़ों से ही संबंधित था, एडल्ट्स में ही था लेकिन जब से आज के समय में जो है यह 30 परसेंट स्मैक, कैनोबीज जैसी चीजों पर आ गये और वे भी 80 परसेंट 18 साल से कम उम्र के युवाओं के बीच में है इस सर्वे के हिसाब से । महोदया, हमारे युवा, हमारा भविष्य हैं, हमारे कल का बिहार है, हमारे कल का भारत है अगर हम इनके उपर आज ध्यान नहीं देंगे और मैं यह नहीं कहता कि सरकार ही सिर्फ इसके उपर काम करे यह एक–एक सिटीजन का फर्ज है अपने बच्चों को देखना, अपने बच्चों को संभालना और अगर हम कामयाब नहीं होते तो यह हम सबका क्लेक्टिव फेलियर है । प्रशासन का भी, हमारा भी और सरकार का भी, आमजन का भी । मैं तो मीडिया के बंधुओं को भी कहता हूं कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डोमेन में डालें ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ऋषि कुमार : महोदया, बस खत्म करूंगा । सिर्फ चार लाईन बोलकर, कहना तो बहुत कुछ था पर चार लाईन ऐसी हैं कि

सरों पर ताज रखते थे, कदम पर तख्त रखाता था ।
वह कैसा वक्त था, मुट्ठी में सारा वक्त रखता था ।।
वे ब–दस्तूर चलते रहे, लम्हों को रोककर वहीं ।
पर आज न साख उनकी थी और न मुस्तकबिल ही उनका था।।

बहुत–बहुत धन्यवाद महोदया ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल जी अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदया, आपने हमको समय दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं पथ निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत जो आय–व्ययक की बात है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हम इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पथ निर्माण मंत्री, भाई नितिन नवीन जी का और

सदानंद बाबू का मैं शुक्रगुजार हूं और अपने क्षेत्र, सुल्तानगंज की महान जनता का भी शुक्रगुजार हूं कि हमको यहां पर बोलने का मौका मिला है ।

महोदया, पहले क्या स्थिति थी इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है । जब हम लोग पढ़ते थे तो सुल्तानगंज से भागलपुर जाने में गाड़ियां हिचकोले खाया करती थी, पता नहीं लगता था रोड है कि गढ्ढा है । गढ्ढा है कि रोड है यह अंतर करने में बहुत परेशानी होती थी । बस मालिक परेशान रहते थे, उनका बार–बार बहुत लॉस हुआ करता था । खैर एन0डी0ए0 की सरकार जब से बनी है तब से जो टारगेट तय किया गया था कि बिहार के किसी कोने से पटना तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लगे वह पूरा हो गया है । बिहार के किसी भाग से हम अगर पटना आते हैं तो 5 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं इसके लिए नीतीश कुमार जी के और एन0डी0ए0 सरकार के शुक्रगुजार हैं । महोदया, यह ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके लिए हाई स्पीड कॉरीडोर,एक्सप्रेस वे का निर्माण, एन0एच0 की लंबाई बढ़ाना, सड़कों के अवरोध को हटाना, रेलवे आर0ओ0बी0 का निर्माण है और मुख्य नदियों पर वृहद पुल का निर्माण इसके लिए कराया गया है । वर्ष 2024 और 2025 के सत्र में इसमें लगभग 4623.47 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं अब फिर एन0डी0ए0 सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को यही संतोष नहीं है, 5 घंटे से संतोष नहीं है । उन्होंने तय किया है कि अब 2027 तक बिहार के किसी कौने से पटना आने के लिए 4 घंटे का टारगेट उन्होंने रखा है कि चार घंटे में हम पटना पहुंच जायें ।

क्रमशः

टर्न–17 / मुकुल / 07.03.2025

क्रमशः

श्री ललित नारायण मंडल : इसके लिए काम करना पड़ेगा और उन्होंने काम तय किया है । ओ0पी0आर0एम0सी0 के तहत कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से पथों का सतत अनुश्रवण की व्यवस्था, कहीं पर अगर कोई सड़क में कुछ गड़बड़ी आ गयी है, कुछ खामियां आ गयी हैं तो उसका बराबर अनुश्रवण होता है और उसमें सुधार होता है कि गाड़ियों को आने–जाने में कोई दिक्कत न हो । महोदया, बहुत सारी और बातें हुई हैं जैसे गोरखपुर –सिलीगुड़ी एक्सप्रेस–वे, पटना–पूर्णिया

एक्सप्रेस–वे, राम जानकी मार्ग, पटना–बेतिया के फोरलेन का निर्माण इसके अतिरिक्त वाराणसी–रांची–कोलकाता एक्सप्रेस–वे, बक्सर–पटना–मोकामा–मुंगेर–भागलपुर–मिर्जा चौकी फोरलेन । जिस पथ से हमलोग पटना से भागलपुर जाते हैं ये लगभग पूरा हो चुका है । बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेस–वे, पिपड़ा–कोठी–रक्सौल टूलेन, पटना रिंग रोड का रामनगर सिक्सलेन पथ, आरा–मोहनिया फोरलेन का निर्माण ये सब कराना है, बहुत काम हो चुका है जिससे कि हम चार घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सकें । हाई स्पीड कोरिडोर की बात हुई है, पूर्णिया फोरलेन, गलगलिया–बहादुरपुर–अररिया फोरलेन का निर्माण कराकर के वहां से समय को बचाने की व्यवस्था की गयी है, रेलवे आर0ओ0बी0 का निर्माण किया गया है, ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियां रुकी रहती थीं जब तक रेलवे की गाड़ियां गुजर नहीं जाती थीं, हमलोग रोड पर जाम में फंसे रहते थे इसलिए हमारी एन0डी0ए0 की सरकार ने रेलवे आर0ओ0बी0 का निर्माण करवाया है । रेलवे समपारों के उन्मूलन की भी व्यवस्था हो रही है कि अधिक से अधिक समपार को हटाकर के उसकी जगह ओवरब्रिज का निर्माण किया जाय और भी काम हुआ है । महोदया, पथ को सुगम बनाने के लिए, पटना आसानी से पहुंचने के लिए बिहार के प्रमुख नदियों में बृहद पुलों का निर्माण भी हुआ है और कुछ योजना भी है । जैसे हम एग्जाम्ल में ले सकते हैं, राज्य में गंगा पर पूर्व से 5 पुल निर्मित हैं, आप जानते हैं बक्सर, आरा, छपरा, दीघा, सोनपुर, महात्मा गांधी सेतु, मोकामा रेल सह सड़क पुल, मुंगेर–भागलपुर–विक्रमशिला पुल ये सब पहले से निर्मित हैं, गंगा नदी पर और भी योजना है, 9 पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । सोन नदी में भी 5 पुल पूर्व से निर्मित हैं, दो पुल का निर्माण शीघ्र करवाया जायेगा, उसी प्रकार गंडक नदी के चलते भी आवागमन में परेशानी होती है, हमारे नीतीश कुमार जी ने, एन0डी0ए0 की सरकार ने तय किया है कि गंडक नदी में पहले से जो 7 पुल पूर्व निर्मित हैं और 4 पुलों के निर्माण का कार्य भी बहुत तेजी से हो रहा है, वह भी बहुत जल्दी पूरा हो जायेगा । उसी तरह कोसी नदी में 4 पुल पूर्व से निर्मित हैं, दो पुल का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है । जे0पी0 गंगा पथ कार्य

में तेजी हो रही है, अब तक कुल 25 बाइपास की स्वीकृति हुई है । जिसके चलते...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आप अपनी बातों को संक्षिप्त करें, आपका समय दो मिनट बचा हुआ है ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदया, दो मिनट का समय बहुत है मेरे लिए ।

महोदया, हमने बताया कि भविष्य की क्या परियोजना है, किस तरह से हम चार घंटे में पटना पहुंचेंगे इसकी बात की है । अब कुछ पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी से हमारा डिमांड है कि भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड, दासपुर पंचायत के आंध्री नदी में शेखपुरा एवं वैद्यनाथपुर के बीच यातायात पुल के निर्माण की आवश्यकता है, मंत्री जी इस पर कृपया ध्यान रखें । सुल्तानगंज प्रखंड में प्रस्तावित ग्रिन फील्ड हवाई अड्डा के पश्चिम फोरलेन से मंझली गांव तक, मंझली बांध पर पी0सी0 सड़क का निर्माण कराया जाय । गंगा रिवर फ्रंट का काम अभी बंद है, उसको तुरन्त चालू कराया जाय । मंत्री महोदय, शाहकुंड में पी0डब्ल्यू0डी0 का एक अतिथि गृह है जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है और उसको अतिक्रमित किया हुआ है उसको कृपया चालू कराया जाय । अंत में मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि तारापुर विधान सभा होकर भी हमलोग आते हैं, गंगटा से मुंगेर सीमा तक 333 एन0एच0 जो सिंग्ल रोड है, जमुई सीमा में रोड चौड़ी है, वहां पर आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और प्रतिदिन दुर्घटना होती है ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है । श्री राजेश कुमार जी, आप अपना पक्ष रखें ।

श्री ललित कुमार मंडल : महोदया, एक मिनट का समय दिया जाय ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार जी अपना पक्ष रखें ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदया, सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण का प्रमाण मिला है, जिस कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री राजेश कुमार : महोदया, सबसे पहले मैं अपना प्रॉब्लम पहले रख देता हूं, चूंकि बाद में पता नहीं समय मिलेगा या नहीं और बाद में हमारे सत्तापक्ष के लोग बोलने देंगे

या नहीं बोलने देंगे, चूंकि यह परम्परा बन चुकी है लोकसभा से लेकर यहां तक । माननीय सभापति महोदया, मैंने दिनांक–25.10.2024 को एक प्रस्ताव भेजा था, आर0डब्ल्यू0डी0 का रोड है वह आर0सी0डी0 में शामिल करने के लिए । मैं एन0एच0 139 संडा से कुटुम्बा पथ, टंडवा रोड भाया अम्बा नबीनगर तुरता, बरीयावां माली से चरण तक, एन0एच0 139 रिसियप से सिमरा चोरहा देव अम्बा रोड, एन0एच0 139 घेउरा सिमरा लभरी अम्बा नबीनगर रोड तक । दूसरा एक आर0सी0डी0 के रोड के एलाइनमेंट पर कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत, महाराजगंज पंचायत के मानिकराज प्राथमिक विद्यालय महाराजगंज, वार्ड नं0–6 में अवस्थित मदरसा के पास यहां पर नाली निर्माण की नितांत आवश्यकता है । चौथा है कि पटना, औरंगाबाद, हरिहरंगज एन0एच0–139 फोन लेन बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार से आई थी जो पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में चली गयी है तो मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह पथ बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी नितांत आवश्यकता है कि यह फोरलेन बने । मैं इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था पर आता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1959 को पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने नागौर, राजस्थान से इसका शुभारंभ किया था और तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका सशक्तिकरण करने के लिए पंचायतों को बहुत ताकत दी और पंचायत में सत्ता हस्तांतरण का एक सशक्त हथियार जनता के बीच में दिया । संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ । तत्कालीन सरकार द्वारा 29 विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायतों का सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए संकल्प पत्र जारी कर ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिया गया । आज की सरकार में वर्ष 2012 के बाद से पंचायतों को दी गयी शक्तियों को प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण कटौती कर दी गयी है, जो महात्मा गांधी जी का सपना था यह कहीं न कहीं उस सपने को अवरुद्ध करने का निर्णय है ।

क्रमशः

टर्न–18 / यानपति / 07.03.2025

(क्रमशः)

श्री राजेश कुमार : महोदया, भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा 12.02.2025 को जारी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष–2013–14, से 2020,2021 और 2022 के बीच में ग्रामीण स्थानीय नियमों को, अंतराल में, बिहार राष्ट्रीय सूचकांक में 18वें नंबर पर होगा किंतु खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ऐसा अब तक प्रतीत नहीं हो रहा । सरकार के 29 विषयों में पंचायती राज संस्थानों का अधिकार प्रदान करने के लिए फिर से संकल्प जारी करना चाहिए ताकि हमारा पंचायत सशक्त हो । राज्य में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार फिर से पंचायतों को प्रदान करना चाहिए और पंचायत सचिव द्वारा जारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लागू करना चाहिए । राज्य में मुख्यमंत्री सोलर लाइट लगाने में व्यापक गड़बड़ियां हो रही हैं और उन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है । जो कंपनियां जहां से वह काम करती है, कब लगाती है, कब बत्ती जलाती है और कब खत्म हो जाता है इसकी कोई मॉनिटरिंग करनेवाला नहीं है । सोलर लाइट की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य में कोई भी लैब स्थापित नहीं है इसलिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है जिसकी मॉनिटरिंग उस लैब में हो सके । मनरेगा, ग्राम पंचायत का जो एक रीढ़ के समान है उसमें प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा पांच लाख से बढ़ाई जानी चाहिए चूंकि सारे मैटेरियलों के दाम बढ़े हैं और कोई भी योजना उसमें जब ली जाती है तब यह राशि कम पड़ती है, अभाव होता है और पूर्ण कार्य कराने में अभाव पड़ता है, इसलिए पांच लाख की राशि जो है उसको बढ़ाना चाहिए । 15वीं और 6ठी वित्त आयोग की सामग्री क्रय का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए । इसी संदर्भ की कड़ी में राज्य के ग्राम पंचायतों में स्थित पंचायत सरकार भवनों में राजस्व कर्मचारियों और कृषि कर्मचारियों को निश्चित तिथि पर उपस्थिति रहने की व्यवस्था करनी चाहिए । आज के समय में यह बराबर देखा गया है कि कई जगह पंचायतों पर उनके प्रभार में रहने के कारण वह एक जगह अपने गंतव्य पर नहीं रहते हैं और कई बार जनता जब जाती है तो उनको कहा जाता है कि वह अमुक पंचायत में हैं और मिलते कहीं

नहीं हैं । मैं पुनः पथ निर्माण विभाग की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । महोदया, जब पथ निर्माण की बात आती है तो कई ऐसी विसंगतियां हैं जो यहां दूर करने की आवश्यकता है । वर्ष–2005 में देश के कुल एन0एच0 में राज्य की हिस्सेदारी 5.4 फीसदी ही थी जो अब घटकर 4.4 फीसदी हो गई है । हम कितना ही ढिंढोरा पीट लें लेकिन हमारी जो औसतन हिस्सेदारी है, केंद्र सरकार से जो राज्य को हिस्सेदारी मिलती है उसमें हमारे बिहार की हिस्सेदारी घटी है इसलिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस हिस्सेदारी को बढ़ाया जाय । सदन में बैठकर ढोल पीटने से और केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होनेवाला है । हम सब का जनता के प्रति दायित्व है और सरकार का जनता के प्रति दायित्व है । देश के एक लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत 11 कि0मी0 है जबकि राज्य को मात्र 5.2 कि0मी0 ही मिल रहा है, इसको देखने और समझने की आवश्यकता है । राज्य में 3782 कि0मी0 राजमार्ग सिर्फ दो लेन के हैं इसपर भी सरकार जितना ढिंढोरा पीट ले लेकिन यह हमको आईना आंकड़ा दिखाती है । राज्य में 23 सड़कों की योजनाएं जमीन के अभाव में लंबित हैं । 23 ऐसी योजना है जो अबतक जमीन का अधिग्रहण या मुआवजा की राशि दिए बगैर यह लटकी हुई है, अधर में लटकी हुई है, यह सरकार के संज्ञान में कभी नहीं आई है । राज्य में एन0एच0 की 43 परियोजनाओं में से अभीतक केंद्र सरकार द्वारा 9 की ही स्वीकृति मिली है । केंद्र सरकार से बार–बार आ रहा है कि हमलोागें को हिस्सेदारी बहुत मिल रही है तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं । अंत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज्य अभियान और आर0जी0एस0ए0 औरंगाबाद जिलांतर्गत 13261 जन प्रतिनिधियों और पंचायत राज कर्मियों का प्रशिक्षण निर्धारित है जिसमें से 7685 जनप्रतिनिधियों को ही प्रशिक्षण दिया गया है, शेष 6576, अभी भी इनका प्रशिक्षण लंबित है औरंगाबाद जिले में । पथ निर्माण में हाल की समीक्षा बैठक में हमलोगों ने पाया कि बारूण बाइपास पथ नए बाजार से एन0एच0–2 भाया धनकी, गजरा पथ निर्माण हेतु 3.40 कि0मी0 जो अनापत्ति के लिए लंबित है । दूसरा है उत्तर कोयल नहर बराज हॉल से एन0एच0–2 वाया महीबिगहा, रामनगर, सिमरी, गोरियाडीह, परसा, गनेसमारा, कनकोरा, खेरा, लोपरिया नाई में पथ निर्माण के

अलाइनमेंट में पड़नेवाले 6 कि0मी0 लगभग हस्तांतरण के लिए प्रत्याशा में है । पथ का चैलेंज 19 कि0मी0 जो है, उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में है और जितना भी बताए हैं इसमें केवल बिहार सरकार को, पथ निर्माण विभाग को, अनापत्ति के अभाव में यह रोड नहीं बन रहा है तो मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इन सारे पथों को अनापत्ति प्रदान की जाय । जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था में हमने कहा कि जब हमलोग यह सारे सपने देख रहे थे बापू, तो सत्ता का हस्तांतरण गांव में होना था लेकिन आज गांव में यह भी देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार पंचायती राज व्यवस्था है और उस पंचायती राज व्यवस्था में कई ऐसी योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार का शिकार हो गए हैं । खासकर के मनरेगा में, जो गारंटी देता है लोगों को, आज कई जगह पाया गया है कि कच्चे वर्क को मशीनी वर्क से किया जाता है और इसका कोई अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है यह देखने की आवश्यकता है । अंत में मैं दो बातें, आवास का अभी सर्वे हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का । सर्वेक्षण में आपके आवास सहायक जो हैं, 2–2 हजार रुपया और प्रखंड विकास पदाधिकारी और सारे आवास जो हैं यह सब मिलीभगत है और वैसे–वैसे लोग का सर्वे कर रहे हैं जिनके पॉकेट में दो हजार रुपया नहीं है और जिनके पास दो हजार रुपया है उनका आवास बनाएं । यह हमारा दावा है, माननीय मंत्री जी सदन में, कि आप इसकी जांच कराइये । यदि सही मायने में आप गरीब के हितैषी हैं तो इसपर आपकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए । अनुसूचित जाति/जनजाति और छोटी जातियां जितनी भी हैं उनको कभी–भी यह आवास मिलने को नहीं है ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, अब समाप्त किया जाय ।

श्री राजेश कुमार : जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे......

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, अब आपका समय पूरा हो गया, समाप्त किया जाय ।

श्री राजेश कुमार : तो प्रत्येक पंचायत में 250 से 300 आवास आते थे ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्या, सुश्री श्रेयसी सिंह जी ।

श्री राजेश कुमार : लेकिन आज एक तो संख्या घट गई और ऊपर से लूट हो रही है इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

टर्न–19 / अंजली / 07.03.2025

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय सभापति महोदया, आज आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं । साथ ही साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय द्वय उपमुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्य सचेतक जी का भी धन्यवाद देती हूं । मैं जमुई की जनता को कोटि–कोटि प्रणाम करती हूं और आभार प्रकट करती हूं कि अपना जनप्रतिनिधि चुनकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आज इस सदन में उनकी आवाज बनकर बिहार सरकार के पक्ष में माननीय मंत्री जी का जो अनुदान राशि की मांग है, उस बजट के समर्थन में बोल सकूं, लेकिन उससे पहले सभापति महोदया, कहीं न कहीं मन बहुत दुखी हो जाता है आज जब मैं सुनती है कि विपक्ष द्वारा ब्रिटिश राज की तारीफ की जाती है । मुझे याद है जब हमलोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें हमें पढ़ाया गया था कि महात्मा गांधी अपने गुरू गोखले से महाराष्ट्र में आशीर्वाद लेकर वे आए थे और बिहार की ऊर्जावान धरती यानी कि चंपारण की धरती से ये ब्रिटिश राज से लड़ाई शुरू की थी और आज उसी बिहार की धरती पर, उसी लोकतंत्र के मंदिर में उपस्थित विपक्ष के साथी, ब्रिटिश राज की तारीफ करते हैं यह कहीं से भी सराहनीय नहीं है । मैं आपसे आग्रह करती हूं, मैं आप लोगों से और सभी लोगों से यह आग्रह करती हूं कि पक्ष–विपक्ष की इस लड़ाई में, यह मेरा है, यह तेरा है कि लड़ाई में यह मत भूलिए कि–

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

साथियों, हम सभी एक वृक्ष के, एक परिवार के लोग हैं और हम सभी का सपना वही स्वर्णिम सपना है जो कि विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना है । साथियों, आज माननीय मंत्री जी ने पथ निर्माण के अनुदान राशि की जो मांग की है मैं उसका समर्थन करती हूं । अक्सर हम सुनते हैं कि विपक्ष विशेष राज्य या विशेष पैकेज की बात करता है । हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के बजट के प्रत्यक्ष तौर पर बिहार में मिले 59 हजार करोड़

का प्रावधान किया गया है लेकिन विभिन्न योजनाओं के मद को यदि हम सब जोड़ें तो आवंटित राशि राज्य के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है । सड़क संपर्क राज्यों और देशों दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है । वे माल यानी कि गुड्स सेवाओं यानी कि सर्विसेज और लोगों के सुचारू आवाजाही को सक्षम बनाते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, कुशल सड़क के ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंच को बेहतर बनाती है, जिससे कृषि और पर्यटन को उद्योग को बढ़ावा मिलता है । अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को पहुंचाने में बढ़ोतरी मिलती है । आखिरकार मजबूत सड़क, बुनियादी ढांचा, राष्ट्र प्रगति और समृद्धि को भी बढ़ावा देने की एक कुंजी है । पटना से पूर्णियां एक्सप्रेस–वे और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस–वे के निर्माण पर कुल 26 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे साथ ही, केंद्र सरकार बक्सर में गंगा नदी पर डबल लेन का एक और पुल बनाएगी ।

सभापति महोदया, यह किसी से भी बात छिपी हुई नहीं है कि एक जमाना था, एक समय था जब हम लोगों को पटना से जमुई आने में 5 से अधिक घंटे लग जाते थे लेकिन आज जिस तरह से फोर लेनिंग का काम, सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, हमलोग पटना से जमुई जाने में सिर्फ तीन घंटा लगता है और इसी तरह से बिहार के हरेक उस कोने में पहुंचने का समय धीरे–धीरे कटौती होते जा रही है और सड़कों का आधारभूत संरचनाओं का नव–निर्माण भी हो रहा है और विस्तारीकरण भी हो रहा है । विगत एक वर्ष में पथ निर्माण विभाग द्वारा कुल 90 योजना जिनकी कुल लागत राशि 4 हजार 826. 4 करोड़ रुपए की है उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है । इन योजनाओं में 23 अद्द कुल परियोजना जिसकी लागत 318.37 करोड़ है । 12 अद्द रेल ओवर ब्रिज परियोजना जिसकी लागत 718.8 करोड़ है । 50 अद्द सड़क परियोजना जिसकी लागत 848.96 करोड़ है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत 5 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी लागत 29.88 करोड़ सम्मिलित है ।

सभापति महोदया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की यह सोच है कि न्याय के साथ विकास करना है । सात निश्चय पार्ट–2 अंतर्गत सुलभ संपर्कता के अधीन राज्य के सभी शहरों और सघन बसावटों में होकर

गुजरने वाली मार्गों में आवश्यकतानुसार बाईपास पथ का निर्माण और फ्लाई ओवर का निर्माण की योजना के तहत अब तक कुल 25 बाईपास पथ का निर्माण की राशि 676.27 करोड़ का प्रावधान किया है । साथ ही साथ, सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान कुल 22 योजनाएं जिनकी लागत राशि 2 हजार 770.91 करोड़ की घोषणा भी की है ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, अपने बड़े भाई नीतीन नवीन जी से यह हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करती हूं कि जमुई में ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए जमुई में उपस्थित खैरमा से मनिअड्डा बाईपास का भी निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू कराएं । साथ ही, जमुई से लखीसराय पथ हंसडीह से आर0के0 होटल–घोड़ा अस्पताल– गिरीश टॉकीज होते हुए आई0टी0आई0 कॉलेज तक पथ निर्माण केंद्र सड़क निधि यानी कि सी0आर0आई0एफ0 से कराया जाय । साथियों, मैं सबको बता दूं कि सी0आई0आर0आई0एफ0 के फंड में कुल 12 योजनाएं स्वीकृत हैं जिसकी प्राप्त राशि 872.524 करोड़ है ।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को धन्यवाद देती हूं कि जब पथ निर्माण उनके पास था, उन्होंने जमुई में उपस्थित गिद्धौर से मांगोबंदर जाने वाली रोड की निविदा प्रक्रिया को पूरा कराया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष खत्म होते–होते गिद्धौर टू मांगोबंदर की रोड का काम भी जरूर शुरू हो जाएगा ।

सभापति महोदया, मेरे कार्यकाल में आर0सी0पी0एल0डब्लू0ई0ए0 योजना यानी कि Road Construction Plan for Left Wing Extreme Affected Area की योजना के तहत 27 किलोमीटर और 3 अद्द पुलों का निर्माण कार्य कराया गया था । इन तीन पुलों में सबसे महत्वपूर्ण पुल और जिसकी आशा जमुई की जनता पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रही थी वह पुल था सिकरिया पुल, मैं इस उदाहरण को आज इस सदन में सबके सामने इसलिए रखती हूं क्योंकि आर0सी0पी0एल0डब्लू0ई0ए0 योजना के तहत यह पुल भी बना और उस पुल के साथ–साथ जो जमुई शहर में एक बड़ी सरकारी भूखंड बची नहीं थी, शहर के विस्तार के लिए जगह की आवश्यकता थी, सिकरिया पुल के

निर्माण हो जाने से क्यूल नदी के पूर्व दिशा में काफी बड़ी सरकारी भूखंड से जमुई शहर को जोड़ा गया है । यही नहीं महोदया, वहां कई ऐसी सरकारी कार्यालय हैं और प्रतिष्ठान हैं जिनका निर्माण तेजी से चल रहा है तो शहर को फैलने की जगह भी मिली जो काफी जरूरी थी और साथ–साथ जिस ट्रैफिक जाम की मैं बात कह रही हूं वहां छोटी गाड़ियों को एक वैकल्पिक रास्ता भी आने–जाने का मिला । अभी हमारे माननीय सदस्य ऋषि जी बता रहे थे कि किस तरह से हमलोगों को पटना में घुसने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम लगता है, ट्रक का ट्रैफिक जाम लगता है । महोदया, आप और माननीय सभी सदस्य यह जानते हैं कि जिस सड़क पर ट्रैफिक जाम लगता है उसी का पैरेलल सड़क मरीन ड्राइव के नाम से उपस्थित है और वह आज के रूप में वह हम सभी लोगों के बीच में बनकर खड़ा है, हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं । मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करती हूं कि आप भी उस सुंदर सड़क का मजा उठाएं और उस सड़क को उपयोग में लाएं ।

(व्यवधान)

बिल्कुल, अगर सड़क अच्छी हो तो लौंग ड्राइव जाने में कोई शर्म की बात नहीं है, महोदया । मुझे लगता है कि सभी लोगों को साथ में जाना चाहिए। इस सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूं कि आर0सी0पी0एल0डब्लू0ई0ए0 योजना आपने धरातल पर उतारी है जिस योजना से बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का और राज्य में शांति व्यवस्था और समृद्धि कायम करने की काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । पथ निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड की ऋण योजनान्तर्गत अब तक 938.2649 करोड़ में कुल 41 परियोजनाएं जिसमें 15 पथ और 26 पुल उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति हमें मिली है ।

सभापति महोदया, समय का ध्यान रखते हुए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमारे लिए निजी रूप से हमारे दिल में एक बेहतरीन स्थान रखता है वह है खेल विभाग । महोदया, अभी माननीय सदस्य खेल पर चर्चा कर रहे थे मैं बता दूं आपके माध्यम से सदन को बता दूं कि बिहार खेल में लगातार आगे बढ़ रहा है । विधायक के रूप में पहले वर्ष में मुझसे पूछा गया था कि खेल

और खिलाड़ियों की क्या परिस्थिति है, क्या परेशानियां हैं ? मैंने उस वक्त भी सदन में कहा था और आज भी आत्मविश्वास के साथ कहती हूं कि बिहार में एन0डी0ए0 सरकार जिस तरह से खेल को सम्मान दे रही है, खेल के आधारभूत संरचनाओं का विस्तारीकरण चल रहा है मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से सराहनीय है और साथ ही साथ, यह भी बता दूं कि हाल ही में अभी 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था । सभापति महोदया, मैं खुद बिहार का प्रतिनिधित्व शॉटगन में करती हूं और मैं भी वहां पर उपस्थित थी । पहली बार बिहार के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ 29वें पायदान पर आकर खड़ा किया था यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और यह ऐतिहासिक जीत सिर्फ अकेले बिहार के खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि बिहार के सरकार की है जिसने राज्य में स्पोर्ट्स को लेकर काम किया है, योजनाएं बनाई हैं, नए–नए आधारभूत संरचनाओं को धरातल पर उतारा है । (क्रमशः)

टर्न–20 / पुलकित / 07.03.2025

(क्रमशः)

सुश्री श्रेयसी सिंह : राजगीर में उपस्थित खेल यूनिवर्सिटी सह खेल अकादमी पूरे भारत में एक उद्धार के रूप में हम सब के सामने खड़ा हुआ है सभापति महोदया । हाल ही में हमलोगों ने विमेंस एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी का भी आयोजन किया था जो फलस्वरूप भारत की टीम ने जीता भी था । मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि खेल यूनिवर्सिटी और खेल अकादमी का काम कम्प्लीट हो चुका है, कुछ काम बाकी भी है और मैं उम्मीद भी करती हूं कि आने वाले समय में एशियन चैम्पियनशिप से भी बड़े–बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किये जायेंगे ।

सभापति महोदया, बिहार में हर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा द्वारा किया जाना है जो कि न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि वैसे खेल प्रेमी जो मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं या फिटनेस के लिए खेल खेलते हैं उनके लिए भी एक आशा की किरण बन रही है । 535 प्रखंड में कुल 5671 ग्राम पंचायत में 6659 खेल मैदान का निर्माण हो चुका है या कार्य प्रगति पर है और साथ ही साथ, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

(एफ0आई0सी0सी0आई0) है उसने 2024 में बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स का अवार्ड भी दिया है ।

माननीय सभापति महोदया, बिहार में जिस तरह से खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देती हूं खासतौर से खेल प्राधिकरण को बधाई देती हूं जिसने मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजना को धरातल पर उतारा है । खिलाड़ियों की एक बड़ी आबादी के लिए सुरक्षित जीवन–यापन करना सुनिश्चित करें । माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगी कि अबतक 71 खिलाड़ियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल चुका है ।

सभापति महोदया, आज विमंस डे का सेलिब्रेशन हमलोग कर रहे थे, आज सभी महिलाओं का बोलने का मौका भी मिला, हम भारतीय जनता पार्टी से आते भी हैं और सुषमा स्वराज जी को अपना आईकन भी मानते हैं । पार्लियामेंट में उन्होंने एक बात कही थी उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि तू इधर, उधर की बात न करिये, ये बता कि काफिला क्यों लूटा ? आज हम बिहार में खड़े हैं इसलिए बोलती हूं कि तू इधर, उधर की बात न कर, ये बता कि चारा घोटाला क्यों हुआ ? तू इधर, उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा ? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है । सभापति महोदया, मैं एक पेशेवर खिलाड़ी हूं, बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कर चुकी हूँ । माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक बहुप्रतीक्षित मांग....

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्या, आपका समय पूरा हो गया ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : सभापति महोदया, दो मिनट का समय दिया जाए । मैं खेल प्रेमी हूं इसलिए यह बात सदन में रखना अति आवश्यक है । माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी एक बहुप्रतीक्षित मांग थी कि बिहार राज्य में एक शूटिंग रेंज खासतौर से शॉटगन शूटिंग रेंज होना चाहिए और अपनी हाल की प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शॉटगन शूटिंग रेंज को जमुई में बनाने की घोषणा भी की है और निर्णय भी लिया है । आज सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अपने हाथ जोड़कर विन्रम आग्रह करती हूँ, माननीय खेल मंत्री जी जमुई स्थित सोनपे गांव में जो खेलो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था ।

उसकी जमीन की नापी होकर विभाग को भेज दी गयी है । कृपया करके इसको यथाशीघ्र निविदा प्रक्रिया में डाला जाए और इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाए । सभापति महोदया, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मांग का समर्थन करती हूं और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं माननीय पयर्टन मंत्री जी को भी बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने पतनेश्वर धाम के लिए नौ करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि हमें आवंटित की है । जमुईवासी इससे काफी खुश है और आपका धन्यवाद मुझे खासतौर से बोलने के लिए बोला गया है । बहुत–बहुत धन्यवाद । जय हिन्द । जय बिहार । जय भारत ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी, अपना पक्ष रखें । आपका समय आठ मिनट है ।

श्री गोपाल रविदास : सभापति महोदया, आज पांच–छह विधेयक पर वाद–विवाद है लेकिन बातचीत सिर्फ पथ निर्माण विभाग पर ही होगी । बाकी विषयों को गिलोटीन में डाल दिया गया है । महोदया, आप सब जानते हैं कि एस0सी0 / एस0टी0 एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन चर्चा से बाहर रखा गया है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय को गिलोटीन में रखना, न रखना यह बता रहा है कि सरकार बिल्कुल भी इस विषय पर गंभीर नहीं है । लेकिन मैं इसी विषय पर अपनी बात रखूंगा उम्मीद है कि सरकार मेरी बातों का संज्ञान लेते हुए जरूर जवाब देगी । माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति के जरूर ध्यान दीजिएगा । महोदया, मैं स्वयं अनुसूचित जाति से आता हूँ । मुझसे बेहतर इस विषय के बारे में, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई जानते होंगे । महोदया, समाज की बात तो मैं बाद में करूंगा सबसे पहले मैं अपनी बीती हुई बात करता हूं । इसी 26 जनवरी के बारे में बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय को भी मैंने संज्ञान में दिया है और बिहार के तमाम माननीय सदस्य अखबार के माध्यम से भी जाने होंगे । फुलवारी शरीफ के कुरथौल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मैं वहां नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करने गया । आप जैसा जानते हैं कि समाज के जो वर्चस्वशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं । महोदया, सदियों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, गरीबों को दबाने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है । कुरथौल विद्यालय में पहले से जो तथाकथित हैं एक दल विशेषकर संरक्षित हैं, उसमें सभी

लोग गुंडे हैं, उन्होंने हमारी जाति का नाम लेते हुए कहा कि चमार, दुसाध से उद्‌घाटन नहीं करायेंगे और हमको अपमानित करने का काम किया गया, जिसका एक एफ0आई0आर0 भी किया गया है लेकिन ताजुब्ब होता है जो डबल इंजन की सरकार लगातार दलितों, गरीबों की रहनुमाई की बात करती है लेकिन अभी तक इतने दिन घटना के बाद भी, सब जानते हैं कि बिहार विधान सभा ने हमको फुलवारी विधान सभा के तमाम विद्यालयों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, एक अध्यक्ष की हैसियत से जब मैं उद्‌घाटन करने जाता हूं तो वहां के शोषणकारी, दमनकारी लोगों ने अपमानित करते हुए हमको भगाने का काम किया और एफ0आई0आर0 होने के बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है । जबकि लिखित तौर पर अध्यक्ष महोदय को और सचिव को दिया गया है अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, यह ताजुब्ब की बात है । महोदया, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और जदयू वाले कहते हुए दलितों की रहनुमाई का काम करते हैं ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य विषय पर बोला जाए ।

श्री गोपाल रविदास : सभापति महोदया, विषय पर, बजट पर ही बोल रहा हूं । विषय है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है । इस विषय पर मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसी समाज से मैं आता हूं, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है । एक बार जुल्म नहीं हुआ है लगातार 1986 से लेकर अभी 2024–25 में भी घटनाएं घटी है । यह संज्ञान हम समझते हैं कि महोदया, इस आसन को लेना चाहिए ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा ।

श्री गोपाल रविदास : पूरे विधान सभा को लेना चाहिए । महोदया, आपने हमको नियुक्त किया है, किसलिए नियुक्त किया है । आपने हमको अध्यक्ष किसलिए नियुक्त किया है, बिहार विधान सभा का सदस्य नियुक्त किया है, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा हमको नियुक्ति मिली है और हमें विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होने के नाते, आप सभी लोग भी कहीं न कहीं अध्यक्ष हैं, उनका अपमान है । सिर्फ मेरा गोपाल रविदास का अपमान नहीं है, पूरे विधान सभा को शर्मसार करने का काम किया है । इस पर संज्ञान तत्काल लेना चाहिए और तमाम अपराधियों को, पेशेवर अपराधी है, एक–दो घटना में नहीं मैं बताना चाहूंगा कि लगातार

आठ घटना उसके ऊपर है । महोदया, लगातार वह पेशेवर अपराधी है, उस अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए । महोदया, आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इस डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में लगातार मध्य बिहार के अंदर में, आप चले जाइये गया के टिकारी में जहां पर सज्जन मांझी को मजदूरी मांगने पर उनके हाथ काट दिये गये, संजय मांझी की बर्बर पिटाई कर हत्या कर दी गयी । नवादा के इलाके में जहां दलितों को सरेआम भूमि सर्वे के नाम पर जला दिया गया 38 घरों को और अभी तक सरकार उस पर हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है । सरकार से लगातार वहां के लोग लड़ रहे हैं । गरीब, दलित, अनुसूचित जाति के लोग लड़ रहे हैं । अभी तक सरकार ने उनको पर्चा देने का काम नहीं किया है और लगातार सरकार दुहाई देती है कि इतने गरीबों को हम बसाने का काम कर रही है । महोदया, लगातार घटनाएं घट रही है । मैं बताना चाहता हूं कि पूरे सम्पूर्ण बिहार में लगातार घटनाएं दलित उत्पीड़न की घट रही है । पटना जिला में आपने देखा होगा कि 2024 में ही दो–दो मांझी जाति की लड़कियों के साथ सरेआम बलात्कार करने का काम किया गया, पटना में ही गोपालपुर में लगातार हत्याएं हुई हैं, लड़कियों को अपमानित किया गया है ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / अभिनीत / 07.03.2025

..क्रमशः..

श्री गोपाल रविदास : कल महिला दिवस है और सरकार की तरफ से घोषणा की गयी है कि विशेष अवसर दिया जायेगा । महिलाओं को कहा जा रहा है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया । अब समाप्त करें ।

श्री गोपाल रविदास : सरकार कहती है, ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' की बात करती है लेकिन पूरे बिहार के अंदर में दलितों की लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ लगातार बर्बर बलात्कार हो रहे हैं । यहां तक कि हमारे जो भाई हैं, जो शिक्षक हैं, जो छपरा, सीवान में मोछ रखने पर पासवान जाति के लोगों को गोली मार देने का काम किया सामंतवादी अपराधियों ने, लगातार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं ।

हम समझते हैं कि इस पर पूरे सदन को संज्ञान लेना चाहिए और खासकर अध्यक्ष महोदया से निवेदन है कि ऐसे समय में हो रहे हैं, दो–दो हमारे केन्द्रीय मंत्री, शर्म नहीं लगती है कि आपके इलाके में, गर्व से कहते हैं कि भारत सरकार में हम मंत्री हैं, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं और वहां पर गया और टेकारी के अंदर लगातार मांझी समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं । लगातार वहां पर महिलाओं का उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है । मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी संख्या 20.68 प्रतिशत है । अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया 20.68 प्रतिशत है, जिसमें मामूली 1.82 प्रतिशत जो है रुपये पूरे डाटा में दिया गया है बजट का वह..

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार जी अपना पक्ष रखें । आपका समय तीन मिनट है ।

श्री अनिल कुमार : माननीय सभापति महोदया, मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बजट बदलते बिहार का है जिसमें भ्रटाचार की नहीं बल्कि विकास की चर्चा है । इसके जमीन पर उतरते ही प्रदेश के विकास की गति तेज होगी और इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा । 2005 ये पहले जहां कागज पर विकास की बातें हुआ करती थी वहीं प्रदेश में माननीय नीतीश कुमार जी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर विकास के काम हो रहे हैं इसका आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है । एनडीए की सरकार बिहार के दूर–दराज क्षेत्रों से राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य 5 घंटे की जगह 4 घंटे पर काम कर रही है । इससे पहले हमारी सरकार बिहार के दूर–दराज क्षेत्रों से पटना पहुंचने के लक्ष्य को 5 घंटे रखी थी । सरकार अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए घटाकर 4 घंटे कर दी है । वर्ष 2027 को इसके परिणाम दिखने लगेंगे । इस पर प्रदेश की एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि इससे पहले पथ निर्माण विभाग का मतलब होता था अलकतरा घोटाला । तब कागज पर पक्की सड़कें हुआ करती थी और जमीन पर सड़कों की क्या हाल थी यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । एनडीए सरकार में पथ निर्माण विभाग की ओर से हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का

निर्माण, राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई बढ़ाना, सड़कों के अवरोधों को दूर करने , रेलवे आर0ओ0बी0 का निर्माण करना, प्रमुख नदियों पर पुलों का निर्माण कराया जा रहा है । पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जल्दी पहुंचने के लिए उत्तर बिहार में पूरब–पश्चिम गलियारा का निर्माण और इस सफर को कम करने के लिए यहां पर एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जा रहा है । इसके तहत पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना–बेतिया का फोर लेन, इसी प्रकार दक्षिण बिहार में पूर्व से पश्चिम जाने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड । हमारी सरकार में बक्सर, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर मिर्जा चौकी फोर लेन पथ पर काम चल रहा है । इसके बनने से पटना, पूर्णिया और बक्सर से पटना की दूरी तय करने में 2005 से पहले कई घंटे लगते थे लेकिन अब मात्र पांच घंटे में पूरा कर लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त भी कई सड़कों पर काम चल रहा है । बिहार की प्रमुख नदियों पर पुल के निर्माण का काम चल रहा है । सिर्फ गंगा पर सात पुल बनकर तैयार हो गये हैं जबकि नौ पर निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसी प्रकार सोन नदी पर पांच पुल बनकर तैयार हो गये हैं, दो बन रहे हैं । गंडक नदी पर सात पुल बने हैं जबकि चार पर काम चल रहे हैं जिसका सीधा लाभ अब बिहार की जनता को मिलने लगा है । जनता कहने लगी है कि बिहार बदल गया है । माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना काम हुआ है, एनडीए के इस प्रयास से बिहार के दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब चार घंटे में पटना सफर कर रहे हैं । सरकार में गुणवत्ता का पूरा ख्याल है, पूरे प्रदेश में पथ निर्माण विभाग से सैकड़ों बड़े पुल, हाजारों रोड बनाकर प्रखंड, जिला एवं राजधानी से जोड़ा गया है ।..

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : अब आपका समय समाप्त होता है ।

श्री अनिल कुमार : बिहार के करीब–करीब सभी शहरों में बाईपास बनाकर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाया गया है । हम माननीय महोदय से एक आग्रह करेंगे कि पथ निर्माण विभाग से संबंधित टिकारी विधान सभा अंतर्गत कुछ ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं । गया से औरंगाबाद जाने वाले पथ का चौड़ीकरण करवाकर डिवाईडर दिया जाय । उस पर..

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी): माननीय सदस्य डॉ0 सत्येन्द्र यादव जी, अपनी बात रखें । आपका समय दो मिनट है ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदया, आज एस0सी0, एस0टी0 के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं । आप जानते हैं कि पिछले पांच से सात वर्षों के अंदर जो एस0सी0, एस0टी0 जाति के लोग हैं, जो ताड़ी उतारने का काम करते थे, हमारे क्षेत्र या बिहार के अंदर जब से शराब बंदी हुई है, ताड़ी उतारने वाले दुसाध और चौधरी जाति के लोगों को, पासी जाति के लोगों को आये दिन पुलिसिया जुल्म का शिकार होना पड़ता है । हमारे मांझी विधान सभा के अंदर दर्जनों गांव पोकरविंडा, कोठया, चैनपुर, शीतलपुर, अरियाव और दूसरे कई गांवों में आये दिन ताड़ी उतारने के नाम पर झंझट होता है, मार–पीट होती है और दलित जाति की महिलाओं को पुलिस सरेआम उठाकर जेल के अंदर बंद कर रही है । शराब की खेप बलिया से सीधे नव सामंती लोग बड़े पैमाने पर लाते हैं और उन सामंती लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है । पुलिस दलितों पर अत्याचार करती है । यह सरकार जो है दलितों के उपर कहर बनकर आयी है, आफत बनकर आयी है । सामंती शक्तियों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय दलित जातियों पर, पिछड़ी दलित जातियों पर पुलिसिया जुल्म होते हैं । आज उस जुल्म का नतीजा है कि हजारों मुकदमें उन गांवों पर लाद दिए गये हैं और वहां के लोग कचहरी का चक्कर काट रहे हैं । यह है इस सरकार की मंशा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास की बात करती है लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है । उनको जेल के शिंकजों के अंदर जाना पड़ता है । अम्बेदकर मिशन के तहत जो अम्बेदकर भवन बनाना था, बिहार के अंदर जितनी राशि गयी अम्बेदकर भवन नहीं बना । मैं कहना चाहता हूं कि दलितों के विकास के लिए, जो दलितों को आरक्षण 65 प्रतिशत...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ । समाप्त किया जाय ।

माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान जी, अपनी बात रखें । आपका समय दो मिनट है ।

श्री सूर्यकांत पासवान : सभापति महोदया, मैं बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदया, पंचायती राज व्यवस्था को स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था, सपना सजाया था कि पंचायत को गांव के लोगों को सुपूर्द किया जाय

लेकिन आज पंचायत का क्या हाल है । पंचायत के जनप्रतिनिधियों को मान–सम्मान नहीं मिलता है । आज मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य जितने भी हैं वे पदाधिकारियों के चंगुल में चले गये हैं । आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है, अफसरसाही हाबी है । जनप्रतिनिधियों का मानदेय लंबित है और उनके जितने भी अधिकार थे उसमें कटौती की गयी है । उनका स्तर पहले की तरह, पंचयात सचिवों के माध्यम से कबीर अंत्योष्टि की राशि एक महत्वपूर्ण सरकार की योजना थी उसको सरल किया जाय । आज अनुसूचित जाति के जितने भी लोग है बिहार में सुरक्षित नहीं हैं । सरेआम उनकी हत्या हो रही है और उनके बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । आज पर्यटन की बात, बेगूसराय जिला में पर्यटन स्थल की असीम संभावनाएं हैं । काबर एशिया महादेश का सबसे मीठे जल की झील है, वहां पर्यटन की असीम संभावना है । अगर बिहार की सरकार उसे पर्यटन स्थल घोषित करती है, बनाती है तो बिहार की सरकार को राजस्व भी उपलब्ध होगा और वहां से बेरोजगारी भी लोगों की दूर होगी । बखरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर 12 मंदिरों की घेराबंदी का प्रस्ताव था जिसमें एक भगनु साह ठाकुरबाड़ी की घेराबंदी छूट गयी । महोदया, उसको भी शामिल किया जाय ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी)ः आपका समय समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान । आपका समय एक मिनट है ।

टर्न–22 / हेमन्त / 07.03.2025

श्री अखतरूल ईमान : महोदया, मैं कटौती प्रस्ताव पर खड़ा हुआ हूं, बोलने के लिए, सरकार को मशवरा देने के लिए । हरिजन की सरकार को मशवरा देना कौए को कालिख लगाने के बराबर है । महोदया, मैं मशवरा देना चाहता हूं कि इस वक्त आर0सी0डी0 की रकम घटा दी गयी है, जबकि बजट का साइज बड़ा है । इसके मायने सरकार के सामने कोई विजन नहीं है कि गांव की ग्रामीण सड़कों को आर0सी0डी0 में लिया जाय । मैं मुतालबा करता हूं कि मेरे क्षेत्र में मात्र 15 किमी सड़क है । इसलिए वहां पर फकीर टोली से अंगर वाया खाड़ी, बौलान, टपोच,

अभयपुर से लेकर हाई लेवल ब्रिज तक उसको पी0डब्ल्यू0डी0 में लिया जाय । दूसरा, गेरिया टू कस्बा पथ वाया बरबट्टा, रसैली को भी पी0डब्ल्यू0डी0 में लिया जाय । महोदया, झील माट का जो काम है उस पर रोक लगायी जाय । पंचायत राज के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं मुखिया हों, समिति के सदस्य हों, पंच हों इन तमाम लोगों की संख्या चेयरमेन से लेकर मेम्बर तक 25 से 5 हजार तक उनका मानदेय किया जाय और साथ ही न्यायमित्र की भी तनख्वाह बढ़ायी जाय । मैं चाहूंगा कि खेल का मैदान पंचायत 10 किमी लंबा है । एक खेल के मैदान से हमारे बच्चे खेल नहीं सकते, मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं । इसलिए कम–से–कम एक एकड़ का खेल का मैदान वहां पर तैयार किया जाय ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदया, एक आपत्ति है कि अनुसूचित जाति के एक विधायक पर अत्याचार हो रहा है, सदन खामोश है और वह एक विधायक हैं और उनके साथ यह हो रहा है।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

गिरफ्तारी नहीं हो रही है यह खेद का विषय है । कानून का उल्लंघन है । संविधान में जो एस0सी0, एस0टी0 को जो हक दिया है,

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री अखतरूल ईमान : अगर 75 सालों के बाद भी नहीं दिया जा सकता है, तो यह आपत्तिजनक है ।

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार । आपका समय बाईस मिनट है ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब गुरबे के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और मखदूमपुर की महान जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं ।

महोदय, अनुसूचित जाति का भी पूरक बजट आज उसके साथ है । यह पांचवा बजट हमने देखा है । महोदय, अनुसूचित जाति के जो मंत्री होते हैं, जिस दिन उनका बजट होता है उनको आगे की रॉ में नहीं बैठाया जाता है ।

यह कैसा भेदभाव है। कम–से–कम जिस दिन अनुसूचित जाति का बजट हो उस दिन तो उनको सम्मान दिया जाय कि भई आपका बजट है आप आगे आकर बैठ जाइये । तो यह सरकार की मंशा दिखाता है कि अनुसूचित जाति के प्रति उनका क्या नजरिया है । आज बिहार में एक तकिया कलाम बन गया है कि ''2005 के पहले बिहार में क्या था, कुछ था जी।'' एक तकिया कलाम बन गया । हम 2005 के पहले बिहार को लेकर जाना चाहते हैं और इसकी शुरूआत हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक लाईन से कहना चाहते हैं कि ''समानता एक कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको वास्तविकता में बदलना चाहिए ।'' यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि समानता, आज आप माननीय बन जाइये, इस देश के राष्ट्रपति बन जाइये, इस देश के उप प्रधानमंत्री बन जाइये, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाइये, लेकिन आप अनुसूचित जाति हैं यह आपको बार–बार एहसास कराया जाता है । आपको यह एहसास कराया जाता है कि इस मनुवादी व्यवस्था में 6743 जाति में आपकी पोजिशन क्या है, यह आपको बताया जाता है । महोदय, यह हम कहना चाहते हैं, आज हम अपनी पीड़ा बयां करने आये हैं कि–

''पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं,
हमारे बच्चे भूखे पेट जोर–जोर चिल्लाते हैं ।''

यह स्थिति इस देश की है महोदय और यह स्थिति आज से नहीं है । यदि हम इसकी चर्चा करें, तो आज हम लेकर आये हैं ''हिन्दू लॉ बुक'' । यह मनुस्मृति, जिस किताब से हमारे धर्म को चलाने की कोशिश की जाती है । जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 दिसम्बर 1925 में जलाने का काम किया था । महोदय, यह जो मनुस्मृति है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पढ़ाने की इजाजत दी है । हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं । इसमें पेज नम्बर 273 पर लिखा है जो शुद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे, तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर उसे देश से निकलवा दे । पेज नम्बर 271 पर लिखता है कि शुद्र यदि जातियों से कठोर वचन कहे, तो उसे जिह्वाछेदन दण्ड दिया जायेगा, क्योंकि वह अधम है वह पैर से उत्पन्न हुआ है । महोदय, एक इसमें कहता है कि नाम और जाति लेकर यदि शुद्र द्वार से जातियों की निंदा करे, तो जलते

हुए दस अंगुली लोहे की सलाख उसके मुंह में डाली जाय । महोदय, क्या किसी कुत्ते को, किसी गधे को दस अंगुली लंबी लोहे की रॉड लाल करके डाला गया होगा। यह भारत के शुद्रों के बारे में एक धर्म विशेष में उनका स्थान है । इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ में इसको रेखांकित किया है । यदि भारत की व्यवस्था को समझना है, तो इस पांच खंड में जो भारत की व्यवस्था है उसको समझना होगा । वैदिक काल, जो 600ई0 पूर्व के पहले का काल है, बौद्धकाल, जो 600 से 1200 ई0 का काल है, मुस्लिम काल जिसको कह सकते हैं मध्यकाल, जो 1200 से 1800 ई0 का काल है, ब्रिटिशकाल, जो 1800 से 1947 और अब जो स्वतंत्रोत्तर काल जो अब चल रहा है जिसमें भारत का संविधान लागू हो गया, उस काल में हम जी रहे हैं । महोदय, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमने आज आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी । कांची इलैय्या की बुक है ''हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर'' उसमें दुनिया के बड़े सोशल साइंटिस्ट, डॉक्टर अंबेडकर के बाद वे गिने जाते हैं, उन्होंने साफ–साफ कहा कि इस देश में यह जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था, तो दलितों पर, शुद्रों पर थोपी गयी, इसमें अगर बुनियादी समझ विकसित करनी है, तो यह समझना चाहिए कि इस देश ने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनायी, लेकिन उसमें शौचालय नहीं बनाया । क्या बनाया, एक जात बनायी, डोम बनाया, मेहतर बनाया कि बाकी लोग मल–मूत्र करेंगे और यह सुबह उठकर हाथ से उठाकर, माथा पर उठाकर फेंकने का काम करेगा । महोदय, इस देश में वॉशिंग मशीन नहीं बनी, इस देश में वॉशरमैन बना कि हम जिंदगीभर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम धोबी हो, तुम्हारा काम जिंदगीभर धोना है ।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री की भी किताब लेकर आये हैं । महोदय, इस देश ने डॉक्टर नहीं बनाया, नर्सिंग होम नहीं बनाया, एक जात बनायी चमईन बनाया कि किसी के घर में डिलीवरी हो, तो बुलाओ चमइनिया को, उस चमईन को बुलाकर डिलीवरी करवाई गयी । इस देश में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किये, जूता

चप्पल नहीं बनाया, लेकिन हमने एक जात बनायी, चमार बनाया कि भई तुम्हारा काम जूता बनाना और जूता खाना है ।

(व्यवधान)

आपकी बारी आयेगी, आप अपनी बात करियेगा । महोदय, इस देश में सबको गहना पहनना है । सबको सोना चांदी का सामान पहनना है, बहुत कीमती लगता है, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनायी । एक जात सुनार बनायी । इस देश में सबको बर्तन चाहिए, लेकिन बर्तन की टेक्नोलॉजी नहीं बनायी, हमने कुम्हार एक जात बनायी, लेकिन उसके साथ हमने क्या व्यवहार किया । इस देश में हेयर कटिंग सर्जरी हमने विकसित नहीं की, हमने एक जात बनायी, नाई बनाया, ठाकुर बनाया कि तुम्हारा काम जीवन भर हमारा बाल और नाखून काटना है । यह है भारत की मनुवादी व्यवस्था । उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित आज लड़कर यहां तक पहुंचे हैं और आज हम अपने अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम–से–कम देर से ही सही, लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इस देश में सावित्री बाई फूले की पहचान होनी चाहिए और उन्होंने हर जिला में 100 बेड का सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास बनाने का एलान किया है। लेकिन क्या महोदय यह काफी है ।

(क्रमशः)

टर्न–23 / धिरेन्द्र / 07.03.2025

...क्रमशः...

श्री सतीश कुमार : महोदय, हम हरेक प्रखंड में कॉलेज, महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं और 100 बच्चियों के लिए हम जिला में आवासन की व्यवस्था कर रहे हैं। महोदय, यहाँ जात पूछ कर डेरा नहीं मिलता है, हम विधायक बन गए हमको तीन महीना तक कोई डेरा नहीं दिया तो जाकर अंतिम छोर पर हमको रहना पड़ा, यह सच्चाई है इस देश की । इसलिए महोदय, कम–से–कम ये जो सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है, इसका कम–से–कम एक हजार बेड का किया जाना चाहिए और 1962 से, 1956 से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास इस राज्य में है, अंबेडकर छात्रावास उसका नाम हो गया है

आज भी उसके सीट का एलॉटमेंट 200, 100, 500 जो बड़े जिला हैं यहाँ तक हो पाया है जबकि 05 हजार से ज्यादा फार्म, 10 हजार से ज्यादा फार्म एक जिले में आ रहे हैं तो क्या इसकी कैपसिटी नहीं बढ़ायी जानी चाहिए ? क्या उसको मल्टीस्टोरी बिल्डिंग नहीं बनायी जानी चाहिए ? क्या उसमें लिफ्ट लगा कर हम अनुसूचित जाति के बच्चों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में नहीं रख सकते हैं ? यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए । इसलिए हम कहना चाहते हैं, अभी स्पष्ट रूप से, ये तो हमने मनुवाद का दंश बताया लेकिन वर्ष 2007 में अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री लोग कहते हैं, उनका एक किताब प्रकाशित हुआ 'कर्मयोगी' । उस किताब को पढ़िये, आप तो जरूर पढ़िये, उस कर्मयोगी के बारे में श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने लिखा कि भारत में..... XXX

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह गलत उदाहरण मत पेश कीजिये, गलत उदाहरण मत पेश कीजिये । इसको प्रोसीडिंग से हटाइये ।

श्री सतीश कुमार : XXX

अध्यक्ष : नहीं, यह गलत है । बैठिये, यह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा । यह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, यह गलत उदाहरण है आपका ।

(व्यवधान जारी)

श्री सतीश कुमार : XXX

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रोसीडिंग में नहीं जा रहा है, वे गलत उदाहरण दे रहे हैं ।

श्री सतीश कुमार : XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रोसीडिंग में नहीं गया है, आपलोग बैठिये ।

XXX – आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, तब लालू यादव जी की भी किताब आपको जाकर पढ़नी चाहिए। लालू यादव जी की किताब जिसमें, जो लालू यादव जी का किताब है गोपालगंज से रायसीना, उस किताब को पढ़ना चाहिए, उस किताब में, उनकी आत्मकथा में

लिखा है कि जब वे बाढ़ के पुनपुन में गये तब वहाँ पर एक लक्ष्मीनिया जो दलित महिला उनसे मिली, उसके बाद लालू यादव जी का जीवन बदल गया, वे लक्ष्मीनिया बहुत धक्का खते हुए भीड़ को चीरते हुए उनके पास आना चाहती थी तब लालू यादव जी का नजर उन पर पड़ा और लालू यादव जी ने कहा कि उनको आने दो, जब वे लालू यादव के नजदीक आयी तो उसकी गोद में एक बच्चा था, थकी हारी कुपोषित महिला थी, उस बच्चे को लालू यादव जी ने अपनी गोद में लिया और पूछा कि क्या लक्ष्मीनिया तुम यहाँ, तो उन्होंने कहा कि लालू भईया, मेरी शादी यहीं पुनपुन में हो गयी है, यहीं हम रहते हैं तो बोलें लक्ष्मीनिया ये लो बच्चा को रखो और इस बच्चे को पढ़ाओ लेकिन जब लालू यादव लौट कर आयें और उन्होंने कहा कि हम उसके बच्चे को पढ़ाने की बात तो कह दिये लेकिन इस अछूत के बच्चे का नामांकन कहाँ होगा ? क्योंकि उस समय तक अछूत के बच्चों का नामांकन बड़ा मुश्किल था तब लालू यादव आते हैं और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं और 300 अछूतों को पढ़ाने के लिए 300 विद्यालय की घोषणा करते हैं । महोदय, ये है लालू यादव जी का विजन, ये है लालू यादव जी की सोच । इसलिए हम....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल 05 मिनट बचा हुआ है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, 05 मिनट काफी है ।

अध्यक्ष : आप अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोल लीजिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा कि राम मंदिर बन गया है, बहुत अच्छी बात है, विवाद खत्म हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, गीता हमने बनाया है महोदय, चौखट हमारे बढ़ी समाज ने बनाया, पत्थर किसी पत्थरकट्टी का चमार जो मूर्तिकार है उसने बनाया है, घंटा हमारे ठठेरा भाई ने बनाया और उसमें जो चढ़ने वाला दूध है वह ग्वाला के यहाँ से आता है और उसमें चढ़ने वाला जो फूल कोइरी–कुर्मी के खेत से आती है, माली तोड़कर लाता है, उसमें बजने वाला शंख जो है वह कोई मछुआरा भाई निकाल कर लेकर आया है लेकिन शर्म तब आती है महोदय, जब बनकर तैयार हो जाता है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लाया नहीं जाता है,

दु:ख तो तब होती है कि राष्ट्रपति भी होकर लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम आदिवासी हैं, दलित हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आराम से बोलिये, तनाव में मत बोलिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज यह जो बजट है, जीतन राम मांझी जी का तो जीभ काटा गया, हम तो कहेंगे कि महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा काटा गया और हम कहेंगे रामायण काल में शंबूक ऋषि की हत्या हुई और नीतीश जी के काल में जीतन राम मांझी जी का जीभ काटा गया, यह है नीतीश जी के सुशासन की सरकार । महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने विधान सभा के बारे में कुछ बोल सकते हैं तो बोल लीजिये।

श्री सतीश कुमार : महोदय, हमारे पास ज्यादातर जो अनुसूचित जाति के मंत्री यहाँ बैठे हैं, आज अनुसूचित जाति का 2022 का जो एन॰सी॰आर॰बी॰ का डाटा है कि 4500 से ज्यादा केस प्रत्येक साल बिहार में दर्ज होते हैं और प्रत्येक साल 10 प्रतिशत केस में इजाफा हो रहा है लेकिन केस का जो कन्विक्शन रेट है, बिहार में पूरे भारत में सबसे कम है । न्याय दलितों को नहीं मिल रहा है । एस॰सी॰/एस॰टी॰ कोर्ट खाली है, उनके पी॰पी॰ का पद खाली है जिसकी वजह से उनका कन्विक्शन रेट जीरो के लगभग 0.98 परसेंट है, एक परसेंट से भी कम है तो हम कैसे दलितों का न्याय कर पायेंगे, कैसे हम उनके साथ, हम उनको न्याय दे पायेंगे तो हम कहना चाहते हैं, दूसरा हम कहना चाहते हैं कि इसी वजह से, इसी प्रताड़ना की वजह से 14 अक्टूबर, 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोधगया महाविहार जो बी॰टी॰एम॰सी॰ एक्ट, 1949 बना वह आज भी कार्यरत है जिसके तहत उसमें चार बौद्ध लोग होंगे, चार हिन्दू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिन्दू होगा, वे उसके पदेन अध्यक्ष होंगे.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट और आपके पास है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये नौ सदस्यों में पाँच हिन्दू होंगे, चार बौद्ध होंगे, क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है । यदि यह लागू होता है, संविधान लागू हो गया तो बी॰टी॰एम॰सी॰ एक्ट को खत्म करना चाहिए और

आर्टिकल–26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उन बौद्ध भाइयों को भी मिलनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो हम इस सदन से मांग करते हैं कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाय, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाय, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाय । ये सिर्फ बोधगया महाविहार के लिए यह एक्ट क्यों काम कर रहा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार में जो भू–स्वामियों की स्थिति है उसमें 65 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है....

अध्यक्ष : सतीश जी, अब समाप्त कीजिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, थोड़ा–सा, एक मिनट में हम अपने क्षेत्र की बात, आप इजाजत दें तो रख लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार को भी बोलना है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एक मिनट हम अपनी बात को रख लें । महोदय, हम सरकार को कुछ सजेशन देना चाहते हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब नहीं, आपको पहले ही कहा था आपका समय खत्म हो रहा है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एस॰सी॰/एस॰टी॰ थाना जिला लेवल पर है, अब समय आ गया है उसको अनुमंडल लेवल पर स्थापित किया जाय....

अध्यक्ष : श्री लखेन्द्र कुमार रौशन । सतीश जी, अब समाप्त कर बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बैठिये । रौशन जी, आप बोलिये ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आज पथ निर्माण विभाग का बजट पर भुगतान का व्यय....

टर्न–24/संगीता/07.03.2025

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वैसे सतीश जी, केवल बुरा पक्ष नहीं देखना चाहिए, अच्छा पक्ष भी समाज का देखना चाहिए और आज स्थिति क्या है । आज एक बात का विचार करिए हमारे

यहां जब शादी होता है तो समाज का हर तबका उसमें शामिल होता है, कोई फूल माला लेकर आता है...

(व्यवधान)

बैठिए आप, बैठिए, सुनिए । आप बैठिए पहले, अपना स्थान ग्रहण करिए ।

(व्यवधान)

बैठिए आप । सब समाज शामिल होता है...

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : रूकिए एक मिनट । बढ़ई आता है, लोहार का काम है, माली का काम है, बांस वाले का काम है, सबका काम है और हम मरते हैं ना तो डोम से अग्नि दिलवाते हैं जो सबसे निचली जाति जिनको मानते हैं लोग, लोग जिनको मानते हैं, बिना उनके हम शुद्ध नहीं होते हैं तो समाज का अच्छा पक्ष भी जानने का कोशिश करिए, इसके बारे में बोलना चाहिए । बोलिए लखेन्द्र जी ।

(व्यवधान)

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, बिना उनके हम शुद्ध नहीं होते हैं ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के बजट और अनुपूरक बजट के प्रस्ताव के समर्थन में हम खड़े हैं लेकिन आज इस सदन के माध्यम से जिस प्रकार सदन के सदस्य के द्वारा पूरे बिहार के दलितों का अपमान किया जा रहा है, हमें लग रहा है ऐसे सदस्यों को...

अध्यक्ष : सदन अपमान नहीं कर रहा है । यह सदन अपमान नहीं कर रहा है गलत मत बोलिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : ऐसे सदस्यों को शर्म होना चाहिए ताकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी ने जो दलित समाज का अधिकार दिया, उस अधिकार की जानकारी इनको नहीं है और इस सदन में आते हैं तो केवल दलितों को गाली देने के लिए आते हैं । हम गर्व से कहते हैं सदन में कि हम दलित हैं, हम गर्व से कहते हैं सदन में कि हम अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं और जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर साहब भीम राव अंबेदकर जी ने दिया है उसी अधिकार के

आधार पर हम सदन में आए हैं । जो सदन में एक बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार के आधार पर एक महादलित की बेटियां जो सदन की मेंबर हैं, उसी आधार पर अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में सदन की, कुर्सी की शोभा बढ़ा रही हैं, यह सदन की गरिमा है, यह संविधान की देन है । यह लालू चालीसा का देन नहीं है, कुछ लोग उस समय लालू चालीसा बोल रहे थे लेकिन अध्यक्ष महोदय यह पथ निर्माण विभाग 6 हजार 8 सौ करोड़ रुपये का जो अनुपूरक मांग...

अध्यक्ष : 2 मिनट केवल आपके पास है, उसी में खत्म करिएगा आप ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : महोदय, 10 मिनट कहा गया था ।

अध्यक्ष : हां तो 3–4 मिनट हो गया भाई, 6 मिनट है ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : जो अनुपूरक मांग के समर्थन में है और ये लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं । जो अनुपूरक मांग है पथ निर्माण का उससे पूरे बिहार का विकास हो रहा है, सड़क बन रही है चकाचक और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विकसित भारत का 2047 तक का जो विजन है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का विकसित बिहार का जो विजन है उसको पथ निर्माण विभाग परंपरागत कार्यान्वयन करके इस पूरे बिहार का विकास कर रही है । हम सब लोग तो सदन समाप्त हो जाएगी, पथ निर्माण मंत्री जी के यहां जायेंगे और कहेंगे कि माननीय मंत्री जी हमारे यहां यह योजना लिख दीजिए यह सड़क कर दीजिए । सदन में आप आते हैं तो कटौती प्रस्ताव लाते हैं, पैसा आप नहीं देते हैं और सदन से बाहर जाते हैं तो मंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे यहां यह योजना को कर दीजिए, दोतरफा नीति नहीं चलेगा । सदन में जब आते हैं तो दोहरा चरित्र आपका दिखाई देता है, तीसरा चरित्र दिखाई देता है लेकिन बिहार में जो विकास हो रहा है चूंकि समय 3 मिनट का है इसमें मैं यह कहूंगा कि :

''हर्षित धरती खुशनुमा आकाश हो रहा है
दुनिया देख रही है बिहार का विकास हो रहा है
जिन्होंने कसम खाई है विरोध जताने का
अब हम सबको पता हो रहा है कि आपका नाश हो रहा है ।''

आप जाने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय, हमको याद है 7 मार्च, 2023 को हमलोग वहां थे और आज ही के दिन वहां से हम बोल रहे थे और आपके स्थान पर सभापति के रूप में बैठे हुए थे, नेता विपक्ष यहां थे, सत्ता के पक्ष में लेकिन 17 महीना के अंदर पथ निर्माण विभाग का मंत्री बनने के बाद भी तेजस्वी यादव जी ने एक काम नहीं किया और इस बिहार की सड़क को गड्ढा में तब्दील कर दिया लेकिन आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में प्रगति यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के हर जिला में जहां गए हैं, वहां सड़क की स्वीकृति अभी उन्होंने कराया है और महोदय, गांव–गांव में चकाचक सड़कें बन रही हैं । गंगा नदी पर 14 पुल का निर्माण हो गया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रतिमा जी के मंत्री का कि पूरे बिहार में जो विकास हो रहा है ये लोग अंधे हो गए हैं इनको दिखाई नहीं दे रहा है । एक अभी बोल रहे थे कि आते हैं लालू चालीसा पढ़के जायेंगे, जब घर में घुसते हैं तो लालू चालीसा को अगरबत्ती दिखा देते हैं । ये लालू चालीसा वाले लोग हैं इनको बिहार के दलितों से कोई मतलब नहीं है । ये देश के प्रधानमंत्री ने तो दलित के बेटा को राज्यपाल भी बनाया है, राष्ट्रपति भी बनाया है और यही सदन है जब दलित के बेटा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी बना रहे थे तो उस समय आरजेडी वाले आप लोग कांग्रेस और भाजपा के लोग, भाकपा के लोग, कांग्रेस और भाकपा के लोग आप सब लोग विरोध कर रहे थे और एक दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनने नहीं दे रहे थे लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने दलित के बेटा और बेटी को राज्यपाल भी बनाया और राष्ट्रपति भी बनाया, आप दलित की बात बोलते हो । आपका दोहरा चरित्र सब जान गया है । 2025 का चुनाव सामने है, वही दलित आपको खदेड़ कर बेलगा देगा और सदन में जब आते हैं तो दलितों का मजाक मत बनाइए, दलितों का अपमान मत कीजिए, लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों को लूटने का काम किया है, पिछड़ों को लूटने का काम किया है और एक परिवार में आरक्षण को संजोगने का काम किया है । बिहार में दलितों को सबसे बड़ा कोई लूटने का काम किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप, बैठिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अति पिछड़ा, मुसलमानों को लूटने का काम किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है और आप जैसे लोग दलितों का अपमान सदन में करते हैं...

(व्यवधान)

लेकिन पथ निर्माण विभाग का जो आज बजट है उस बजट...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट ठहरिए रौशन जी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए सतीश जी, बैठिए, बैठिए पहले ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कल ही माननीय सिंचाई मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो माननीय सदस्य हों या बाहर हों, उनके ऊपर कोई अभियोग लगाने के पहले आसन से सबूत देकर के स्वीकृति ले लेनी चाहिए और तब वह स्वीकृति मिले तब बोलना चाहिए...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : इसीलिए इन्होंने जो कहा लूटने का, यह बिना आपके इजाजत के हुआ है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिए उनको ।

श्री अवध विहारी चौधरी : इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि...

(व्यवधान)

उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय ।

अध्यक्ष : दिखवा लेंगे ।

(व्यवधान)

बोलिए । बैठिए आप, बैठिए न आप । बोलने दीजिए उनको, उनको बोलने दीजिए माननीय सदस्य को ।

(व्यवधान)

बैठिए तारकिशोर जी । रौशन जी बोलिए ।

(व्यवधान)

बोलने दीजिए न उनको ।

(व्यवधान)

आप बैठिए तारकिशोर जी । बोलने दीजिए माननीय सदस्य को ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : जो रामायण पर और सनातन धर्म पर आरोप लगाते हैं ऊंगली उठाते हैं, जो दलित समाज का अपमान करते हैं, जो रामचरित और गीता का अपमान करते हैं वे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अपमान करते हैं, वे व्यक्ति आज हमको सदन में क्या सिखलायेंगे इसलिए पथ निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में हम खड़ा हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक हम विकसित बिहार बनायेंगे, विकसित राष्ट्र बनायेंगे, उसमें पथ निर्माण विभाग का मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बिहार में जो सड़क बनी है वह एक चकाचक सड़क है, लालटेन युग को समाप्त कर दिया इसीलिए आज पूरे देश से 1 लाख 81 हजार इन्वेस्टर, हमारे वित्त मंत्री जी ने कल ही अपने भाषण में बताया कि पूरे देश से चकाचक सड़क के कारण, भेपर लाईट वाला बिजली के कारण, लालटेन युग समाप्ति के कारण पूरे देश के 1 लाख 81 हजार इन्वेस्टर बिहार में आकर अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं यह बिहार की एनडीए की सरकार है, यह सुशासन की सरकार है इसलिए आपको विकास नहीं दिखाई देगा और आपलोगों को तो चाहिए टीन वाला चश्मा, फूटा हुआ चश्मा पहन लेना है और मैं तो कहता हूं कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीम राब अंबेदकर जी के बाद दलितों का सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है तो उस व्यक्ति का नाम दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेन्द्र मोदी जी है, नरेन्द्र मोदी जी है...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए । एक मिनट है केवल आपके पास, केवल एक मिनट ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : और आपके पास में हिम्मत है, लालू प्रसाद यादव जी के पास में हिम्मत है, आप दलित–दलित करते हो, लालू प्रसाद यादव जी के पास में हिम्मत है तो कसम खा लीजिए अपने परिवार को मुख्यमंत्री नहीं बनायेंगे कोई दलित के बेटा को, कोई मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनायेंगे, घोषणा कर दीजिए । केवल चुनाव का समय आता है तो दलितों को ठगने का काम करते हैं इसलिए...

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

टर्न–25 / सुरज / 07.03.2025

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात कहकर मैं आपनी बात समाप्त करता हूं :

हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का...

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, एक लाईन और है

उसे कोई गिरा नहीं सकता
जो चलना ही ठोकरों से सीखा है ।

अध्यक्ष : बैठिये, धन्यवाद ।

श्री राज कुमार सिंह । 8 मिनट टाइम है राज कुमार जी आपके पास ।

श्री राज कुमार सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । मैं इस सदन का, आपका, अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार पुनः मुझे सदन में कुछ बोलने का मौका मिला है और आज जो अनुपूरक बजट आया है मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूं, अनुपूरक मांग के पक्ष में । इसके साथ ही चूंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो आज मैं अपने इस सदन की सभी 27 महिला साथी सदस्याओं का, इस सदन में जितने भी महिला कर्मी हैं उनका, पूरे राज्य एवं इस देश की समस्त माताओं–बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और खासकर विशेष तौर पर अपने मटिहानी की उन तमाम माताओं–बहनों का आभार भी व्यक्त करता हूं और शुभकामना भी देता हूं...

अध्यक्ष : राजकुमार जी, मुझे दुःख भी है कि बोलने की जब बारी आयी पथ निर्माण विभाग के बजट पर तो केवल एक महिला को बोलने का अवसर मिला, शायद वह सत्तारूढ़ दल की महिला थी । इधर से भी कोई महिला बोलती तो अच्छा लगता ।

श्री राज कुमार सिंह : मैं विशेष तौर से मटिहानी के माताओं–बहनों को भी बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा जिनकी वजह से आज मैं इस सदन में आकर बोलने के काबिल हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, अभी साथी काफी आक्रोश में थे और शायद बड़ी मायूसी भी थी और उधर का खौफ भी बहुत बड़ा है जिसकी वजह से हकीकत देखने में उनको थोड़ी परेशानी हो रही है । आपके लिये कहूंगा सतीश जी,

अध्यक्ष : राजकुमार जी, इधर देखकर बोलिये ।

श्री राज कुमार सिंह : मैं दुष्यंत की दो पंक्तियों से उनकी बात का जवाब दूंगा कि :

यह धुंध हल्का है नजर का
तू महज मायूस है
रोजनों को देख
दीवारों में दीवारें न देख ।

(व्यवधान)

रोजन का मतलब होता है खिड़की । आप दीवारों में खिड़कियों को देखो, दीवारों में दीवारों को न देखो...

अध्यक्ष : आप जिनको समझा रहे हैं, उनके समझ से परे हो गया । आगे बोलिये ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुपूरक मांग रखा गया है यह इसलिये रखा गया है क्योंकि आर0सी0डी0 के पास आज 2150 रोड हैं, 160 ऑनगोइंग प्रोजेक्टस है और जो डिस्ट्रीक्ट रोड्स हैं उसकी भी संख्या 1971 है और साथ ही साथ स्टेट हाइवे की संख्या 177 है । इन तमाम रोड्स का उन्नयन, उनका विस्तारीकरण ये सारी चीजें तीव्र गति से हो रही है और इसके लिये पैसों की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता की पूर्ति इसी सदन के माध्यम से होता है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जब यह कटौती प्रस्ताव आता है और इसका इतना विरोध ये लोग अनुपूरक मांग का करते हैं, ये तो प्रतीकात्मक होता ही है हम सब जानते हैं । एक रुपये या 10 रुपये से मांग की कटौती की जाती है ताकि विमर्श का मौका मिले और इसमें जो संशोधन हो सकता है योजनाओं के प्रति, जो आपका ख्याल है उसमें कुछ विस्तारीकरण है

तो वह होना चाहिये । अगर ऐसा ही विरोध है तो आपको पूरा का पूरा मांग को ही रख देना चाहिये कटौती में । वह आप नहीं करते हैं, वह करेंगे तो विकास की आपकी भी जो सड़कें हैं जो चमचमाती हुई दिख रही है, वह दिखेगी नहीं । मैं कुछ बातें बताऊंगा चूंकि बातें हो ही रही हैं । मैं, ये क्यों मांगा गया, 2005 और आज की स्थिति से थोड़ी सी तुलना करूंगा । 2005 तक हमारे राज्य में दो लेन के मात्र 3 ब्रिज थे । आज इन 3 ब्रिज के अतिरिक्त 3 ब्रिज और भी हैं यानी 6 ब्रिज । फोरलेन का सिर्फ 1 ब्रिज था 2005 तक और आज 1 के अलावा 7 और ब्रिज हैं फोरलेन का । सिक्स लेन का कोई ब्रिज नहीं था हमारे राज्य में आज 4 ब्रिज हैं इस राज्य में । तो यह पथ निर्माण विभाग इसलिये कार्य कर रहा है क्योंकि 2005 से आज की जो स्थितियां हैं वह काफी बदली है और यह बदलाव इसलिये हुआ है क्योंकि सरकार ने इसके लिये अपने मार्गदर्शन से, अपने दृष्टिकोण से धन भी मुहैया कराया है और वातावरण भी तैयार ऐसा किया है कि आज हमलोग एक अच्छी सड़क पर चल रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय–2 के तहत सुलभ संपर्कता के तहत 5 घंटे में राज्य के किसी भी कोने से पटना तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा है उस पर भी अभी वर्तमान में 676 करोड़ से अधिक रुपये खर्च हो रहे हैं, सड़क के निर्माण में । तो इन सब चीजों की अगर आपलोगों को आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सरकार का हौसलावर्द्धन भी करना चाहिये...

अध्यक्ष : दो मिनट और है आपके पास ।

श्री राज कुमार सिंह : मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में हमारे भी विधान सभा में एक बाईपास रोड दिया जो एन0एच0 31 से बलिया तक जायेगा । लगभग 38 किलोमीटर का वह सड़क है और 4 सौ किलोमीटर की अभी उसकी आरंभिक राशि स्वीकृत भी हुई है इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं । दो ही मिनट का समय है और महिला दिवस भी है कल और आज आपने काफी मौका भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को इम्पावर करने के लिये काफी कार्य किया है, उनके सशक्तिकरण के लिये, कहने की आवश्यकता नहीं

है । महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की प्रेरणा में एक कविता अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा

जो तुझ से लिपटी बेड़ियां समझ ले इनको वस्त्र तू
ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू
तू खुद की खोज में निकल तू किस लिये हताश है
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, दो पंक्तियां और है ।

अध्यक्ष : बोल दीजिये ।

श्री राज कुमार सिंह : चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी
ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी
तू खुद की खोज में निकल तू किस लिये हताश है
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है
चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कंपकंपायेगा
अगर तेरी चुनर गिरी तो इक भूकम्प आयेगा
तू खुद की खोज में निकल तू किस लिये हताश है
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है ।

बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव की चर्चा में करीब 15 सदस्यों ने भाग लिया । मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं । माननीय समीर कुमार महासेठ जी, सुरेन्द्र राम जी, मिथिलेश जी, ऋषि जी, ललित नारायण जी, राजेश जी, श्रेयसी जी, गोपाल जी, अनिल जी, सत्येन्द्र जी, सूर्यकांत जी, अखतरूल ईमान साहब, सतीश जी, लखेन्द्र जी एवं राज कुमार जी ।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस बजट पर चर्चा हो रही थी मुझे लगा कि पथ निर्माण विभाग की दृष्टि से अपने माननीय विपक्ष के साथियों ने जब कटौती

प्रस्ताव लाया तो साथ ही साथ कुछ सुझाव और कुछ योजनाओं की भी चर्चा करते...

अध्यक्ष : आपको निराश नहीं होना चाहिये इससे । यह इस बात का प्रमाण है कि पथ निर्माण विभाग के काम से संतुष्ट हैं सारे लोग इसलिये आपकी चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति यात्रा के माध्यम से पूरे राज्य के हर जिले में जाकर पथ निर्माण के साथ–साथ विभिन्न विभागों का जो योजनाओं का कार्यान्वयन का रूप दिया गया है।

(क्रमशः)

टर्न–26 / राहुल / 07.03.2025

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : (क्रमशः) उसमें एक बड़ा भार पथ निर्माण विभाग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी है । मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था कि हम 5 घंटे में कैसे पटना राजधानी पहुंचे, राज्य के किसी भी कोने से तो उस पर लगातार विभाग ने काम किया और आज वह दिन आ गया है जब इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक या अगले वर्ष के तीन–चार महीने के अंदर हम पांच घंटे के लक्ष्य को इसी वर्ष पूरा करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को है लेकिन यही तक हम लोग रूकने वाले नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया है कि सड़कों के क्षेत्र में अगर विकास करना है, बिहार को विकास के मॉडल पर 2047 तक विकसित बिहार बनाना है, नरेन्द्र मोदी जी के सपने को जो 2047 तक विकसित भारत का है तो सड़क एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा और इसी के लिए उन्होंने बिहार की सड़कों के लक्ष्य को और आगे किया है और 4 घंटे के लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को सौंपा है । हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस सदन को आश्वस्त करते हैं कि जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए विभाग पूरी तत्परता से काम करेगा । पथ निर्माण विभाग को प्रगति यात्रा के माध्यम से करीब 137 योजनाओं को स्वीकृति मिली और करीब 23375 करोड़ की

योजनाएं प्रगति यात्रा के माध्यम से स्वीकृत हुई हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ–साथ समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं की शुरुआत अगले तीन महीने के अंदर हम लोग करने की योजना बना रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जब यह बात आती है कि चार घंटे के लक्ष्य को आप लोग कैसे पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका भी रोडमैप पथ निर्माण विभाग ने बनाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंडा दिया है, अपनी कल्पना को दिया है तो निश्चित रूप से रोडमैप के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं । अभी करीब 5000 किलोमीटर की दो लेन की सड़कें हैं और इसको अधिक चौड़ा करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं और दो लेन से फोर लेन की सड़कों को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जी की योजना के साथ–साथ मुख्यमंत्री पथ विस्तारीकरण योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं । साथ ही साथ, आने वाले समय में राज्य योजना की जो बड़ी राशि खर्च होती है उसमें एक बड़ा कंपोनेंट हम लोग ए0डी0बी0 के तहत भी लेते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के तहत राशि लेना शुरू करवाया और आज पथ निर्माण विभाग हर दो–तीन सालों में एक बड़ी राशि इसपर खर्च करता है जिसमें ए0डी0बी0 के तहत हम सहयोग लेते हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि दो लेन की चौड़ीकरण की जिन सड़कों को ले रहे हैं वह बी0एस0एच0पी0 योजना, बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट के तहत ए0डी0बी0 के तहत करीब 225 किलोमीटर की 2900 करोड़ की योजना इसी वर्ष स्वीकृत हो रही है जो अपने आप में 5 बड़ी योजनाओं की सौगात मिलेगी । साथ ही साथ, इसके फेज–2 जो है, फेज–2 के अंतर्गत भी 493 किलोमीटर की योजना जो 6287 करोड़ की है इसको भी अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिल जायेगी । इससे सड़कों के क्षेत्र में जहां पहले भी ए0डी0बी0 का सहयोग लेकर हम लोगों ने काम किया है लेकिन राज्य योजना के बाद प्रगति यात्रा के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सात निश्चय की कल्पना को रखा वह अपने आप में एक बड़ी योजना है चूंकि कई बात हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम पटना आते हैं या राज्य के, जिले के मुख्यालय में जाते हैं तो हमको तकलीफ होती है मुख्यालय के केन्द्र में पहुंचने के लिए ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से चार साल पहले ही पथ निर्माण विभाग को इसकी सहमति दी थी और सुलभ संपर्कता पथ जो सात निश्चय पार्ट–2 की योजना थी उसके तहत पहले भी करीब दर्जनों बाईपास को कंप्लीट किया गया और इस बार भी प्रगति यात्रा के माध्यम से करीब 23 बाईपास को स्वीकृति मिली है जिससे शहरों के अंदर घुसने में और शहर से बाहर निकलने में बहुत बड़ा अंतर आयेगा और मुझे लगता है कि जो हम लोग कह रहे थे कि कैसे हम दूरी को कम करें इसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर सुलभ संकर्पता पथ होगा जिसकी 2000 करोड़ की योजनाओं से शुरूआत हो रही है । प्रगति यात्रा के माध्यम से जहां एक ओर कुल 137 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं लेकिन इसके अलावा भी जो यह बात आती है कि पटना पहुंचने के लिए भी, कई माननीय सदस्यों ने इस पर सवाल किया और कुछ लोगों ने सुझाव दिये तो मुझे यह बताते हुए खुशी है कि शहर के अंदर जो जे0पी0–गंगा पथ है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दीघा से दीदारगंज की एक योजना, अध्यक्ष जी आप उस समय मंत्री भी थे, उस कल्पना की शुरुआत की थी । तीन फेज की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को सुपुर्द कर दी है लेकिन चौथा फेज जो बहुत ही इंपोर्टेंट होने जा रहा है वह है दीघा से दीदारगंज की कनेक्टिविटी का और यह पूरी योजना इसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पूर्ण हो जायेगी । एक बहुत बड़ा तोहफा बिहार के लोगों को है, इसका एक बड़ा लाभ अगर आप समझ सकते हैं, पूरे सदन के लोग कि आज उत्तर बिहार से जब हम जे0पी0–गंगा पथ से आयेंगे तो कहीं न कहीं पूरी तरह से हम जो दक्षिणी पटना का इलाका जो हमारा बेगूसराय, मुंगेर है, इस इलाके में जो दीदारगंज से आयेंगे उसको सिक्स लेन से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है यानी कच्ची दरगाह, बिदुपुर भी इस जे0पी0–गंगा पथ से कनेक्ट होने जा रहा है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही नहीं किया है इसके अलावा कई और योजना को जो सरकार की प्रगति यात्रा में हुआ है इस जे0पी0–गंगा पथ को कोईलवर तक भी कनेक्ट कर रहे हैं और इधर मोकामा तक भी कनेक्ट करने की करीब 6000 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली है। इसके लिए भी मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । नौबतपुर के जाम की बात आयी थी तो मुझे बताते हुए खुशी है कि नौबतपुर

लख पर 73 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है और यह योजना भी इसी प्रगति यात्रा का पार्ट है । जहां तक कई बार माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे एन0एच0 के विषय पर लोग चर्चा करते हैं मैं तो कहूंगा माननीय सदस्यगण, आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि 2005 के पहले की मैं चर्चा भी नहीं करूंगा लेकिन कुछ आंकड़े जरूर आपको जानने चाहिए कि केन्द्र सरकार ने किस प्रकार से पूरी तरह से बिहार सरकार को हर चीज में, सड़क के क्षेत्र में बहुत बड़ी मदद दी है । लोग पैकेज की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 54 हजार करोड़ की योजनाओं की सड़क के क्षेत्र घोषणा की थी । मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि अभी तक मात्र 10 साल होने जा रहे हैं दो लाख अड़तालीस हजार करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है, केवल केन्द्र की योजनाओं से और मैं ये आंकड़े आज आपके सामने लेकर आया हूं । हमारे साथी कई बार बोलते हैं, पूरे इतिहास की चर्चा कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को पथ निर्माण मंत्री रहते हुए भी इस विषय का वक्तव्य दिया होगा लेकिन मैं पूछता हूं दो लाख अड़तालीस हजार करोड़ में तो पूरी एन0एच0 की योजनाएं हैं, आपने अपने खुद के, जब आप मंत्री थे तो आपने भी पटल पर जो रखा था वे भी यही आंकड़े थे आप अपने ही आंकड़ों को सही नहीं बता पा रहे हैं यह एक दुर्भाग्य आपके साथ है लेकिन मैं इसके डीटेल में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो एक विषय उठता है कि हमारे यहां टू लेन, फोर लेन जो माननीय सदस्य बोल भी रहे हैं, मैं आपको यह आंकड़े बताता हूं । तीन हजार किलोमीटर की सड़कें थी 2005 में और आज छः हजार किलोमीटर की एन0एच0 की सड़कें हैं लेकिन इससे बड़ा जो आंकड़ा है जो इनको समझने की जरूरत है कि उस समय सिंगल लेन और टू लेन की सड़कें होती थी एन0एच0 की और आज छः हजार किलोमीटर में से तीन हजार किलोमीटर फोर लेन की सड़कें हैं । हम किलोमीटर में ही नहीं बढ़े हैं हमने चौड़ाई जो टू लेन और फोर लेन की सड़कें होती हैं, सिक्स लेन की सड़कें होती हैं वह बिहार को तोहफा मिला । इसके साथ–साथ केन्द्र की योजना से जो एक्सप्रेस वे मिला है । मैं एक्सप्रेस वे की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, तीन बड़े एक्सप्रेस वे जो अपने आप में लाईफ लाईन बनने जा रहे हैं उत्तर बिहार के

लिए जो सबसे इंपोर्टेंट है गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, पटना–पूर्णिया एक्सप्रेस वे और फोरलेन ग्रीनफील्ड मोकामा टू मुंगेर के लिए इसमें करीब 50 हजार करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है और यह नये बिहार की जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2047 का विकसित बिहार बनाना चाहते हैं उसमें ये तीनों योजनाएं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी चूंकि आप समझ सकते हैं कि जो बाढ़ प्रौण इलाका हमारा रहा है उन प्रौण इलाकों में से यह गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे जायेगा जिससे उस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए विकास का हब बनेगा । मैं साथ ही साथ, जो अभी टू लेन और फोर लेन की बात आयी, इसके साथ–साथ कई एक्सप्रेस वे का गिफ्ट हमारी सरकार को मिला है । मैं इसके लिए केन्द्र में अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि लगातार केन्द्र ने एन0एच0 की योजनाओं में हम लोगों को सहयोग दिया है । अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड की योजनाओं की चर्चा हो रही थी...

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय,...

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : सी0आर0आई0एफ0 की योजनाओं की चर्चा हो रही थी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा...

(व्यवधान)

आज राज्य उच्च पथ की बात होती है । केवल नाबार्ड में एक हजार करोड़ की योजना की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में मिली है जो अपने आप में बड़ी योजना है...

(व्यवधान)

जिसके माध्यम से हम सड़क के प्रक्षेत्र में काम कर रहे हैं । सी0आर0आई0एफ0 में करीब 600 करोड़ की योजना की केन्द्र से स्वीकृति मिली है जो हम लोग राज्य के पथों के लिए लेने जा रहे हैं...

(व्यवधान)

एक विषय जो हमेशा आता है, हमारे कई सदस्य इस पर बात करते हैं कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो ए0डी0बी0 के तहत हो रही थी । आपको मैं

बताना चाहूंगा कि नाबार्ड के अलावा ए0डी0बी0 की योजनाएं भी पूरी तरह इसी वर्ष हम लोग स्वीकृत करने जा रहे हैं और...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

एक विषय जो हमारे सदस्य कहते हैं ब्रिज मेंटिनेंस पॉलिसी । अध्यक्ष महोदय, ब्रिज मेंटिनेंस पॉलिसी के तहत भी एक पूरी जानकारी देना चाह रहा हूं ।

(क्रमशः)

टर्न–27 / मुकुल / 07.03.2025

क्रमशः

श्री नितिन नवीन, मंत्री : यह जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी है । अध्यक्ष महोदय, मुझे सौभाग्य मिला है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, पहले भी मैंने दो बार पथ निर्माण विभाग का बजट रखा था । उस समय भी ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पर काम शुरू हुआ था और मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी अब फाइनल स्टेज में है और इसी अगले वित्तीय वर्ष से हम इस पॉलिसी को लाने जा रहे हैं । ओ0पी0आर0एम0सी0 के तहत हमारी जो ब्रिज मेंटेनेंस की जो स्कीम है, जो हमलोग सड़कों को मेंटेन करने के लिए करते थे, मुझे बताते हुए खुशी है कि केन्द्र सरकार ने भी परफोर्मेंस बेस मेंटेनेंस कान्ट्रेक्ट और शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कान्ट्रेक्ट जो बिहार का मॉडल था ओ0पी0आर0एम0सी0 का, उस मॉडल को एक्सेप्ट किया और आज देश में भी, अभी जो रायपुर में जो पूरी रोड कांग्रेस की जो बैठक हुई । उसमें रोडों के मेंटेनेंस के लिए केन्द्र सरकार ने भी उस पॉलिसी को एडॉप्ट किया है और साथ ही साथ ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी जिस पर दो साल, तीन साल पहले इस विभाग ने इस पर काम शुरू किया था, आज रोड कांग्रेस ने इसको भी सहमति दी है और बिहार राज्य पुल प्रबंधन संधारण नीति–2025, जिसमें ब्रिज हैल्थ इंडेक्स बनाने की योजना, उसके जो कम्पोनेंट हैं जो बड़ी–बड़ी बातें ब्रिज के विषय पर लोग करते हैं, समय उनको भी मिला था क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा पाये । ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी अब फाइनल स्टेज में है । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय

कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद दूंगा कि इस पॉलिसी को लेकर आपने जो वर्कआउट किया अब वह फाइनल स्टेज में है और इस पूरे पॉलिसी में जहां ब्रिज हेल्थ कार्ड, ब्रिज इंडेक्स, टाइप ऑफ ब्रिज एलोकेशन, ब्रिज हेल्थ स्टार रेटिंग इस तरह से 6 कम्पोनेंट हैं जो कि आई0आर0सी0 कोड जो मेंटेनेंस का इंडियन रोड कांग्रेस ने दिया है, उस कोड के तहत हमलोग इसको बनाकर ला रहे हैं और बहुत जल्द सदन के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से इसकी सहमति मिलेगी और यह पॉलिसी पूरे राज्य में करीब 10 हजार ब्रिजेज पुल निर्माण निगम ने बनाये हैं, उन सभी ब्रिज का हमलोगों ने रिपोर्ट मंगाई है और अभी तक जितने क्षतिग्रस्त ब्रिज थे, उन सब पर हमलोगों ने काम शुरू कर दिया है और इस पॉलिसी के बाद हम निश्चित रूप से ब्रिज के पूरे हेल्थ कार्ड बनाकर कहीं न कहीं राज्य की जनता को ब्रिज को लेकर कोई चिंता न हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग काम करेंगे । साथ ही साथ, आज एक विषय आ रहा था कि 2025 में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमलोगों ने इस वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं हुई हैं और पिछले समय में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको 2025–26 में हमलोग कम्प्लीट करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में जो काम हुआ है सड़क के क्षेत्र में उनमें कई योजनाओं का सौगात अगले वित्तीय वर्ष में मिलने जा रहा है । अप्रैल महीन में जे0पी0 गंगा पथ, जिसकी मैंने चर्चा की उसका उद्‌घाटन हो सकता है जो कम्प्लीशन के फेज में है । 6–लेन गंगा पुल परियोजना सबलपुर से राघोपुर का अंश है अप्रैल में हमलोग समाप्त करेंगे, महनार से सिकंदरा का मई में समाप्त करेंगे, राघोपुर से महनार अंश को भी हमलोग नवंबर में समाप्त करने जा रहे हैं, मीठापुर–महुली जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कराई थी उसका फर्स्ट फेज सिपारा से महुली हम अप्रैल महीने में देने जा रहे हैं । साथ ही साथ, मीठापुर–सिपारा–महुली के अन्य फेजों को भी हमलोग सितम्बर माह के पहले तक पूर्ण करने जा रहे हैं । बैसी–बहादुरगंज अंश यह भी अप्रैल महीने में हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं, बख्तियारपुर–ताजपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही लम्बा समय से ड्रीम रहा था कि इस योजना को कम्प्लीट किया

जाये, मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक फेज चकलाशाही से ताजपुर सम्पर्कता अप्रैल में हमलोग समाप्त करेंगे और डुमरी से चकलाशाही सम्पर्कता सितम्बर महीने तक समाप्त करेंगे । इसके अलावा जो ए0डी0बी0 की पुरानी योजनाएं थीं उसको भी बेतिया, नरकटियागंज, फॉलगो हॉल्ट, सिमरी और फतेहपुर–गोविंदपुर का भी हमलोग इसी वर्ष मतलब अप्रैल, अगस्त के बीच में समाप्त करेंगे । एक डबल डेकर ब्रिज जो पटना में बन रहा है, मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और अगले महीने उसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं, कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर सकते हैं । साथ ही साथ, एन0एच0 की कई योजनाएं जो समय से चल रहा था वे भी अगले वित्तीय वर्ष में समाप्त होने वाले हैं, जिसमें औटा से सिमरिया मई महीने में समाप्त होने वाला है, बख्तियारपुर, मोकामा भी कम्प्लीशन के फेज में है वह भी मई महीने में समाप्त हो रहा है । गोपालगंज शहर का जो फोरलेन एलीवेटेड मिला है वह भी 31 मई तक समाप्त हो जायेगा, एन0एच0 पटना, गया, डोभी, मंझौली, चरौत, पथांश, सरिस्तावाद का नथुपुर, वाराणसी–औरंगाबाद 6–लेन ब्रिज ये सारी योजनाएं जून तक पूर्ण हो जायेंगी, अध्यक्ष महोदय यह मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं । साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमलोगों ने विभाग की दृष्टि से कुछ और भी योजनाओं को हमलोगों ने अपने साथ जोड़ा है । मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चीज के लिए आभार देना चाहूंगा कि कोई भी योजनाएं होती हैं उनको करने वाला अभियंता का टीम होता है और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जो लंबे समय से अभियंताओं की कमी विभाग झेल रहा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभाग और अपने मुख्य सचिव और माननीय हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने लगातार प्रयास किया और करीब 6 हजार कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा हुआ यह अपने आप में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इससे हम बेहतर काम की गुणवत्ता के साथ दे पायेंगे, जिसमें करीब 500 कनीय अभियंता पथ निर्माण विभाग को मिले हैं इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही साथ, अब मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमलोग करना चाह रहे हैं, एक

बहुत बड़ा काम जब मैं पूर्व में आपलोग के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम किया था तो ओ0पी0आर0एम0सी0 को मेंटेनेंस के लिए हमलोगों ने रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे हो, उस समय हमलोगों ने कंट्रोल एण्ड कमांड रूम के माध्यम से उसकी शुरुआत की थी और वह मॉडल कहीं न कहीं बहुत अच्छा बना और बाद में इसको कई राज्यों ने एक्सेप्ट किया । आज मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लंग्वेज के तकनीक का प्रयोग करने जा रहे हैं जो रोड की मॉनिटरिंग सिस्टम में बहुत बड़ा मिल का पत्थर होगा और मुझे लगता है कि यह आने वाले समय के लिए एक नया टेक्नोलॉजी के साथ हम रोड के संधारीकरण को देख पायेंगे । साथ ही साथ, एक दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति जो सड़कों के क्षेत्र में ओ0पी0आर0एम0सी0 के माध्यम से थी इसमें तीन फेज का काम रुका हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी और सबकी सहमति होने के बाद हमलोगों ने मुजफ्फरपुर, बांका और गया, शेरघाटी को भी अगले वित्तीय वर्ष में सड़क संधारण के लिए हमलोग लेने जा रहे हैं । साथ ही साथ, जे0पी0 गंगा पथ जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बहुत बड़ा पूरे पटना के लिए टूरिस्ट नहीं पूरे बिहार के लिए, लोग जब इस बार छठ पर आये थे तो हर लोग जे0पी0 गंगा पथ जाना चाहता था, मेरे भी परिवार के सदस्य हों या बाहर के जितने मित्र आयें तो जे0पी0 गंगा पथ को कैसे और एक बड़ा, बेहतर हब क्रिएट किया जाये जिसमें ईको टूरिज्म नजर आये, इकोनॉमिक हो, हाट हो तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जे0पी0 गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना पर काम हो रहा है जो दीघा से लेकर करीब 8 किलोमीटर के पैच को फर्स्ट फेज में लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विषय जो आता है, आज देशभर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और नये–नये तकनीक से भी काम हो रहे हैं तो जहां एक तकनीकी की बात है, वहीं रेवेन्यू की बात है, आज पूरे देश में हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल बहुत सफल हुआ है और हमलोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में हम विभाग के माध्यम से उसकी समीक्षा कर रहे हैं और हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल से भी बिहार की सड़कों को लेंगे जो केन्द्र सरकार ने कई जगहों पर किया है और उसका सफल प्रयोग नजर आ रहा है और बिहार में भी अपने रेवेन्यू के जो कन्सर्न हैं

उसको देखते हुए हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल के माध्यम से हम नयी सड़कों को लेंगे जो अपने आप में बिहार के लिए झलक होगा । साथ ही साथ, रिंग रोड एक अपने आप में बड़ी कल्पना होती है, अगर हम शहरों के विकास के लिए सोचते हैं, पहले पटना रिंग रोड पर भी काम चल रहा है उसका एक फेज अभी भी बचा हुआ है । साथ ही साथ, 4 रिंग रोड पहले भी हमलोगों ने प्रस्ताव किया था, अब 2 और रिंग रोड बेगूसराय, कटिहार पर भी बिहार सरकार काम कर रही है तो अब गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय और कटिहार ये 6 रिंग रोड पर भी विभाग काम कर रहा है और आने वाले समय में इसकी सहमति मिलने के बाद हमलोग केन्द्र सरकार के पास जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि हमारे साथी कई बात बोल गये लेकिन मुझे लगता है कि सड़क के क्षेत्र में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 के बाद एक कल्पना दी और आज पूरे आपके नेतृत्व में भी, आप भी उस समय मंत्री रहे जिस प्रकार से बिहार का पहली झलक ही सड़क बना और बिहार की पहचान को बदलने में कोई अगर सबसे इम्पोर्टेंट कारगर हुआ तो सड़क और लॉ एण्ड ऑर्डर और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों ही विषयों पर हमलोग आज भी 20 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज भी उसमें अपना एक अलग स्थान बनाते जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आज इस पूरे विषय पर मेरे साथी लोग कई तरह की बात कर रहे थे, उसमें कई योजनाएं की चर्चा की है मेरा यह मानना है कि उन योजनाओं को अगर प्रगति यात्रा के माध्यम से वह मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते तो मुझे खुशी होती कि आज मुख्यमंत्री जी ने करीब 23 हजार करोड़ रुपये से ऊपर की योजनाओं का सौगात दिया और

क्रमशः

टर्न–28 / यानपति / 07.03.2025

(क्रमशः)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, मैं तो उसके लिए अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि आज योजनाओं के माध्यम से जो पूरा विषय, लोग कहते थे कि बिहार में पैसों की कमी है, मेरा मानना है कि इच्छा की कमी थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको करके दिखाया । इच्छा होती है तो रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं ।

जो हमारे साथी कल बड़ा–बड़ा भाषण दे रहे थे, पूरे इतिहास की चर्चा कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष तो आज पूरे दिन ही सदन में नहीं रहे । मुझको लगता है कि उनको, एक लाइन के लिए मैं बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

''अंधा चकाचौंध का मारा है, क्या जाने इतिहास बेचारा

साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, भूगोल, खगोल

कलम उनकी जय बोलेगा, बिहार उनकी जय बोलेगा ।

न्याय के साथ जिन्होंने विकास दिया, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया निश्चित रूप से बिहार भी उनकी जय बोलेगा और मैं आपके माध्यम से अपने अनुदान मांग को पूरा करने के लिए, कटौती मूवर तो......

अध्यक्ष : आप चाहें तो और अपनी बात रख सकते हैं ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो विषय, एक विषय आता है, जो पुल के विषय को लोगों ने लगातार किया मैं स्पष्ट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं होती हैं उसकी गुणवत्ता पर कोई कंपरमाइज नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति हो वह बख्शा नहीं जायेगा और हमलोगों ने पहले भी यह करके दिखाया है । पथ निर्माण विभाग हमेशा एक मॉडल दिया है कि हम किसी भी योजना को गुणवत्ता के साथ करते हैं, अगर इसमें कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसको बख्शा नहीं जायेगा । नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर निश्चित रूप से आगे भी हमलोग काम करेंगे और विभाग उसके लिए कमिटेड है कि हम किसी भी इस तरह के केसेज को, इस तरह की किसी भी चीज को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर रखेंगे और ऐसी किसी भी चीज को होने नहीं देंगे । साथ ही साथ, मैं यह भी आपको सदन के माध्यम से कहूंगा अध्यक्ष महोदय, लोगों ने हमेशा कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से समाज के आईने को बनाकर लोग केवल चंद वोट बैंक की खातिर राजनीति करने का प्रयास करते हैं, अगर आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम पर चर्चा करते तो वह कहीं ठहर नहीं पाते इसलिए मुझे लगा कि आज उन्होंने कोई भी काम की चर्चा नहीं की, केवल राजनीति की चर्चा की, यही आज दुर्भाग्य है । मैं आपके

माध्यम से अध्यक्ष जी पथ निर्माण विभाग के अनुपूरक मांग को पूरा करने का आग्रह करता हूं । कटौती प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भी आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : आपको तो कहना चाहिए था माननीय मंत्री जी,

''कभी शहर से तो होकर गुजर,
क्यों रास्तों के जाल में उलझा है ।''

आपने कहा ही नहीं उनलोगों को । वैसे मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भी कुछ कहना चाहता हूं, मैं कभी आपको देखता था पहले, अब आपकी बनाई गई सड़कों को देखता हूं । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो नजर और देखनेवालों की बात हो रही थी, हमारी तो नजर बस आप पर थी कि आप जिधर देख रहे थे सब उधर देख रहे थे हम तो बस देखने वालों की नजर देख रहे थे ।

अध्यक्ष : विजय बाबू, कठिनाई हमारी क्या है, मैं जब इधर बैठता था तो पक्ष में शेरो–शायरी करता था, जब उधर बैठता था तो विपक्ष में शेरो–शायरी करता था अब यहां निष्पक्ष की कुर्सी पर बैठा हूं, कितना शेरो–शायरी करूं !

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शीर्षक के मुख्य शीर्ष–3054, उप मुख्य शीर्ष 80 के लिए 23,43,23,71,000 रुपये की मांग 5,00,00,000 रुपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 6806,53,49,000/– (छः हजार आठ सौ छः करोड़ तिरेपन लाख उनचास हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–07 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–37 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक–10 मार्च, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।